असंशोधित

बिहार विधान-सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

17 मार्च, 2023

सप्तदश विधान सभा — शुक्रवार, तिथि 17 मार्च, 2023 ई0

अष्टम सत्र — 26 फाल्गुन, 1944 (शक)

(कार्यवाही प्रारंभ होने का समय- 11.00 बजे पूर्वाह्न)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्षः सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है । अब प्रश्नोत्तर काल होगा । अल्पसूचित प्रश्न लिये जाएंगे ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दलः अध्यक्ष महोदय, बहुत महत्वपूर्ण सूचना है, महोदय, मुजफ्फरपुर कांटी थाना अंतर्गत राहुल साहनी जिसकी हत्या हुई और उसके संदर्भ में इसी सदन में माननीय मुख्यमंत्री जी ने सारे कागजात लिए और आज उसकी माता मंजू देवी थाना में बैठी हुई हैं, आवेदन दिया है । रात में उनके घर पर धमकी दिया है कि बेटा की हत्या की, अब दामाद की हत्या करेंगे और सरकार के मंत्री इसराईल मंसूरी के लोगों के द्वारा धमकी दी गई, माननीय मुख्यमंत्री जी इसका जवाब दें कि आपने कागजात लिया और सरकार में बैठे अपराधी छवि के मंत्री धमकी दे रहे हैं उनके दामाद को भी मारने की, कहां जाएंगे, माननीय सरकार बैठे हैं जवाब दें क्या हुआ उस कागज के लेने का, उसपर एफ0आई0आर0 हुआ, मंत्री को हटाने की बात हो ।

अध्यक्षः माननीय नेता प्रतिपक्ष, अब आसन ग्रहण करें ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दलः नहीं महोदय, जवाब दें यह इंपोर्टेंट है ।

अध्यक्षः जवाब तुरंत नहीं न मिलता है ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दलः महोदय, यह संगीन मामला है ।

अध्यक्षः अब आप स्थान ग्रहण करें । माननीय सदस्य श्री मुकेश कुमार रौशन ।

(व्यवधान)

आपने अपनी बात को रख दिया और आप क्या चाहते हैं कि रख दिए सवाल और जवाब आपको तुरंत मिल जाएगा, ऐसा होता है क्या ? आपने पढ़ दिया, सुना दिया, सदन के सामने आपने रखा ।

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण वेल में आ गए)

(व्यवधान जारी)

आपने तो पढ़ा ।

(व्यवधान जारी)

सरकार सुन रही है । श्री मुकेश कुमार रौशन । माननीय मंत्री स्वास्थ्य विभाग ।

प्रश्नोत्तर काल

अल्पसूचित प्रश्न सं0–55 (श्री मुकेश कुमार रौशन, क्षेत्र सं0–126, महुआ)

(व्यवधान जारी)

अध्यक्षः उचित समय पर आपका जवाब दिया जाएगा लेकिन आप स्थान ग्रहण करें । आप स्थान ग्रहण करें माननीय सदस्यगण । माननीय मंत्री स्वास्थ्य विभाग ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, उप मुख्यमंत्रीः अध्यक्ष महोदय, स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि राज्य के राजकीय दंत महाविद्यालय अस्पतालों में दंत चिकित्सक शिक्षकों की नियमित नियुक्ति के निमित्त बिहार दंत शिक्षा सेवा संवर्ग नियमावली एवं बिहार दंत शिक्षा सेवा ट्विटर नियमावली के गठन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है ।

अध्यक्षः माननीय सदस्य श्री मुकेश कुमार रौशन जी ।

श्री मुकेश कुमार रौशनः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उप मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि जल्द नियमावली बना ली जाय ताकि जो 12 वर्षों से अनुबंध पर दंत चिकित्सक शिक्षक कार्य कर रहे हैं उनको कम से कम इसमें फायदा मिले महोदय और जो दंत चिकित्सक हैं काफी आशा है माननीय उप मुख्यमंत्री जी से कि कम से कम उनलोगों को स्थायी नौकरी मिल जाय महोदय ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, उप मुख्यमंत्रीः महोदय, प्रोसेस में है, प्रक्रियाधीन है । दोनों पॉलिसी जो है प्रक्रियाधीन है ।

श्री मुकेश कुमार रौशनः धन्यवाद ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्षः माननीय सदस्य श्री अजय कुमार सिंह । उत्तर मुद्रित है । आप पूरक पूछें ।

अल्पसूचित प्रश्न सं0–56 (श्री अजय कुमार सिंह, क्षेत्र सं0–166, जमालपुर)

(लिखित उत्तर)

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्रीः वस्तुस्थिति यह है कि योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु सरकारी/लोक भूमि की उपलब्धता एक अनिवार्य शर्त है । अतः भूमि उपलब्धता संबंधी प्रतिवेदन प्राप्त होने पर ही माननीय सदस्य, बिहार विधान मंडल द्वारा अनुशंसित योजनाएं क्रियान्वित की जाती हैं ।

अनुशंसित योजना की प्रशासनिक स्वीकृति एवं क्रियान्वयन हेतु मार्गदर्शिका में वर्णित प्रावधानों के अनुपालन हेतु भूमि उपलब्धता संबंधी प्रतिवेदन/अनापत्ति प्रमाण पत्र ससमय उपलब्ध कराने हेतु सभी अंचलाधिकारी एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी को निदेशित करने एवं जिलास्तरीय समन्वय समिति की बैठक में नियमित रूप से इस बिन्दु की समीक्षा एवं अनुश्रवण करने का निदेश सभी जिला पदाधिकारियों को विभागीय पत्रांक–4792, दिनांक–7 नवम्बर, 2019,

पत्रांक-5703, दिनांक-31 दिसम्बर, 2019 एवं पत्रांक-886, दिनांक-14 फरवरी, 2023 द्वारा दिया गया है ।

स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, बिहार के सभी कार्य प्रमंडलों में क्रियान्वित योजनाओं का अनुश्रवण नियमित रूप से मुख्य अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, मुख्यालय तथा विभाग के क्षेत्रीय पदाधिकारियों के द्वारा किया जाता है ।

उल्लेखनीय है कि बिहार विकास मिशन द्वारा अपूर्ण योजना के अनुश्रवण हेतु असैनिक कार्य सूचकांक के माध्यम से सभी कार्य विभागों के स्तर पर अपूर्ण योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की जाती है ।

श्री अजय कुमार सिंह: माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री ने कहा है कि भूमि उपलब्धता संबंधित प्रतिवेदन.....

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष: आप स्थान ग्रहण करें ।

श्री अजय कुमार सिंह: अनापत्ति प्रमाण पत्र ससमय उपलब्ध कराने हेतु आदेश निर्गत है तो मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि ससमय इसकी समय सीमा क्या निर्धारित है ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष: आप स्थान ग्रहण करें, नेता प्रतिपक्ष ने तो अपनी बात को रख दिया है । प्रश्नकाल होने दीजिए ।

श्री अजय कुमार सिंह: दूसरा पूरक है महोदय क्या माननीय मंत्री जी.....

अध्यक्ष: माननीय सदस्य आप पूरक पूछें । उत्तर मुद्रित है ।

श्री अजय कुमार सिंह: महोदय, पूरक ही तो पूछ रहे हैं ।

अध्यक्ष: पूछा जाय ।

श्री अजय कुमार सिंह: मैंने कहा कि माननीय मंत्री जी ने कहा है कि भूमि उपलब्धता संबंधी प्रतिवेदन अनापत्ति प्रमाण पत्र.....

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष: आप पोस्टर लीजिए । पोस्टर ले लीजिए ।

श्री अजय कुमार सिंह: ससमय उपलब्ध कराने हेतु आदेश निर्गत है तो मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि ससमय की समय सीमा क्या है ?

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष: आप पोस्टर न दिखाएं, पोस्टर दे दीजिए ।

श्री अजय कुमार सिंह: दूसरा पूरक है महोदय, क्या माननीय मंत्री जी केवल वित्तीय वर्ष 2022-23 का ही आंकड़ा बताएंगे कि 318 विधान सभा और विधान परिषद् क्षेत्रों

में विधान मंडल के माननीय सदस्यों द्वारा कब-कब अनुशंसा की गई और उसका भूमि उपलब्धता प्रतिवेदन, अनापत्ति प्रमाण पत्र कब-कब उपलब्ध कराया गया है ।

अध्यक्ष: माननीय मंत्री, योजना एवं विकास विभाग ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव: महोदय, जो प्रश्न है उसका समुचित उत्तर दिया जा चुका है, उसके अतिरिक्त उसमें पूरा डीटेल मांग रहे हैं तो अलग से करें वह उनको दिया जाएगा ।

अध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय मंत्री जी ने उत्तर दे दिया है, अगर अन्य कुछ जानना चाहते हैं तो आप लिखित दे दीजिए इनको ।

श्री अजय कुमार सिंह: महोदय, मैंने इतना ही कहा है कि जो सदस्य अनुशंसा करते हैं मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना में उसके अनापत्ति अथवा अनापत्ति के लिए समय सीमा निर्धारित की जाय । यह समय सीमा निर्धारित नहीं है ।

अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि आप विशेष जानकारी कुछ चाहते हैं तो लिखित दे दीजिए । माननीय सदस्य श्री संजय सरावगी ।

अल्पसूचित प्रश्न सं0-57 (श्री संजय सरावगी, क्षेत्र सं0-83 दरभंगा)

(प्रश्न नहीं पूछा गया)

अध्यक्ष: माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा । पूरक पूछा जाय ।

अल्पसूचित प्रश्न सं0-58 (श्री अजीत शर्मा, क्षेत्र सं0-156 भागलपुर)

(लिखित उत्तर)

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री: अध्यक्ष महोदय, इस संबंध में कोई आंकड़ा उपलब्ध नहीं है । विद्युत विपत्र में लिये जाने वाले बिजली की दर बिहार विद्युत विनियामक आयोग द्वारा स्वीकृत टैरिफ में निहित प्रावधानों के तहत निर्धारित है । वर्तमान टैरिफ में बिजली विपत्र अथवा डी0पी0एस0 के माफी का कोई प्रावधान उपलब्ध नहीं है ।

श्री अजीत शर्मा: महोदय, पूरक पूछता हूं ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष महोदय, जिस तरह से ये लोग प्रश्नकाल को बाधित करना चाहते हैं, जनता का अपमान है इस सदन का, इनपर आपको कार्रवाई करनी चाहिए ।

अध्यक्ष: मैं तो कहता हूं कि माननीय नेता प्रतिपक्ष, आप अपने माननीय सदस्यों को कहिए कि वह आसन ग्रहण करें आपने जो बात उठा दिया, वह बात सदन के सामने आया हुआ है और वह उचित समय आता है उसमें उसपर विचार किया जाएगा । तबतक सबलोग अपना स्थान ग्रहण करें ।

श्री अजीत शर्मा: अध्यक्ष महोदय, सरकार महिलाओं के लिए बहुत सारे काम कर रही है, मेरा प्रश्न था विधवा महिलाओं और बेसहारा के लिए, माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया है कि विपन्न विधवा एवं बेसहारा महिलाओं के संबंध में कोई आंकड़ा उपलब्ध

नहीं है तो मैं जानना चाहता हूं कि जातीय गणना जो हो रही है उसमें यह आंकड़ा उपलब्ध होगा तो क्या सरकार आंकड़ा उपलब्ध होने के बाद उपर्युक्त श्रेणी की महिलाओं के विद्युत विपत्र को माफ करेगी ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्रीः महोदय, इस तरह का कोई प्रस्ताव नहीं है, विद्युत विनियामक आयोग निर्णय करता है इसलिए सरकार के पास कोई विचार नहीं है ।

श्री अजीत शर्माः अध्यक्ष महोदय, दूसरा पूरक है मेरा, सरकार ने कहा है कि वर्तमान में बिजली विपत्र अथवा डी0पी0एस0 की माफी का कोई प्रावधान नहीं है तो मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या प्रश्न के आलोक में इस विषय पर सरकार विचार करेगी और क्या बिहार विद्युत विनियामक आयोग को इसपर विचार करने का निर्देश देगी और कबतक देगी ?

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्रीः महोदय, इस तरह का कोई विमर्श, इस तरह का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

श्री अजीत शर्माः अध्यक्ष महोदय, तो महिलाओं, बेसहारा जो विधवा हैं उसके लिए सरकार क्यों नहीं सोचेगी । आदरणीय मुख्यमंत्री जी तो महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, मंत्री जी को इसपर विचार करना चाहिए ।

अध्यक्षः माननीय मंत्री जी ने कहा कि इस तरह का कोई मामला अभी सामने नहीं है ।

श्री अजीत शर्माः महोदय, तो मैं आग्रह कर रहा हूं कि इसपर विचार करना चाहिए, जो विधवा हैं, बेसहारा महिला हैं ।

अध्यक्षः आपने आग्रह कर दिया, अब अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए ।

(व्यवधान जारी)

माननीय सदस्य, श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह ।

अल्पसूचित प्रश्न सं0-59 (श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह, क्षेत्र सं0-221 नवीनगर)

(लिखित उत्तर)

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्रीः (1) स्वीकारात्मक ।

(2) चूंकि वितरण कंपनी द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में ग्रामीण क्षेत्रों में औसतन 22 घंटे बिजली की आपूर्ति की गई । अतः उपरोक्त प्रावधान के तहत फिक्स्ड चार्ज में कोई छूट नहीं दी जा सकती है । (प्रति संलग्न)

(3) लागू नहीं ।

अध्यक्ष : आप पूरक पूछिए ।

श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंहः अध्यक्ष महोदय, जवाब मुझे मिल गया है लेकिन जो जवाब विभाग के द्वारा दिया गया है । वर्ष 2021-22 में ये लोग कहते हैं कि 22 घंटा बिजली आपूर्ति हुई और इसकी प्रति संलग्न है लेकिन ऑनलाईन में कहीं प्रति

संलग्न नहीं मिला है और यह जो कह रहे हैं कि 22 घंटे बिजली आपूर्ति किए हैं, 2021-22 में ही हमारे जिला औरंगाबाद में कितने दिन तक मिला है हम इसके लिए चैलेंज कर सकते हैं कि इसमें कमी है और इसमें हर हालत में जांच होनी चाहिए ।

टर्न-2/अंजली/17.03.2023

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, ऊर्जा विभाग ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, उत्तर स्पष्ट रूप में दे दिया गया है । इसमें कोई गुंजाइश नहीं बचती है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री प्रेम कुमार ।

अल्पसूचित प्रश्न संख्या-60 (श्री प्रेम कुमार, क्षेत्र संख्या-230, गया टाउन)

(प्रश्न नहीं पूछा गया)

अब तारांकित प्रश्न लिये जायेंगे । माननीय सदस्या श्रीमती नीतु कुमारी ।

तारांकित प्रश्न संख्या-1958 (श्रीमती नीतु कुमारी, क्षेत्र संख्या-236, हिसुआ)

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री (लिखित उत्तर) : अध्यक्ष महोदय, आंशिक स्वीकारात्मक है ।

वस्तुस्थिति यह है कि नवादा जिला के हिसुआ विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत 33/11 KV विद्युत शक्ति उपकेंद्र, हिसुआ एवं नारदीगंज को 132/33 KV ग्रिड (GSS) नवादा से 33 KV हिसुआ फीडर द्वारा विद्युत आपूर्ति की जाती है । गर्मी के दिनों में Peak hour में विद्युत मार बढ़ने के कारण 33 KV हिसुआ फीडर का ACSR Dog Conductor अधिभारित हो जाती है, जिसके निराकरण हेतु 220/132/33 KV ग्रिड (GIS) खनवा से 33/11 KV विद्युत शक्ति उपकेंद्र, हिसुआ तक एक नया 33 KV लाईन (लंबाई 13.1 CKM) निर्माण का प्रस्ताव है, जो प्रक्रियाधीन है ।

अध्यक्ष : आप पूरक पूछिये ।

श्रीमती नीतु कुमारी : अध्यक्ष महोदय, पूरक यही है कि तार की स्थिति बहुत जर्जर है उसको चेंज करा दिया जाय । हमेशा कुछ न कुछ घटना घटते रहती है । दो-चार लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से यही कहूंगी कि तार को जल्द चेंज करा दें ।

अध्यक्ष : आप माननीय सदस्यों को बैठाइए न । आप माननीय सदस्यों को स्थान पर बैठाइए, आप बैठाइए तो ।

माननीय सदस्या, आपको माननीय मंत्री जी का जवाब मिला हुआ है आप पूरक पूछिये ।

श्रीमती नीतु कुमारी : अध्यक्ष महोदय, मेरा पूरक यही है कि वह तार जो है वह बहुत जर्जर स्थिति में है और वहां कई बार घटना भी घट चुकी है, दो लोगों की मृत्यु हो चुकी है इसलिए मैं मंत्री जी से चाहूंगी कि जल्द से जल्द उस तार को चेंज करवा दिया जाय ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, उत्तर में लिखा हुआ है कि प्रस्ताव है, कार्रवाई की जा रही है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्या श्रीमती मीना कुमारी ।

तारांकित प्रश्न संख्या-1959 (श्रीमती मीना कुमारी, क्षेत्र संख्या-34, बाबूबरही)

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, उप मुख्यमंत्री (लिखित उत्तर) : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि सतधारा ग्राम में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र न होकर स्वास्थ्य उपकेंद्र स्वीकृत है । वर्तमान में स्वास्थ्य उपकेंद्र पंचायत भवन में संचालित है । जहां श्रीमती लक्ष्मी कुमारी एन0एन0एम0 एवं श्री उमेन्द्र कुमार सिंह सी0एच0ओ0 द्वारा आमजनों को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है ।

सतधारा ग्राम स्थित अर्द्धनिर्मित स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण, भवन निर्माण विभाग के द्वारा लगभग 15 वर्ष पूर्व ही प्रारंभ किया गया था, परंतु पूर्ण नहीं किये जाने के कारण हस्तगत नहीं कराया जा सका ।

वर्तमान में माननीय सदस्य के अनुशंसा के आधार पर नये भवन निर्माण की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है ।

अध्यक्ष : आप पूरक पूछिये ।

श्रीमती मीना कुमारी : अध्यक्ष महोदय, मधुबनी जिलान्तर्गत बाबूबरही प्रखंड के सतधारा ग्राम में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मंजूर हो गई है लेकिन एक साल पहले उसका टेंडर भी हो गया है लेकिन अभी तक, वहां पर संवेदक से हमारी आज बात हुई है तो हम कहें कि आज तक क्यों इसको शुरू नहीं किए हैं तो संवदेक का कहना था कि वहां पर जब सीमांकन करने गए थे तो वहां जमीन खाली थी, लेकिन अभी वर्तमान में उसको अतिक्रमण कर लिया गया है तो पता चला है कि सी0ओ0 के द्वारा ही कराया गया है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्या, आप पूरक पूछिये ।

श्रीमती मीना कुमारी : अध्यक्ष महोदय, पूरक ही है ।

अध्यक्ष : आपका यह पूरक नहीं हो रहा है ।

श्रीमती मीना कुमारी : अध्यक्ष महोदय, पूरक ही है कि कब तक बनेगा, जमीन अतिक्रमण है, उसको खाली कब तक की जाएगी । एक साल से ज्यादा हो गया टेंडर का, कब बनेगा ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, जवाब में हमने दिया है कि अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र न होकर स्वास्थ्य उपकेंद्र की स्वीकृति है । वर्तमान में स्वास्थ्य उपकेंद्र पंचायत भवन में संचालित है जहां श्रीमती लक्ष्मी कुमारी एन0एन0एम0 एवं श्री उमेन्द्र कुमार सिंह सी0एच0ओ0 द्वारा आमजनों को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई जा रही थी ।

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण सदन से बहिर्गमन कर गए)

जो सतधारा ग्राम स्थित अर्द्धनिर्मित स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण, भवन निर्माण विभाग के द्वारा लगभग 15 वर्ष पूर्व ही प्रारंभ किया गया था । जो ये प्रश्न पूछ रही हैं जो आधा-अधूरा भवन है, वह भवन निर्माण जो है 15 साल पहले से ही उसको बना रहा था परंतु पूर्ण नहीं किए जाने के कारण हस्तगत नहीं कराया जा सका है । हम माननीय सदस्या से कहेंगे कि भवन निर्माण अगर नहीं बना रहा है तो जैसी इनकी इच्छा हो, हम भवन निर्माण से अनुरोध भी कर सकते हैं कि वे बनाएं और नहीं तो अगर आपकी इच्छा होगी तो हम खुद ही, हमारा विभाग बनाकर के वह काम करा देगी ।

श्रीमती मीना कुमारी : अध्यक्ष महोदय, मेरे द्वारा अनुशंसा हो गई है, वहां पर स्वीकृत है वे कब बनायेंगे ? नीचे की एक लाईन छूट गयी है मंत्री जी से, जवाब हमारे पास आया है। उसमें लिखा हुआ है वर्तमान में माननीय सदस्य के अनुशंसा के आधार पर नये भवन का निर्माण कार्य कार्रवाई प्रक्रियाधीन है ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, उप मुख्यमंत्री : आपको हम कह रहे हैं कि जो स्वीकृत है, जो आधा-अधूरा बना है, वह भवन निर्माण 15 साल से बना रहा है, अगर नहीं तो हम भवन निर्माण को अनुरोध कर दें, आपकी जो इच्छा हो, या तो हम अनुरोध कर दें भवन निर्माण विभाग को या तो हम खुद ही बना लें ।

श्रीमती मीना कुमारी : नया बनाना है, देखिए लिस्ट में आ गया है नया बनाना है । वहां पर जमीन खाली करवाइए न ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ने आपके प्रश्न का जवाब दे दिया है, आप स्थान ग्रहण करें ।

माननीय सदस्य श्री लाल बाबू प्रसाद गुप्ता ।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या-1960 (श्री लाल बाबू प्रसाद गुप्ता, क्षेत्र संख्या-20, चिरैया)</u>

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

माननीय सदस्य श्री मुकेश कुमार यादव ।

तारांकित प्रश्न संख्या-1961 (श्री मुकेश कुमार यादव, क्षेत्र संख्या-27, बाजपट्टी)

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, उप मुख्यमंत्री (लिखित उत्तर): अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि सीतामढ़ी सदर अस्पताल में नशा मुक्ति केंद्र के संचालन हेतु 08 वार्ड अटेंडेंट की प्रतिनियुक्ति की जानी थी परंतु जिला स्वास्थ्य समिति के द्वारा 08 वार्ड अटेंडेंट को आउटसोर्स किया गया था ।

सदर अस्पताल, सीतामढ़ी में 125 जी0एन0ए0एम0 के पदस्थापन के उपरांत प्राइवेट एजेंसी के माध्यम से वार्ड अटेंडेंट पर होने वाले व्यय को महालेखाकार, बिहार के अंकेक्षण प्रतिवेदन संख्या-322/16-17 के अनुसार उपयुक्त नहीं माना गया, जिसके कारण उक्त 08 अटेंडेंट की सेवा संबंधित एजेंसी को वापस कर दी गई एवं उनके कार्य अवधि का भुगतान किया जा चुका है ।

अध्यक्ष : आप पूरक पूछिये ।

श्री मुकेश कुमार यादव : अध्यक्ष महोदय, माननीय उप मुख्यमंत्री सह-स्वास्थ्य मंत्री जी का जवाब आया है कि इसमें सिर्फ माननीय मंत्री जी से मैं जानना चाहता हूं कि इसमें प्राइवेट एजेंसी के माध्यम से अटेंडेंट के महालेखाकार की रिपोर्ट आई है तो सिर्फ सीतामढ़ी जिले में हटाया गया है, अन्य जिलों में आउटसोर्स के माध्यम से कार्य कर रहा है । इसलिए माननीय उप मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि अन्य जिलों में जो किया जा रहा है उसी तरह से सीतामढ़ी जिले में भी रखा जाय ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, इनका सवाल आया था कि संविदा पर किया गया है, साफ तौर पर कहा गया है कि संविदा पर नियुक्ति नहीं की गई थी बल्कि उन्हें आउटसोर्स किया गया था बल्कि महालेखाकार की कुछ क्वेरी थी उसकी वजह से यह नहीं हो पाया था ।

अध्यक्ष : संभव नहीं है । माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा ।

तारांकित प्रश्न संख्या-1962 (श्री अजीत शर्मा, क्षेत्र संख्या-156, भागलपुर)

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, उप मुख्यमंत्री (लिखित उत्तर) : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण सदर अस्पताल, भागलपुर में चर्मरोग विशेषज्ञ के पद पर एक चिकित्सक, शिशु रोग विशेषज्ञ के पद पर दो चिकित्सक कार्यरत हैं तथा 25 (पचीस) स्टाफ नर्स ग्रेड-ए कार्यरत हैं ।

आयुष फिजिशियन के पद पर नियुक्ति हेतु अधियाचना बिहार तकनीकी सेवा आयोग को भेजी गई है, जिसके अनुशंसोपरांत शीघ्र नियुक्ति की कार्रवाई की जाएगी । अधीक्षक के पद पर पदस्थापन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है ।

श्री अजीत शर्मा : महोदय, जवाब आया हुआ है, पूरक पूछता हूं । महोदय, माननीय मंत्री जी ने विवरण दिया है कि पदस्थापन का, मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण सदर अस्पताल, भागलपुर के अंतर्गत अधीक्षक चर्म रोग विशेषज्ञ, आयुष फिजिशियन, शिशु रोग विशेषज्ञ और स्टाफ नर्स के कितने पद स्वीकृत हैं और कितनी रिक्तियां हैं तथा रिक्तियों को कब तक भर दिया जायेगा ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, इसमें इनका सवाल आया था कि जो सदर अस्पताल है भागलपुर अंतर्गत, अधीक्षक-1, चर्म रोग विशेषज्ञ-1, आयुष फिजिशियन-2 शिशु रोग विशेषज्ञ-1, स्टाफ नर्स-25 पद विगत पांच वर्षों से अधिक समय से रिक्त हैं । हमने जवाब में दिया है कि वस्तुस्थिति यह है कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण सदर अस्पताल, भागलपुर में शिशु रोग विशेषज्ञ के पद पर दो चिकित्सक कार्यरत हैं तथा 25 स्टाफ नर्स ग्रेड-ए कार्यरत हैं ।

आयुष फिजिशियन के पद पर नियुक्ति हेतु अधियाचना बिहार तकनीकी सेवा आयोग को भेजी गई है, जिसके अनुशंसोपरांत शीघ्र नियुक्ति की कार्रवाई की जाएगी । अधीक्षक एवं चर्म रोग विशेषज्ञ के पद पर पदस्थापन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है तो इसमें शीघ्र जैसे ही वहां से आता है तो हमलोग करा लेते हैं ।

श्री अजीत शर्मा : अध्यक्ष महोदय, और कुछ है, जैसे आपने कहा कि 25 नर्स वहां पर पदस्थापित हैं, मैंने यह पूछा कि कितने पद हैं जो रिक्त हैं ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, शर्मा जी, माननीय मंत्री जी का जो जवाब है बहुत ही सकारात्मक है, आप स्वयं समझते हैं ।

श्री अजीत शर्मा : बिल्कुल है । लेकिन हम आग्रह करेंगे मंत्री जी से कि इसको दिखवा लें अगर वह रिक्त है तो ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, इनका सवाल था कि जैसे इग्जांपल है- स्टाफ नर्स 25 पद विगत पांच वर्षों से अधिक समय से रिक्त हैं । इसमें साफ तौर पर दिया गया है उत्तर में कि 25 स्टाफ नर्स ग्रेड-ए कार्यरत हैं ।

श्री अजीत शर्मा : महोदय, वह सही है कार्यरत है लेकिन और भी जो रिक्त है, उसके लिए 25 खाली है वह मैंने बताया ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, उप मुख्यमंत्री : महोदय, पूरे बिहार में सिर्फ भागलपुर ही नहीं, हमारी सरकार नीतीश जी के नेतृत्व में यह फैसला, निर्णय लिया है कि जहां भी रिक्त पदें हैं उसको भरने की कवायद वह चल रही है ।

श्री अजीत शर्मा : धन्यवाद ।

तारांकित प्रश्न संख्या–1963 (श्री अनिल कुमार, क्षेत्र संख्या–231, टिकारी)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री अनिल कुमार । आप पूरक पूछिये ।

श्री अनिल कुमार : महोदय, उत्तर नहीं मिला है ।

अध्यक्ष : उत्तर नहीं मिला है । माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग जवाब पढ़ दें, इनको जवाब नहीं मिला है ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार पटना के द्वारा वर्ष 2020 में बी0एम0एस0आई0सी0एल0 के माध्यम से अल्ट्रासाउंड मशीन की आपूर्ति करायी गई थी, परंतु उस समय स्त्री रोग विशेषज्ञ/रेडियोलॉजिस्ट की पदस्थापना नहीं होने के कारण अल्ट्रासाउंड मशीन अधिष्ठापन हेतु वांछित पी0सी0 एंड पी0एन0डी0टी0 सर्टिफिकेट निर्गत नहीं किया जा सका । तदुपरांत चमकी बुखार के चिकित्सीय प्रबंधन हेतु उस अल्ट्रासाउंड मशीन को बी0एम0एस0आई0सी0एल0 द्वारा मुजफ्फरपुर में अधिष्ठापित करा दिया गया । वर्तमान में अनुमंडलीय अस्पताल, टिकारी में रेडियोलॉजिस्ट की पदस्थापना हो गई है । अब पी0सी0 और पी0एन0डी0टी0 सर्टिफिकेट निर्गत करने में कोई तकनीकी अड़चन नहीं है ।

अनुमंडलीय अस्पताल, टिकारी में दो माह के अंदर अल्ट्रासाउंड मशीन उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया है ।

श्री अनिल कुमार : धन्यवाद माननीय मंत्री जी को । माननीय सदस्य श्री राम सिंह ।

तारांकित प्रश्न संख्या–1964 (श्री राम सिंह, क्षेत्र संख्या–4, बगहा)

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

माननीय सदस्य श्री गुंजेश्वर साह ।

टर्न–3/सत्येन्द्र/17–03–2023

तारांकित प्रश्न संख्या– 1965(श्री गुंजेश्वर साह,क्षेत्र सं0–77,महिषी)

अध्यक्ष: आप पूरक पूछिये । आपको प्रश्न का जवाब उपलब्ध हो गया है ?

श्री गुंजेश्वर साह: उत्तर नहीं मिला है ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री: ऊर्जा विभाग स्ट्रीट लाईट नहीं लगाती है । पंचायती राज विभाग की ओर से लगाया गया होगा ।

अध्यक्ष: पंचायती राज के लिए यह स्थानांतरित हो गया है ।

ये क्वेश्चन नं0-1965, श्री गुंजेश्वर साह का है और ये ऊर्जा विभाग से प्रश्न किये हैं और ऊर्जा विभाग ने कहा कि पंचायती राज विभाग का मामला है इसलिए पंचायती राज विभाग को स्थानांतरित किया गया है माननीय सदस्य । पंचायती राज विभाग इसका जवाब इसी सत्र में वे देंगे ।

तारांकित प्रश्न संख्या- 1966(श्री पवन कुमार यादव,क्षेत्र सं0-155,कहलगांव)

(अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न संख्या- 1967(श्री गुंजेश्वर साह,क्षेत्र सं0-77,महिषी)

अध्यक्ष: अब आया है माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग का ।

श्री गुंजेश्वर साह: पूछता हूँ ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव,उपमुख्यमंत्री: आंशिक स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, पंचगछिया, सहरसा के नवनिर्मित भवन में फिलहाल प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पंचगछिया संचालित है, जिसमें 01 दन्त चिकित्सक पदस्थापित एवं कार्यरत है । इसके अतिरिक्त उक्त संस्थान में 24×7 चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु डॉ0 धीरज कुमार ''मुन्ना'' चिकित्सा पदाधिकारी, अनुमंडलीय अस्पताल, सिमरी बख्तियारपुर एवं डॉ0 दिलीप कुमार मंडल, चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सिमरी बख्तियारपुर से कार्य लिया जा रहा है ।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, पंचगछिया, सहरसा में मानक के अनुरूप चिकित्सकों के पद सृजन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है ।

अध्यक्ष: माननीय विधायक जी, क्या आप और पूरक पूछना चाहते हैं या माननीय मंत्री जी के उत्तर से आप संतुष्ट हैं ?

श्री गुंजेश्वर साह: हम संतुष्ट हैं लेकिन पूछना चाहते हैं ।

अध्यक्ष: पूछा जाय ।

श्री गुंजेश्वर साह: अध्यक्ष महोदय, हम माननीय मंत्री जी से कहना चाहते हैं कि सत्तरकटैया बिहार में ऐसा प्रखंड हैं जहां बिहार में सबसे अधिक कैंसर के मरीज है और सबसे अधिक कैंसर से लोग वहीं के मरते हैं । अगले बार भी हमलोग ध्यानाकर्षण में लाये थे ।

अध्यक्ष: पूरक पूछा जाय ।

श्री गुंजेश्वर साह: तो पूरक यह है कि वहां पर सामुदायिक भवन बनकर तैयार है और उसका नोटिफिकेशन नहीं हुआ है जिसके चलते जो प्रक्रियाधीन है वह तब होगा जब उसका नोटिफिकेशन हो जायेगा । उसी भवन में दो वर्षों से चल रहा है होस्पीटल, सामुदायिक विकास भवन में उसका नोटिफिकेशन हो और डॉक्टर वहां स्थायी रूप

से रहे । सबसे अधिक लोग वहां त्रस्त है कैंसर है और पूरे बिहार में कैंसर का सबसे अधिक मरीज वहीं के है ।

अध्यक्ष: माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव,उपमुख्यमंत्री: यह प्रक्रियाधीन है । इस पर जल्द ही कार्रवाई की जायेगी।

अध्यक्ष: जल्दी कार्रवाई की जा रही है।

तारांकित प्रश्न संख्या-1968 (श्री जनक सिंह, क्षेत्र सं0-116 तरैया)

(अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न संख्या- 1969 (श्री प्रहलाद यादव, क्षेत्र सं0- 167, सूर्यगढ़ा)

(लिखित उत्तर)

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, उपमुख्यमंत्री: वस्तुस्थिति यह है कि सूर्यगढ़ा प्रखंड की आबादी लगभग 3,42,000 है। यहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र है, जहाँ तीन सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी एक स्त्री रोग विशेषज्ञ, डॉ0 ममता कुमारी (बॉन्ड के आधार पर कार्यरत) पदस्थापित एवं कार्यरत हैं । उक्त स्वास्थ्य केन्द्र 30 बेड का अस्पताल है, जहाँ ओ0पी0डी0, आई0पी0डी0 संस्थागत प्रसव परिवार नियोजन ऑपरेशन तथा टीकाकरण का कार्य सफलतापूर्वक किया जा रहा है । साथ ही उक्त स्वास्थ्य केन्द्र पर 24x7 चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है ।

चानन प्रखण्ड की आबादी लगभग 1,37,000 है । सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, चानन 30 बेड का अस्पताल है, जहाँ प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी के रूप में डॉ0 रितुराज कार्यरत है । साथ ही एक सामान्य चिकित्सक डॉ0 शालिनी शर्मा पदस्थापित एवं कार्यरत हैं । उक्त स्वास्थ्य केन्द्र पर ओ0पी0डी0, आई0पी0डी0 संस्थागत प्रसव परिवार नियोजन ऑपरेशन तथा टीकाकरण का कार्य सफलतापूर्वक किया जा रहा है ।

रिक्त पदों पर नियुक्ति की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है ।

अध्यक्ष: आप पूरक पूछें । जवाब उपलब्ध हो गया है आपको ?

श्री प्रहलाद यादव: जी, पूरक ही पूछ रहे हैं। माननीय मंत्री जी से हम जानना चाहते हैं कि जो जवाब आया है यह सही नहीं है । महोदय, सूर्यगढ़ा प्रखंड में 3 लाख से अधिक आबादी है और चानन प्रखंड में 1 लाख से ज्यादा की आबादी है और वहां पर जो स्थिति है, महिला डॉक्टर जो है वह कभी भी नहीं आती है और एक जो पदस्थापित हैं वह भी गायब रहते हैं और चानन में तो बिल्कुल गायब ही रहते हैं, ये स्थिति है तो माननीय मंत्री जी से मैं मांग करता हूँ कि पहले तो बेड बढ़ा दीजिये, वहां 30 बेड का ही है और 3 लाख से ज्यादा की आबादी है ।

अध्यक्षः पूरक पूछिये ।

श्री प्रहलाद यादवः बेगूसराय का जो दियारा इलाका है साम्भो है,सरलाही है,बिजुलिया है उस जिला का भी आदमी सूर्यगढ़ा में आता है तो माननीय मंत्री जी से मैं मांग करता हूँ कि उसको तो 100 बेड कर दीजिये और जो जवाब दिया गया है निश्चित रूप से इसको जांच करवा लीजिये इसलिए कि ये गलत रिपोर्ट दिया गया है ।

अध्यक्षः माननीय सदस्य, अब आप स्थान ग्रहण करें । माननीय मंत्री ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव,उपमुख्यमंत्रीः इसमें जो चानन प्रखंड की बात की जा रही है महोदय, यहां डॉक्टर शालिनी शर्मा पदस्थापित हैं और कार्यरत हैं, फिर भी अगर शिकायत है कि वह उपस्थित नहीं होती है तो हमारा विभाग जो है जांच करवा लेगा, दिखवा लेगा । चानन प्रखंड में पदस्थापित होने के वाबजूद भी अगर कोई डॉक्टर अगर वहां नहीं जा रहा है तो हमारा विभाग जांच करवाकर दिखवा लेगा लेकिन बाकी जो नियुक्ति के लिए है, उसमें रिक्त पदों पर नियुक्ति की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है, प्रोसेस में है वह चल रहा है ।

अध्यक्षः माननीय सदस्य, अब हो तो गया ।

श्री प्रहलाद यादवः बेड के बारे में माननीय मंत्री जी नहीं बोल रहे हैं, बेड तो बढ़ाया जाय।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव,उपमुख्यमंत्रीः अभी बेड बढ़ाने की कोई वैसा पौलिसी नहीं है, अभी इस पर विचार नहीं है । हर ब्लौक में मैक्सिमम जो है 30 बेड का ही किया गया है, हर ब्लौक की जहां तक बात है और जब आगे निर्णय होगा तो उस पर बात होगी ।

अध्यक्षः प्रहलाद बाबू, बैठ जाईए ।

श्री राज कुमार सिंहः अध्यक्ष महोदय, हमारा क्षेत्र सान्हो से भी यह सबंध रखता है...

अध्यक्षः माननीय सदस्य, प्रहलाद बाबू ने जो प्रश्न किया है, वे स्पेसिफिक जगह के बारे में उन्होंने कहा, उसकी सूचना और जांच सरकार मंगायी और सरकार ने उसी संदर्भ में जवाब दे दिया इसीलिए आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं, आप अलग से पूछियेगा तो सरकार उस पर जवाब देगी । आप स्थान ग्रहण कीजिये ।

तारांकित प्रश्न संख्या- 1970 (श्री संदीप सौरभ, क्षेत्र सं0-190, पालीगंज)

(लिखित उत्तर)

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, उपमुख्यमंत्रीः आंशिक स्वीकारात्मक । वस्तुस्थिति यह है कि State Allied And Healthcare Council गठन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है । इसके ड्राफट (प्रारूप) पर वित्त तथा विधिक परामर्श प्राप्त है । प्राप्त परामर्श के आलोक में उक्त काउंसिल के गठन की कार्रवाई की जा रही है ।

श्री संदीप सौरभः पूरक पूछ रहा हूँ महोदय ।

अध्यक्ष: पूछिये पूरक ।

श्री संदीप सौरभ: महोदय, मैंने मांग की थी State Allied and Health Care Council यानी पारा मेडिकल काउन्सिल जो बिहार का है उसको गठन करने के लिए । कई वर्षों से देश के बाकी राज्यों में, बिहार को छोड़कर बाकी सारे राज्यों में ये पारा मेडिकल काउन्सिल का गठन हो चुका है, बिहार में लंबे समय से छात्रों की मांग है और लाखों छात्र इससे प्रभावित हैं और ये काउन्सिल नहीं होने की वजह से बिहार के अभ्यर्थी जो हैं, पारा मेडिकल के जो स्टुडेंटस है वे किसी और राज्य में अप्लाई नहीं कर सकते हैं । इसका सबसे बड़ा नुकसान बिहार के बच्चों को यह हुआ, उसके अलावे सरकार को यह तक पता नहीं है कि पारा मेडिकल स्टूडेंटस जो है उसमें कितने स्टूडेंटस ट्रेंड है। यह जानकारी अगर सरकार को होती तो कोरोना के टाईम में इलाज में भी काफी सहुलियत होती । तीसरा जो इसका नुकसान है कि काउन्सिल नहीं होने से कोई भी बहाली आता है बिहार में तो बाहर के लोग जो आवेदन करते हैं उसमें तमाम तरह के फर्जी डिग्री भी आती है इसके चलते बहालियां जो है वह लंबित हो जाती है। जैसे 2014 की जो बहाली आयी वह 21 में पूरी हुई ।

अध्यक्ष: माननीय सदस्य..

श्री संदीप सौरभ: मैं पूरक पर आ रहा हूँ महोदय, वर्ष 2021 में भारत सरकार के एक गजट में यह आदेश जारी किया गया कि सभी राज्यों को 6 महीना के अंदर पारा मेडिकल काउन्सिल का गठन करना है वर्ष 2021 में और उसकी सूचना केन्द्र को देना है लेकिन उसके वाबजूद बिहार में क्यों 6 महीना के अंदर गठित नहीं हुआ, ये मेरा पहला पूरक है ।

अध्यक्ष: अब मंत्री जी के जवाब को सुनिये, उनकी बात को सुनिये । माननीय मंत्री ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव,उप मुख्यमंत्री: जवाब में तो स्पष्ट कर दिया गया है महोदय । वस्तुस्थिति यह है कि State Allied And Healthcare Council गठन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है । इसके ड्राफट (प्रारूप) पर वित्त तथा विधिक परामर्श प्राप्त है । प्राप्त परामर्श के आलोक में उक्त काउंसिल के गठन की कार्रवाई की जा रही है ।

श्री संदीप सौरभ: महोदय, मैं कह रहा हूँ कि 2021 में यह गजट का हिस्सा बनकर आया है और उसके पहले सारे राज्यों में लागू है, बना हुआ है और 2021 के बाद आज 2023 आ गया जबकि 6 माह के अंदर ही करना था । जवाब में भी कोई समय सीमा नहीं दिया गया है । हम तो समय सीमा की मांग करते हैं सरकार से कि समय सीमा क्या हो सकता है ?

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, उपमुख्यमंत्रीः आपके सवाल पर विभाग से हमलोगों को भी यह जानकारी मिली । यही विधान-सभा से फायदा हुआ और उत्तर में साफ तौर पर है कि इसके गठन की कार्रवाई जारी है । इसको हमलोग दिखवाकर समय सीमा के अंदर करवा देंगे ।

अध्यक्षः प्रोसेस में है । आप स्थान ग्रहण करें ।

श्री संदीप सौरभः महोदय,एक समय सीमा की बात और दूसरा मैं सरकार को सजेशन देना चाहता हूँ कि जो गठन होगा कि उसमें जो पारा मेडिकल स्टूडेंटस के जो अलग अलग कैडर होते हैं, उनके जो सदस्य हैं, उनको भी सदस्य रखा जाय जैसे बाकी राज्यों में है ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, उपमुख्यमंत्रीः इसमें जो भी सुझाव है, लिखित में हमको दे दीजिये । आप लिखित उपलब्ध करवा दीजिये जो संभव होगा वह किया जायेगा ।

अध्यक्षः सौरभ जी आप लिखित दे दीजिये । माननीय मंत्री जी उसको दिखवा लेंगे ।

श्री संदीप सौरभः अध्यक्ष महोदय, इसमें अभी भी छात्र आन्दोलन कर रहे हैं और इसलिए इसको जल्दी से जल्दी सरकार करे ।

अध्यक्षः अब तो स्थान ग्रहण कीजिये ।

टर्न-4/मधुप/17.03.2023

<u>तारांकित प्रश्न संख्या-1971, श्री संजय कमार तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी (क्षेत्र सं0 200 बक्सर)</u>

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, उप मुख्यमंत्री(लिखित उत्तर) : वस्तुस्थिति यह है कि सदर अस्पताल, बक्सर में एल0एस0ए0एस0 प्रशिक्षित दो चिकित्सक यथा डॉ0 अभिषेक कुमार एवं डॉ0 विनिश कुमार कार्यरत हैं, जिनके द्वारा ऑपरेशन के दौरान मूर्च्छक का कार्य किया जाता है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य तिवारी जी, आप पूरक पूछिये ।

श्री संजय कुमार तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी : महोदय, मैं पूरक ही पूछ रहा हूँ । मुझे उत्तर प्राप्त हो गया है ।

अध्यक्ष : पूछा जाय ।

श्री संजय कुमार तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी : महोदय, बक्सर जिला में दो अनुमंडल है, हमारे इस प्रश्न के उत्तर में एनेस्थीसिया के दो डॉक्टर रखने की बात कही गयी है । दो अनुमंडल है - डुमराव और बक्सर, मरीजों का भारी दबाव रहता है वहाँ के अस्पतालों में । चाहे एक्सीडेंटल मरीज हों या गर्भवती प्रसूति महिलाओं का मामला

हो और ये दो डॉक्टर जो हैं बराबर उन अनुमंडल अस्पतालों में या राजकीय अस्पताल में नहीं रह पाते हैं, या तो वे प्राइवेट हॉस्पीटल में जाते हैं । एक का तो बराबर गायब रहना, बाजिव है कि एक बराबर ही गायब रहते हैं इससे मरीजों को काफी कठिनाइयॉं होती हैं दोनों अस्पतालों में ।

मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि दो और एनेस्थीसिया डॉक्टरों की वहॉं पदस्थापना कब तक कर देंगे ? माननीय मंत्री जी से मैं यह जानना चाहता हूँ ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, दो डॉक्टर ऑलरेडी हैं ही और इनके द्वारा मूर्क्षक का कार्य किया जाता है । अभी तक ऐसी कोई कठिनाई वहॉं पायी नहीं गयी है । अगर जरूरत पड़ेगी तो उसमें हमलोग देखेंगे ।

(इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यगण सदन में आ गये)

श्री संजय कुमार तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी : हुजूर, ये कठिनाइयॉं वहॉं के स्थानीय पदाधिकारी नहीं बता पाते हैं और वे अपने कार्य को छुपाते हैं तो मैं माननीय मंत्री जी से यह आग्रह करूंगा कि यथाशीघ्र अगर दो एनेस्थीसिया डॉक्टरों को वहॉं बहाल कर देंगे तो हमारे दोनों अनुमंडल में पर्याप्त संख्या हो जायेगी और मरीजों की जान बच जायेगी एक्सीडेंटल केसों में या गर्भवती महिलाओं का, तो मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि यथाशीघ्र दो और डॉक्टर की पदस्थापना वहॉं कराने की कृपा प्रदान करें ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, उप मुख्यमंत्री : महोदय, देखवा लेंगे ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी देखवा लेंगे ।

श्री संजय कुमार तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी : जी । धन्यवाद ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय नेता प्रतिपक्ष, आप क्या कहना चाहते हैं ? लेकिन आप लोग स्थान तो ग्रहण कर लीजिये । बैठ जाइये ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, पीड़ित परिवार थाने के अंदर बैठा रो रहा है । माननीय मुख्यमंत्री सारे कागजात लिये और उन्होंने कहा कि मैं पता करके कार्रवाई करूंगा । एफ0आई0आर0 में नाम नहीं होना, मंत्री पद का दुरूपयोग हो रहा है, उनको बर्खास्त करके एफ0आई0आर0 तो प्रथम दृष्टया हो, उनपर कार्रवाई हो और आज धमकी दिया गया है ।

सरकार इसपर जवाब दे कि क्या हुआ ? 10 दिन से ज्यादा हो चुका है, अध्यक्ष महोदय ।

अध्यक्ष : हो तो गया ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : जवाब सरकार से दिलाइये न । सरकार जवाब दे ।

अध्यक्ष : माननीय नेता प्रतिपक्ष, आपने इसको पूर्व में उठाया था और सरकार उसको देखवा रही है । सरकार देखवा कर जो समुचित होगा, वह कार्रवाई करेगी । आपने जो अभी सूचना दिया, मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री से चाहूँगा कि आप अपने स्तर से इसको ग्रहण करें, सरकार तो कार्रवाई कर ही रही है, आप सूचना को ग्रहण कर लीजिए । मैंने कह दिया ।

श्री नन्द किशोर यादव : महोदय ।

अध्यक्ष : बोलिये ।

(व्यवधान)

आप शांति बनाये रखें । यह प्रश्नकाल चल रहा है, नन्द किशोर बाबू ।

श्री नन्द किशोर यादव : ठीक बात है लेकिन महोदय, आपने अनुमति दिया इसलिये खड़ा हूँ ।

अध्यक्ष : मैंने कह दिया कि सरकार सूचना ग्रहण करे, सरकार सूचना ग्रहण कर रही है ।

श्री नन्द किशोर यादव : महोदय, आपने मुझे अनुमति दिया इसलिये खड़ा हूँ । बिना अनुमति के नहीं खड़ा हुआ हूँ ।

महोदय, मैं केवल एक बात कहना चाहता हूँ, मेरी बात सुन लीजिये । यह सवाल पहले भी सदन में उठा है और हमलोग बड़े प्रसन्न हुए जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका संज्ञान लिया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उन लोगों को बुलाया, बात की, कागजात माँगा ।

महोदय, सामान्य परम्परा रही है कि जिस बात का संज्ञान माननीय मुख्यमंत्री लेते हैं तो उसका क्या हुआ ? यह सरकार कभी न कभी कहती है, आज ही अभी कह देगी यह मैं नहीं कह रहा हूँ, कभी न कभी कहती है । महोदय, सामान्य रूप से संसदीय कार्य मंत्री बतायें कि इस संबंध में सरकार अपना वक्तव्य कब देगी ? इतनी ही तो बात है, महोदय । और क्या है ?

अध्यक्ष : मैंने आसन से संसदीय कार्य मंत्री को कहा है कि आप सूचना ग्रहण कर लीजिये । मैंने कहा है ।

श्री नन्द किशोर यादव : महोदय, वक्तव्य कब देंगे ? सूचना ग्रहण करें, यह कहाँ विषय है ? कब वक्तव्य देंगे, यह विषय है न ।

अध्यक्ष : माननीय ग्रामीण विकास मंत्री ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष अध्यक्ष के आसन पर भी रहे हैं और बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली को हम सब लोगों ने पढ़ा है और माननीय नन्द किशोर बाबू भी इस सदन के पुराने सदस्य हैं ।

महोदय, हमने देखा है कि अभी तक यह परम्परा नहीं रही है कि किसी भी सवाल को माननीय नेता प्रतिपक्ष उठायें, किसी माननीय सदस्य ने उठाया और सदन से बहिर्गमन कर गये, फिर सदन में आकर वही सवाल उठा रहे हैं । हमारी नियमाित्त है, महोदय । नियम का पालन होना चाहिए । महोदय, यह सदन नियम और नियमावली से चलता है । इस तरह से अगर बार-बार, सदन शुरू होता है तब नेता प्रतिपक्ष उठ जाते हैं, सदन से बाहर चले जाते हैं, फिर लौटकर आते हैं, फिर खड़े हो जाते हैं तो क्या सदन नियम से चलेगा अध्यक्ष महोदय, नियमावली से चलेगा कि दबाव से सदन चलेगा ? यह विरोधी दल के लोगों के दबाव से सदन चलेगा ? यह सदन आपसे जानना चाहता है, अध्यक्ष महोदय ।

अध्यक्ष : सदन नियम और कानून से चलेगा, विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली से चलेगा । माननीय नेता प्रतिपक्ष बिना किसी कारण के सदन से बाहर चले गये और फिर बिना बुलाये ही वे सदन में आये हुये हैं । यह परिपाटी नहीं है।

(इस अवसर पर भा0ज0पा0 के माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर खड़े हो गये)

(व्यवधान)

आप गये और फिर आ गये । आपको बुलाया जाता तो आते । अपने ही न गये ?

(इस अवसर पर भा0ज0पा0 के कई माननीय सदस्यगण वेल में आ गये)

अभी प्रश्नकाल है । श्री हरीभूषण ठाकुर 'बचोल' । श्री हरीभूषण ठाकुर 'बचोल' ।

तारांकित प्रश्न सं0 1972, श्री हरीभूषण ठाकुर 'बचोल'(क्षेत्र सं0 35, बिस्फी)

(प्रश्न नहीं पूछा गया)

माननीय सदस्या श्रीमती मंजु अग्रवाल ।

यह देखिये । यह शून्यकाल है ? आपने तो पढ़ दिया । माननीय मंत्री श्रवण कुमार जी ने आपको यह बतला भी दिया, आप इस आसन पर भी रहे हुये हैं । सरकार को मैंने कहा कि आपकी सूचना को सरकार ग्रहण करे और सरकार सूचना ग्रहण करती है । आप बैठिये । मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है, कार्रवाई चल रही होगी और जो फलाफल आयेंगे, उस फलाफल की भी आपको जानकारी दे दी जायेगी । श्रीमती मंजु अग्रवाल ।

(व्यवधान जारी)

तारांकित प्रश्न संख्या–1973, श्रीमती मंजु अग्रवाल (क्षेत्र सं0–226, शेरघाटी)

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री (लिखित उत्तर) : 1– वस्तुस्थिति यह है कि शेरघाटी नगर परिषद् के वार्ड संख्या– 26, 27 एवं 28 में अधिकांश जगहों पर LT AB Cable लगाकर विद्युत आपूर्ति की जा रही है, शेष जगहों पर विद्युत संरचना हेतु स्थल निरीक्षण करा लिया गया है ।

2– उपरोक्त दोनों कार्यों को Revamped Distribution Sector Scheme (RDSS) योजना में शामिल कर लिया गया है एवं कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य जून, 2024 है ।

श्रीमती मंजु अग्रवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा पूरक है कि अतिशीघ्र शेष जगहों पर भी पोल की व्यवस्था करायी जाय जिससे जानमाल का खतरा न बने ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, ऊर्जा विभाग ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, प्रश्न से संबंधित ही न उत्तर आयेगा ! वह अलग से भी पूछ रही हैं कि और जगह भी कराया जाय तो इसका अभी क्या उत्तर होगा । जो है उसको कराया जायेगा, जो प्रश्न है ।

(इस अवसर पर माननीय नेता विरोधी दल सहित भा0ज0पा0 के माननीय सदस्यगण वेल में आ गए)

(व्यवधान जारी)

तारांकित प्रश्न सं0– 1974, श्री रामप्रीत पासवान (क्षेत्र सं0–37, राजनगर(अ0जा0)

(प्रश्न नहीं पूछा गया)

तारांकित प्रश्न सं0– 1975, श्री जय प्रकाश यादव (क्षेत्र सं0–46, नरपतगंज)

(प्रश्न नहीं पूछा गया)

तारांकित प्रश्न सं0– 1976, श्री जनक सिंह (क्षेत्र सं0–116, तरैया)

(प्रश्न नहीं पूछा गया)

तारांकित प्रश्न सं0– 1977, श्री मुरारी मोहन झा (क्षेत्र सं0–86, केवटी)

(प्रश्न नहीं पूछा गया)

तारांकित प्रश्न सं0–1978, श्री अली अशरफ सिद्दिकी(क्षेत्र सं0–158, नाथनगर)

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, उप मुख्यमंत्री (लिखित उत्तर) : वस्तुस्थिति यह है कि स्वास्थ्य उपकेन्द्र में चिकित्सक का पदस्थापन नहीं किया जाता है बल्कि ए0एन0एम0 का पदस्थापन होता है । नाथनगर विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत कुल–64 स्वास्थ्य उपकेन्द्र कार्यरत हैं । सभी स्वास्थ्य उपकेन्द्रों में ए0एन0एम0 पदस्थापित हैं एवं उनके द्वारा स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री अली अशरफ सिद्दिकी । पूरक पूछिये ।

श्री अली अशरफ सिद्दिकी : महोदय, हमको जवाब मिल गया है । हमको पूरक नहीं पूछना है। धन्यवाद । हम उत्तर से संतुष्ट हैं ।

(इस अवसर पर भा0ज0पा0 के माननीय सदस्यगण वेल में बैठ गये)

टर्न–5/आजाद/17.03.2023

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री विनय कुमार ।

तारांकित प्रश्न सं0–1979(श्री विनय कुमार, क्षेत्र सं0–225, गुरूआ)

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न सं0–1980(श्री प्रमोद कुमार, क्षेत्र सं0–19, मोतिहारी)

(प्रश्न नहीं पूछा गया)

तारांकित प्रश्न सं0–1981(श्री नीतीश मिश्रा, क्षेत्र सं0–38, झंझारपुर)

(प्रश्न नहीं पूछा गया)

तारांकित प्रश्न सं0–1982(श्री प्रमोद कुमार, क्षेत्र सं0–19, मोतिहारी)

(प्रश्न नहीं पूछा गया)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री मनोज मंजिल ।

तारांकित प्रश्न सं0–1983(श्री मनोज मंजिल, क्षेत्र सं0–195, अगिआंव)

(लिखित उत्तर)

श्री शाहनवाज, मंत्री : 1– जिलापदाधिकारी, भोजपुर से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार सूअरों के मरने का कारण की जांच हेतु त्रि–सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया । जांच दल द्वारा दिनांक–15.05.2022 को स्थलीय जांच की गयी । जांच के क्रम में पशुपालकों द्वारा बताया गया कि मृत्यु लगभग 1 से 1.5 माह पूर्व हुई है । जांच के क्रम में यह भी तथ्य उभर कर आया कि सूअरों का मृत्युपरान्त पोस्टमार्टम नहीं कराया जा सका। फलतः सुअरों की मृत्यु का कारण स्पष्ट नहीं है । साथ ही, तत्कालीन माह में मानव में किसी तरह का सुरकजनित संक्रमण की सूचना भी अप्राप्त रही है ।

2- किसी घटना/(मृत्यु के कारण) की पुष्टि में पोस्टमार्टम रिपोर्ट, संबंधित थाने में एफ0आई0आर0 आदि सहयोगी होते हैं, किन्तु प्रश्नगत मामले में न तो मृत सूअरों का पोस्टमार्टम कराया जा सका है और न ही थाने में सनहा/एफ0आई0आर0 दर्ज है । इस संबंध में गठित त्रि-सदस्यीय कमेटी को भी घटना/मृत्यु का कोई स्पष्ट प्रमाण प्राप्त नहीं हुआ है ।

3- अतः ऐसी स्थिति में आपदा प्रबंधन विभाग के प्रावधानों के अन्तर्गत अनुदान राशि का भुगतान किया जाना संभव नहीं है ।

अध्यक्ष : आप पूरक पूछें ।

(व्यवधान जारी)

नेता प्रतिपक्ष को यह शोभा नहीं दे रहा है ।

श्री मनोज मंजिल : अध्यक्ष महोदय, भोजपुर जिला के जगदीशपुर प्रखंड में 41 मांझी टोलो में हजारों सूअरों की मौत हुई । 5554 सूअरों की मौत हुई और मुआवजा के लिए वहां तीन दिन तक एस0डी0एम0 कार्यालय के सामने धरना हुआ । एस0डी0एम0 ने वादा की, डी0एम0 ने भी वादा किया था लेकिन मुआवजा नहीं मिला ....

अध्यक्ष : आप पूरक पूछिए न ।

श्री मनोज मजिल : मुआवजा नहीं मिला, यह कहा जा रहा है कि पोस्टमार्टम नहीं हुआ महोदय, पोस्टमार्टम करने की जवाबदेही किसकी है ? इन लोगों को मुआवजा कब मिलेगा ?

अध्यक्ष : आप सरकार से क्या पूछ रहे हैं ?

श्री मनोज मंजिल : महोदय, हम सरकार से 41 मांझी टोलों में जो हजारों सूअरों की मौत हुई है, हम मुआवजा की मांग कर रहे हैं कि मुआवजा इनको दिया जाय ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, आपदा प्रबंधन ।

माननीय सदस्यगण, आपलोग अपना-अपना स्थान ग्रहण करें । माननीय नेता प्रतिपक्ष, आप अपना स्थान ग्रहण करें ।

श्री शाहनवाज, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, सरकार आपदा पीड़ितों के प्रति संवेदनशील है और उनका प्रयास रहता है कि हम जो है त्वरित और शीघ्र मुआवजा राशि दें लेकिन इस परिस्थिति में आपदा प्रबंधन विभाग के कुछ प्रावधान हैं, कुछ नियम हैं, जिनके अनुकूल यह मामला नहीं आता है और न इसका पोस्टमार्टम हुआ है और न थाना में एफ0आई0आर0 दर्ज हुई है । त्रिस्तरीय समिति गठित की गई जिला पदाधिकारी के द्वारा, उसमें भी मृत्यु के कारण स्पष्ट नहीं हुये हैं जिस कारण मुआवजा नहीं दिया जा सकता है ।

श्री मनोज मंजिल : महोदय, तीन दिनों तक धरना चला था और मेडिकल टीम गांव-गांव में गई थी, उसने लिखित रिपोर्ट दी है कि लू से मौत हुई है । लू से भी हुई मौत तो प्राकृतिक आपदा में ही आती है और मंत्री महोदय, उसमें जो मांझी समाज के लोग हैं, उनके पास न तो जमीन है, न नौकरी है, न पूँजी है, न बैंक बैलेंस होता है, सूअर पालन से ही उनका पेट चलता है, जीवन यापन होता है, उसी से दवाई, शादी-विवाह, शौख-श्रृगांर करते हैं, जब वे सूअर पालन करते हैं और तभी वे बच्चा भी पालते हैं । महोदय, तीन दिनों तक .....

अध्यक्ष : आप दूसरा पूरक पूछिए ।

श्री मनोज मंजिल : महोदय, तीन दिनों तक अनिश्चितकालिन एस0डी0एम0 के सामने दो-दो बार धरना हुआ और दोनों बार एस0डी0एम0 ने एक-एक घंटा वार्ता की, भोजपुर के डी0एम0 साहेब ने कहा कि मुआवजा निश्चित रूप से मिलेगा लेकिन अभी तक मुआवजा नहीं मिला । भोजपुर जिला के बसौर में और मांझी टोलों में सूअरों की मौत हुई । टोला का टोला साफ हो गया तो पास्टमार्टम नहीं हुआ तो इसकी जवाबदेह तो सरकार है, स्वास्थ्य विभाग है और लू से हुई मौत की पुष्टि वहां के डॉक्टर ने अपनी जॉच में की है तो हम मुआवजा की मांग कर रहे हैं । मेरा माननीय मंत्री महोदय से आग्रह है कि सरकार को पावर है, सरकार इसके लिए ऑथोराईज है मुआवजा दे सकती है ।

अध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण करें, माननीय मंत्री जी ।

श्री शाहनवाज, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं पुनः इसको देखवा लेता हूँ, जो भी प्रावधान नियमानुकूल आयेगा, उसको किया जायेगा ।

अध्यक्ष : चलिए बहुत अच्छा ।

तारांकित प्रश्न सं0-1984(श्री विनय बिहारी,क्षेत्र सं0-5, लौरिया)

(प्रश्न नहीं पूछा गया)

तारांकित प्रश्न सं0-1985(श्री शम्भू नाथ यादव,क्षेत्र सं0-199, ब्रह्मपुर)

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न सं0-1986(श्री नारायण प्रसाद,क्षेत्र सं0-6, नौतन)

(प्रश्न नहीं पूछा गया)

तारांकित प्रश्न सं0-1987(श्री विद्या सागर केशरी,क्षेत्र सं0-48, फारबिसगंज)

(प्रश्न नहीं पूछा गया)

तारांकित प्रश्न सं0-1988(श्री जय प्रकाश यादव,क्षेत्र सं0-46, नरपतगंज)

(प्रश्न नहीं पूछा गया)

तारांकित प्रश्न सं0-1989(श्री बिजय सिंह,क्षेत्र सं0-68, बरारी)

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री गोपाल रविदास ।

तारांकित प्रश्न सं0-1990(श्री गोपाल रविदास,क्षेत्र सं0-188, फुलवारी(अ0जा0)

(लिखित उत्तर)

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, उप मुख्यमंत्री : अस्वीकारात्मक ।

बिहार में ममता कार्यकर्त्ताओं हेतु निर्गत दिशा-निर्देश के अनुसार ममता को प्रति प्रसव 300/-रू0 की दर से प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जाता है, जिसे ममता कार्यकर्त्ताओं को किये गये कार्य दिवस के अनुरूप दिया जाता है ।

ममता को अस्पतालों में विश्राम हेतु अलग से व्यवस्था किये जाने हेतु सभी जिलों को निदेशित किया जा चुका है ।

वर्त्तमान में ममता कार्यकर्त्ताओं को 15 हजार रूपये प्रतिमाह/पोशाक की व्यवस्था दिये जाने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, पूरक पूछिए ।

श्री गोपाल रविदास : महोदय, मेरा प्रश्न है कि ममता कार्यकर्त्ताओं को बिहार सरकार 300/- रुपये का प्रोत्साहन देती है, जबकि सुप्रीम कोर्ट का नियमन है, आदेश है कि 18000/-रू0 से कम मिलता हो तो वह गुलामी करता है । साथ ही साथ प्रतिदिन डिलीवरी नहीं होती है, एक-दो दिनों के बाद, चार दिनों के बाद होती है । उनकी जीवन रोटी कैसे चलेगी ? महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूँ कि क्या सरकार इसमें ममता कार्यकर्त्ताओं को 300/-रू0 से बढ़ाकर आगे प्रोत्साहन भत्ता देना चाहती हैं, सरकार यह विचार रखती है या नहीं ?

दूसरा जो मेरा पूरक प्रश्न है कि इनको कहा गया है कि विश्राम के लिए सभी जिलों को निदेशित कर दिया गया है लेकिन व्यवहार में नीचे में कहीं भी रात-दिन घटता हैं लेकिन इनको विश्राम के लिए कहीं जगह नहीं मिलती है । इसको लागू कब तक करायेंगे ?

और तीसरी बात है कि इनको रेगुलर भी नहीं मिलता है तो सोच लीजिए प्रतिदिन डिलिवरी नहीं होती है तो इनकी जीवन रोटी कैसे चलेगी ? जबकि जो न्यूनतम मजदूरी सरकार की है, वह मनरेगा में कम से कम 210/-रू0 और ऐसे दिहाड़ी मजदूर हैं, उनको 450/-रू0 मिलता है.....

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, उत्तर में स्पष्ट जवाब दिया जा चुका है । कोई सप्लीमेंट्री इनका नहीं था, एक ही क्वेश्चन को उन्होंने फिर से पढ़ दिया। प्रति प्रसव जो है ममता कार्यकर्त्ताओं को 300/–रू0 प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जाता है । इनका दूसरा सवाल था कि ममता कार्यकर्त्ताओं को अस्पतालों में विश्राम हेतु जगह उपलब्ध करायी जाय, इसके लिए हमारे विभाग द्वारा अलग से व्यवस्था किये जाने हेतु सभी जिलों को निदेशित किया जा चुका है कि उनको अस्पताल में विश्राम हेतु अलग से व्यवस्था की जाय और तीसरा कि 15000/–रू0 प्रतिमाह जो दिया जाय, इसके लिए सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

श्री गोपाल रविदास : अध्यक्ष महोदय, हम कह रहे हैं कि हमारी महागठबंधन की सरकार है और जब हम सत्ता में नहीं थे तो हम वादा भी किये हैं और बड़ी खुशी की बात है कि हमारे उप मुख्यमंत्री जी विभाग के प्रभारी हैं, मंत्री हैं तो कम से कम ममता कार्यकर्त्ताओं को 300/–रू0 से बढ़ाकर आगे तो करना चाहिए, यह हमारी मांग है।

अध्यक्ष : सरकार के अधीन इस तरह के किसी तरह का प्रस्ताव लंबित नहीं है, इसीलिए सरकार ने जवाब दिया, अब आप अपना स्थान ग्रहण करें ।

श्री गोपाल रविदास : महोदय, इस दिशा में कम से कम पहल तो करें ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री मोतीलाल प्रसाद ।

तारांकित प्रश्न सं0–1991(श्री मोतीलाल प्रसाद,क्षेत्र सं0–23, रीगा)

(प्रश्न नहीं पूछा गया)

तारांकित प्रश्न सं0–1992(श्री रामविलास कामत,क्षेत्र सं0–42, पिपरा)

(लिखित उत्तर)

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, उप मुख्यमंत्री : वस्तुस्थिति यह है कि राज्य के सभी स्वास्थ्य केन्द्रों एवं अस्पतालों में चरणबद्ध ढंग से चहारदिवारी का निर्माण अलग से कराये जाने की योजना है । तदनुसार अगले वित्तीय वर्ष में निधि उपलब्धता को देखते हुए विहित प्रक्रियानुसार प्रश्नगत स्वास्थ्य केन्द्रों के परिसर में चहारदिवारी का निर्माण भी कराया जायेगा ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री रामविलास कामत, पूरक पूछिए ।

श्री राम विलास कामत : अध्यक्ष महोदय, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, पिपरा अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, थुमहा एवं उप स्वास्थ्य केन्द्र, महेशपुर जो घनी आबादी के बीच में है और आये दिन इसके परिसर में ग्रामीण जानवर और आवारा किस्म के जानवरों का जमावड़ा लगा रहता है अध्यक्ष महोदय, महिलायें ....

अध्यक्ष : माननीय सदस्य पूरक पूछिए न ।

श्री रामविलास कामत : महोदय, पूरक मेरा यही है कि क्या माननीय मंत्री जी अगले वित्तीय वर्ष में कार्य पूर्ण कराना चाहते हैं ?

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, उप मुख्यमंत्री : महोदय, सभी स्वास्थ्य केन्द्र एवं अस्पतालों में चरणबद्ध ढंग से चहारदिवारी का निर्माण अलग से कराये जाने की योजना है । तदनुसार अगले वित्तीय वर्ष में निधि की उपलब्धता को देखते हुए जो विहित प्रक्रियानुसार प्रश्नगत स्वास्थ्य केन्द्रों के परिसरों में चहारदिवारी का निर्माण कराया जायेगा ।

श्री रामविलास कामत : महोदय, निधि की उपलब्धता के बाद जो किया जायेगा, मुझको लगता है कि इसको स्पष्ट कर देना चाहिए कि अगले वित्तीय वर्ष में हो जायेगा ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, उप मुख्यमंत्री : करवा दिया जायेगा अगले वित्तीय वर्ष में ।

श्री रामविलास कामत : धन्यवाद मंत्री जी ।

तारांकित प्रश्न सं0-1993(श्री लाल बाबू प्रसाद गुप्ता,क्षेत्र सं0-20, चिरैया)

(प्रश्न नहीं पूछा गया)

तारांकित प्रश्न सं0-1994(डॉ0 रामानुज प्रसाद,क्षेत्र सं0-122, सोनपुर)

(लिखित उत्तर)

श्री शाहनवाज, मंत्री : भारत सरकार द्वारा अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं तथा राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित स्थानीय प्रकृति की आपदाओं के अन्तर्गत आवारा कुत्ता, पागल कुत्ता, जंगली जानवर यथा- बंदर आदि के काटने के कारण हुई मृत्यु सम्मिलित नहीं है ।

साथ ही, प्रश्नगत मामले को अधिसूचित आपदा में सम्मिलित करने का कोई प्रस्ताव सम्प्रति आपदा प्रबंधन विभाग में विचाराधीन नहीं है ।

ज्ञातव्य हो कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा जंगली जानवरों/वन्यप्राणी यथा-बाघ, तेन्दुआ, हाथी, भालू, जंगली सूअर, लकड़बग्घा, सियार, भेड़िया, गैण्डा, जंगली कुत्ता, मगरमच्छ, घड़ियाल एवं गौर द्वारा पहुंचायी गयी क्षति के विरूद्ध प्रभावित व्यक्तियों/उनके आश्रितों को निर्धारित दर के अनुसार सहाय्य राशि का भुगतान किए जाने का प्रावधान किया गया है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, पूरक पूछिए ।

डॉ0 रामानुज प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, मेरा पूरक है कि माननीय मंत्री जी ने ....

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : माननीय नेता प्रतिपक्ष से आग्रह करता हूँ कि आप आसन पर आवें । आप आसन ग्रहण करें । आप नेता प्रतिपक्ष हैं, आपको वहां बैठना शोभा नहीं देता है, इसलिए आप अपने स्थान पर तो आवें ।

माननीय सदस्य श्री रामानुज प्रसाद जी, आप अपना पूरक पूछें ।

डॉ0 रामानुज प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, मैं पूरक ही पूछ रहा हूँ । माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि प्रावधान नहीं है । वन विभाग में जंगली कुत्ता तो आज तक हमलोगों ने नहीं देखा है, पागल कुत्ता लोगों को काटता है और पागल कुत्ता काटने से और बन्दर काटने से कई लोगों की मौत हुई है । अभी बीते पिछले महीने में हमारे यहां रंभू राय, चन्दन राज कुमार राय, नया गांव, सारण में पागल कुत्ता काटने से मौत हुई है । मैं सरकार से आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से आपदा और किसी चीज के काटने से होता है, जैसे सॉप काटने पर आपदा से राशि देने का प्रावधान किया गया है । आवारा कुत्ता अगर काटता है गरीब लोगों को और उसका ईलाज सरकार नहीं दे पाती है तो वैसी मौत पर सरकार मुआवजा देने का प्रावधान करे । अगर सरकार ऐसा करना चाहती है तो कब तक और कितना?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, आपदा प्रबंधन ।

टर्न-6/शंभु/17.03.23

(व्यवधान जारी)

श्री शाहनवाज,मंत्री : इसमें स्पष्ट तौर पर लिखा है भारत सरकार द्वारा अधिसूचित प्राकृतिक आपदा तथा राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित स्थानीय प्राकृतिक आपदाओं के अन्तर्गत आवारा कुत्ता, पागल कुत्ता जंगली जानवर यथा-बंदर आदि के काटने के कारण हुई मृत्यु सम्मिलित नहीं है और साथ ही प्रश्नगत मामले को अधिसूचित आपदा में सम्मिलित करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव अभी नहीं है ।

डॉ0 रामानुज प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, प्रस्ताव नहीं है यह तो उत्तर में है । मैं ये कहता हूँ कि सरकार इसको संज्ञान में लेकर के इसपर व्यवस्था करे-सांप काटने का नहीं था, लेकिन सामूहिक रूप से सदन का इसपर हुआ और सांप काटने पर मृत्यु का हुआ । पागल कुत्ता भी इनका ऐसा ही एक आपदा ही है कि गरीब लोगों को ही काटता है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपने जो सूचना दी उसको सरकार ने सुन लिया । इस तरह का कोई प्रोविजन नहीं है । इसलिए अपना स्थान ग्रहण करें ।

डॉ0 रामानुज प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, प्रोविजन नहीं है तो प्रोविजन करने के लिए ही तो मैं प्रश्न लाया हूँ । प्रोविजन नहीं है तो प्रोविजन सरकार करे ।

अध्यक्ष : आपने प्रश्न किया सरकार का जवाब आ गया, आगे सरकार की इस तरह की कोई बातें होगी तो देखा जायेगा । इसलिए स्थान ग्रहण करें ।

तारांकित प्रश्न सं0-1995(श्री महानंद सिंह)क्षेत्र सं0-214,अरवल

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव,उप मुख्यमंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि पत्रांक-554(10)ए, दिनांक-15.11.2011 द्वारा राजेन्द्र नगर अतिविशिष्ट नेत्र अस्पताल, पटना में निदेशक का एक पद है, मुख्य प्रशासी पदाधिकारी का एक पद है और अतिरिक्त शेष चिकित्सकों के सभी पद संविदा के आधार पर सृजित है । उक्त सृजित पदों के विरूद्ध इस संस्थान में एक निदेशक नियमित पद पर पदस्थापित हैं तथा 5 नेत्र कन्सलटेंट अनुबंध पर पदस्थापित हैं । साथ ही इस संस्थान में 3 नेत्र विशेषज्ञ चिकित्सक वर्तमान में प्रतिनियुक्ति के आधार पर कार्यरत हैं । इसके अतिरिक्त अन्य स्वास्थ्यकर्मी यथा 15 नेत्र सहायक तथा 5 नर्स भी पदस्थापित एवं कार्यरत हैं । उपर्युक्त चिकित्सकों एवं स्वास्थ्यकर्मियों द्वारा इस अस्पताल में ऑख से संबंधित मरीजों का इलाज एवं मोतियाबिन्द का ऑपरेशन किया जाता है । राजेन्द्र नगर अतिविशिष्ट नेत्र अस्पताल, पटना में नेत्र रोग से संबंधित और भी बेहतर सेवा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से नियमित चिकित्सकों के अतिरिक्त पदों के सृजन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

अध्यक्ष : आप पूरक पूछिए ।

श्री महानंद सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, ये 125 करोड़ रूपये की लागत से.....

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, ऐसा नहीं, ऐसे आपलोग नहीं बोलिये ।

श्री महानंद सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, ये 125 करोड़ रूपये की लागत से राजेन्द्र नगर में अतिविशिष्ट नेत्र अस्पताल बना है और जैसा कि उत्तर मिला है इसमें करीब 27-28 कर्मचारी वहां डाक्टर समेत रहते है, लेकिन अभी इतना वहां नहीं रहते हैं । मैं मंत्री महोदय से आग्रह करूँगा कि इसकी जॉच करा ली जाय । वहां लोग उपस्थित नहीं रहते हैं । वह बहुत बेहतर नेत्र अस्पताल बना है और जो बाहर लोगों को जाना पड़ता है तो यहां बेहतर तरीके से लोगों का इलाज हो जायेगा । इसकी जॉच करा दी जाय, यह मैं कहना चाहता हूँ । दूसरा कि प्रक्रियाधीन है अतिरिक्त पदों के लिए तो इसको बहुत जल्दी करवाया जाय । अध्यक्ष महोदय, इसके अलावे मैं आपको एक सूचना देना चाहता हूँ कि अरवल जिला के मंझियामा गांव में.....

अध्यक्ष : आपको पूरक पूछना चाहिए ।

श्री महानंद सिंह : दो पूरक मैंने पूछ दिया महोदय ।

अध्यक्ष : पूछ दिया तो अब सरकार का उत्तर तो सुनिये ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव,उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, जवाब में स्पष्ट कर दिया गया है जो इनका सप्लीमेंट्री क्वेश्चन या मूल प्रश्न था कि महज एक-दो डाक्टर हैं उस अस्पताल में जो नेत्र रोग विशेषज्ञ नहीं हैं । जिससे किसी तरह से जनरल इलाज ही होता है ऐसा बिलकुल नहीं है । हमने वस्तुस्थिति अपने उत्तर में स्पष्ट कर दिया है । पत्रांक-554(10), दिनांक-15.11.2011 द्वारा राजेन्द्र नगर अतिविशिष्ट नेत्र अस्पताल, पटना में निदेशक का एक पद है, मुख्य प्रशासी पदाधिकारी का एक पद है और अतिरिक्त शेष चिकित्सकों के सभी पद संविदा के आधार पर सृजित है । उक्त सृजित पदों के विरूद्ध इस संस्थान में एक निदेशक नियमित पद पर पदस्थापित हैं तथा 5 नेत्र कन्सलटेंट अनुबंध पर पदस्थापित हैं । साथ ही इस संस्थान में 3 नेत्र विशेषज्ञ चिकित्सक वर्तमान में प्रतिनियुक्ति के आधार पर कार्यरत हैं । इसके अतिरिक्त अन्य स्वास्थ्यकर्मी यथा 15 नेत्र सहायक तथा 5 नर्स भी पदस्थापित कार्यरत हैं । महोदय, अतिरिक्त पदों के सृजन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है । इस परिप्रेक्ष्य में हम चाहेंगे कि जल्द से जल्द हो ।

श्री महानंद सिंह : महोदय, ये अस्पताल बनने के पहले वहां ज्यादा डाक्टर लोग रहते थे, लेकिन जब से अस्पताल नया बनकर तैयार हुआ है । इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सरकार का जो जवाब आया है । इस जवाब के आलोक में वहां जॉच करा ली जाय, वहां उपस्थिति नहीं रहती है । यह मैं कहना चाहता हूँ ।

अध्यक्ष : स्थान ग्रहण किया जाय ।

श्री महानंद सिंह : एक सूचना है महोदय कि अरवल जिला के मंझियामा गांव जहां यदुनंदन शर्मा की कार्यस्थली रहा है और पुनपुन योजना के.....

अध्यक्ष : आपके इस प्रश्न से इसका.....

श्री महानंद सिंह : सूचना दे रहे हैं महोदय, सूचना है ।

अध्यक्ष : ये सूचना का आवर नहीं है, ये प्रश्नकाल है ।

श्री महानंद सिंह : वे वहां आमरण अनशन कर रहे हैं ये हमिद नगर पुनपुन परियोजना के तहत जो उनकी जमीन का.....

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, सरकार ने आपका उत्तर दे दिया आप स्थान ग्रहण कीजिए ।

तारांकित प्रश्न सं0-1996(श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह)क्षेत्र सं0-194, आरा

(माननीय सदस्य द्वारा प्रश्न नहीं पूछा गया ।)

तारांकित प्रश्न सं0-1997(श्री दिलीप राय)क्षेत्र सं0-26, सुरसंड

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि सीतामढ़ी जिलान्तर्गत सुरसंड प्रखंड के ग्राम मझौरा, पो0-मझौरा, निवासी स्व0 रामबाबू राय की दिनांक 14.09.2014 को विद्युत् स्पर्शाघात से मृत्यु के फलस्वरूप कंपनी के कार्यालय

आदेश सं0-160, दिनांक- 28.01.2015 द्वारा अनुमान्य मुआवजा की राशि दो लाख रूपये मात्र की स्वीकृति प्रदान किया गया, जिसका भुगतान चेक सं0-945351, दिनांक-28.01.2015 द्वारा मृतक की आश्रित पत्नी श्रीमती पवन देवी को किया जा चुका है ।

अध्यक्ष : आप पूरक पूछें ।

श्री दिलीप राय : महोदय, जवाब से संतुष्ट हूँ, धन्यवाद ।

तारांकित प्रश्न सं0-1998(श्री मनोहर प्रसाद सिंह)क्षेत्र सं0-67,मनिहारी

(माननीय सदस्य द्वारा प्रश्न नहीं पूछा गया।)

तारांकित प्रश्न सं0-1999(श्री मिथिलेश कुमार)क्षेत्र सं0-28,सीतामढ़ी

(माननीय सदस्य द्वारा प्रश्न नहीं पूछा गया।)

तारांकित प्रश्न सं0-2000(श्रीमती अरूणा देवी)क्षेत्र सं0-239,वारिसलीगंज

(माननीय सदस्या द्वारा प्रश्न नहीं पूछा गया ।)

तारांकित प्रश्न सं0-2001(श्री रणविजय साहू)क्षेत्र सं0-135,मोरवा

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव,उप मुख्यमंत्री : महोदय, पर्यटन विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 में समस्तीपुर जिलान्तर्गत मोरवा प्रखंड स्थित बाबा केबल स्थान के विकास एवं सौंदर्यीकरण हेतु 361 लाख की योजना स्वीकृत की गयी है । इस योजना के अन्तर्गत यात्री विश्राम गृह, पब्लिक ट्वायलेट ब्लॉक, मिस्लेनियस वर्क, अर्थ फीलिंग एवं लेबलिंग, लैंड स्कीपिंग एवं हॉर्टीकल्चर वाटर सप्लाय एवं पाइप लाइन सिवरेज ड्रेनेज तथा लाइट अधिष्ठापन इत्यादि कार्य किया गया है । यात्री निवास का रख-रखाव प्रबंधक, मंदिर विकास समिति द्वारा किया जा रहा है ।

अध्यक्ष : आप पूरक पूछें ।

श्री रणविजय साहू : अध्यक्ष महोदय, जवाब मुझे प्राप्त हुआ है । माननीय मंत्री जी से हम अनुरोध करना चाहते हैं कि वहां जो पर्यटन विभाग की तरफ से 3 करोड़ 61 लाख रूपये की लागत से यात्री निवास बना और भी तरह की सुविधा जो है उसका रख-रखाव नहीं हो रहा है तो महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से हम जानना चाहते हैं कि विभाग के द्वारा रख-रखाव के लिए सरकार विचार रखती है कि नहीं ?

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव,उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, पर्यटन विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 में समस्तीपुर जिलान्तर्गत मोरवा प्रखंड स्थित बाबा केबल स्थान के विकास एवं सौंदर्यीकरण हेतु 361 लाख की योजना स्वीकृत की गयी है । इस योजना के अन्तर्गत यात्री विश्राम गृह, पब्लिक ट्वायलेट ब्लॉक, मिस्लेनियस वर्क, अर्थ फीलिंग एवं लेबलिंग, लैंड स्कीपिंग एवं हॉर्टीकल्चर वाटर सप्लाय

एवं पाइप लाइन सिवरेज ड्रेनेज तथा लाइट अधिष्ठापन इत्यादि कार्य किया गया है । यात्री निवास का रख-रखाव प्रबंधक, मंदिर विकास समिति द्वारा किया जा रहा है ।

श्री रणविजय साहू : अध्यक्ष महोदय, मेरा पूरक था.....

अध्यक्ष : एक पूरक समय खतम हो गया ।

श्री रणविजय साहू : मेरा पूरक था कि वहां रख-रखाव नहीं हो रहा है, वहां उनके द्वारा रख-रखाव नहीं हो रहा है । इसीलिए हम आग्रह करना चाहते हैं कि विभाग के द्वारा रख-रखाव पर सरकार विचार करेगी ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव,उप मुख्यमंत्री : मंदिर का रख-रखाव मंदिर विकास समिति द्वारा किया जाता है । वैसा होगा तो एक बार हमलोग उसको देखवा लेंगे ।

श्री रणविजय साहू : धन्यवाद मंत्री जी ।

अध्यक्ष : अब प्रश्नोत्तर काल समाप्त हुआ । जिन प्रश्नों के उत्तर तैयार हो उन्हें सदन पटल पर रख दिये जाएं । अब कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना ली जायेगी ।

टर्न–7/पुलकित/17.03.2023

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 17 मार्च, 2023 के लिए निम्न माननीय सदस्यों से कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं :

श्री अरूण शंकर प्रसाद, श्री संजय सरावगी, श्री विजय कुमार खेमका, श्री जनक सिंह, श्री उमाकांत सिंह, विद्या सागर केशरी, डॉ0 निक्की हेम्ब्रम, श्रीमती गायत्री देवी, श्री प्रेम कुमार ।

आज सदन में वित्तीय वर्ष 2023–24 के आय–व्ययक में सम्मिलित अनुदानों की मांग पर वाद–विवाद एवं मतदान का कार्यक्रम निर्धारित है।

अतएव बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम– 172(3) एवं 47(2) के तहत नियमानुकूल नहीं रहने के कारण कार्य स्थगन प्रस्ताव की सभी सूचनाओं को अमान्य किया जाता है ।

अब शून्यकाल लिये जायेंगे ।

<u>शून्यकाल</u>

अध्यक्ष : श्रीमती मंजु अग्रवाल, अपना शून्यकाल पढ़ें ।

श्रीमती मंजु अग्रवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग पटना द्वारा जारी विज्ञापन नं0–06060114 प्रथम इंटर स्तरीय परीक्षा के अंतिम परिणाम के बाद रिक्त पड़े पदों को भरने एवं नियुक्ति पत्र जारी करने की मांग करती हूं ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री इजहारूल हुसैन, अपना शून्यकाल पढ़ें ।

श्री इजहारूल हुसैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, एम0जे0सी0नं0–1059/15, जवाहर लाल झा बनाम बिहार सरकार में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 03.08.2022 के अनुपालनार्थ राज्य के 531 अनुदानित संस्कृत स्कूल एवं 1128 कोटि मदरसा में 15.02.2011 ये पूर्व बहाल शिक्षकों का दिनांक– 01.03.1989 से अबतक का बकाया अन्तर वेतन का भगुतान हेतु राशि आवंटन करने की मांग करता हूं ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री अनिल कुमार ।

(सूचना नहीं पढ़ी गयी)

माननीय सदस्य श्री उमाकांत सिंह ।

(सूचना नहीं पढ़ी गयी)

माननीय सदस्य श्री महा नंद सिंह ।

श्री महा नंद सिंह : अध्यक्ष महोदय, हाईस्कूलों में कम्प्यूटर शिक्षकों की बहाली होने से बच्चों को कम्प्यूटर ज्ञान के अलावे अन्य विषयों की पढ़ाई की गुणवत्ता में सुधार होगा ।

लिहाजा, कम्प्यूटर शिक्षक के लिए एस0टी0ई0टी0 पास सभी अभ्यर्थियों को सातवें चरण में बहाल करने की मांग करता हूं ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्या श्रीमती गायत्री देवी ।

(सूचना नहीं पढ़ी गयी)

माननीय सदस्या डॉ0 निक्की हेम्ब्रम ।

(सूचना नहीं पढ़ी गयी)

माननीय सदस्य श्री विद्या सागर केशरी ।

(सूचना नहीं पढ़ी गयी)

माननीय सदस्य श्री श्यामबाबू प्रसाद यादव ।

(सूचना नहीं पढ़ी गयी)

माननीय सदस्य श्री अरूण शंकर प्रसाद ।

(सूचना नहीं पढ़ी गयी)

माननीय सदस्य श्री धीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ रिंकू सिंह ।

श्री धीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ रिंकू सिंह : अध्यक्ष महोदय, पश्चिम चम्पारण जिलांतर्गत बगहा प्रखण्ड के तिरहुत मेन कैनाल 19 आर0डी0 से लक्ष्मीपुर पुल के बगल से हाईडल नहर पार कर भेड़िहारी माईनर कई वर्षों से जर्जर के कारण वर्मा टोला, भेड़िहारी सहित दर्जनों गांव के किसान सिंचाई से वंचित है । उक्त माईनर का जीर्णोद्धार की सूचना देता हूं ।

श्री अचमित ऋषिदेव : अध्यक्ष महोदय, अररिया जिलान्तर्गत रानीगंज प्रखंड में फरियानी नदी पर कदम घाट में पुल निर्माण करने के लिए मैं सरकार से मांग करता हूं ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री सुनील मणि तिवारी ।

(सूचना नहीं पढ़ी गयी)

माननीय सदस्य श्री कुमार शैलेन्द्र ।

(सूचना नहीं पढ़ी गयी)

माननीय सदस्य श्री संजय सरावगी ।

(सूचना नहीं पढ़ी गयी)

माननीय सदस्य श्री छत्रपति यादव, अपना शून्यकाल पढ़ें ।

श्री छत्रपति यादव : अध्यक्ष महोदय, खगड़िया जिलांतर्गत गोगरी-नारायणपुर तटबंध (जी0एन0 बांध) के माधवपुर-विशनपुर स्थल पर जल जमाव के कारण वहां की स्थिति नरकीय हो गयी है ।

अतः जल-जमाव से मुक्ति हेतु स्लुईस गेट का निर्माण कराने की मांग करता हूं ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री राम सिंह ।

(सूचना नहीं पढ़ी गयी)

माननीय सदस्य श्री रत्नेश सादा ।

श्री रत्नेश सादा : अध्यक्ष महोदय, बिहार के टोला स्वयंसेवकों एवं तालीमरकज का मानदेय 9,680/- है । जिससे परिवार के भरण-पोषण एवं बच्चों की पढ़ाई में कठिनाई हो रही है । जिसके कारण नालन्दा जिला के रामानन्द मांझी ने आर्थिक तंगी के कारण आत्महत्या की ।

अतः टोला स्वयंसेवकों, तालीमरकज का मानदेय बढ़ाने एवं मांझी के परिवार को मुआवजा मिले ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : आप लोग शोर नहीं मचायें । माननीय सदस्या श्रीमती भागीरथी देवी, अपना शून्यकाल पढ़ेंगी ।

(सूचना नहीं पढ़ी गयी)

माननीय सदस्य श्री अजय कुमार ।

श्री अजय कुमार : अध्यक्ष महोदय, समस्तीपुर जिला के विभूतिपुर विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत सिंघियाघाट रेलवे क्रॉसिंग पर रोड ओवर ब्रिज नहीं होने के कारण घंटों जाम की समस्या बनी रहती है एवं आवागमन में काफी कठिनाई होती है ।

मैं सरकार से सिंघियाघाट रेलवे क्रॉसिंग पर रोड ओवर ब्रिज के निर्माण हेतु सरकार से मांग करता हूं ।

श्री गोपाल रविदास : माननीय अध्यक्ष महोदय, नवनियुक्त राजस्व कर्मचारियों पंचायत सचिव एवं ए0एन0एम0 को गृह जिला में पदस्थापित किया जाए तथा शिक्षकों को स्वैच्छिक स्थानान्तरण की सुविधा प्रदान करने की मांग सरकार से करता हूं ।

श्री वीरेन्द्र प्रसाद गुप्ता : माननीय अध्यक्ष महोदय, बेगूसराय में लगातार दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों पर हो रही अत्याचार की घटनाओं में गिरफ्तारी नहीं हो रही है। अति पिछड़ी जाति की महिला के साथ घटित बलात्कार की घटना बलिया थाना कांड-09/2023 के मुख्य अभियुक्त विमल सिंह की गिरफ्तारी की मांग करता हूं ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : इस पर भाषण नहीं करेंगे, आप अपना स्थान ग्रहण करें ।

माननीय सदस्य श्री बीरेन्द्र कुमार ।

(सूचना नहीं पढ़ी गयी)

माननीय सदस्य श्री मोती लाल प्रसाद ।

(सूचना नहीं पढ़ी गयी)

माननीय सदस्य श्री राम रतन सिंह ।

श्री राम रतन सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, बेगूसराय जिला के तेघड़ा विधान सभा अंतर्गत तेघड़ा प्रखंड के पकठौल पंचायत के पासवान टोला वार्ड न0–5 के बांध किनारे पानी टंकी के पास हरिजन सामुदायिक भवन निर्माण कराने की मांग सरकार से करता हूं ।

श्री भरत बिन्द : माननीय अध्यक्ष महोदय, बिहार के पंचायत वार्ड सचिवों से चार साल तक लगातार कार्य कराने के पश्चात् 1,14,690 लोगों को पद से हटा दिया गया जबकि कोरोना काल में इन लोगों की भूमिका सराहनीय रही है ।

अतः उक्त सभी पंचायत वार्ड सचिवों को पुनः पद पर रखने की सरकार से मांग करता हूं ।

श्री राजेश कुमार गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, रोहतास जिला के मोची टोला सासाराम में मो0 बबलू राईन के 05 साल का बच्चा ऐहसान कैंसर पीड़ित था, दिल्ली में मृत्यु उपरांत परिवार के सदस्यों में माता, दादी, बुआ सहित पांच लोगों की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गयी । पीड़ित परिवार को एक नौकरी के साथ मुआवजा उपलब्ध करावें ।

टर्न–8/अभिनीत/17.03.2023

श्री ललित नारायण मंडल : अध्यक्ष महोदय, भागलपुर जिले के सुल्तानगंज प्रखंड में स्थित कन्या विद्यालय, करहरिया के जर्जर भवन के पुनर्निर्माण की मांग करता हूं ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री जय प्रकाश यादव ।

(सूचना नहीं पढ़ी गयी)

माननीय सदस्य श्री अजीत कुमार सिंह ।

श्री अजीत कुमार सिंह : महोदय, डुमरांव निवासी श्री कन्हैया सिंह के पुत्र एवं जवाहर नवोदय विद्यालय, धूम मानिकपुर, उत्तर प्रदेश के कक्षा 9वीं के छात्र पंकज कुमार अपने विद्यालय से ही दिनांक– 12.04.2022 से लापता हैं । लापता छात्र पंकज कुमार की शीघ्र बरामदगी हेतु कार्रवाई करने की मांग करता हूं ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री पवन कुमार जायसवाल ।

(सूचना नहीं पढ़ी गयी)

माननीय सदस्य श्री मुरारी मोहन झा ।

(सूचना नहीं पढ़ी गयी)

माननीय सदस्य श्री अरूण सिंह ।

श्री अरूण सिंह : महोदय, किसान बागमती बचाओ संघर्ष समिति बनाकर लंबे समय से आंदोलन चला रहे हैं । 2017 में सरकार रिव्यू कमेटी बनाई थी । रिपोर्ट के आधार पर बांध बांधने का निर्णय था । बिना रिपोर्ट आये कार्य का ओदश दे दिया गया है। रिपोर्ट के आधार पर बांध बांधने की मांग करता हूं ।

श्री मुकेश कुमार यादव : महोदय, सीतामढ़ी जिलांतर्गत 27 वाजपट्टी विधान सभा क्षेत्र में तीन प्रखंड वाजपट्टी, नानपुर, बोखड़ा में एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है ।

अतः नानपुर प्रखंड में एक डिग्री कॉलेज खोलने की मांग सरकार से करता हूं ।

श्री अमरजीत कुशवाहा : महोदय, सिवान जिलांतर्गत प्रखंड-मैरवा के लक्ष्मीपुर फ्लाई ओवर पर दिनांक- 16.03.2023 को सड़क दुर्घटना में 3 दलित नौजवानों की दर्दनाक मौत हो गयी । मृतकों के आश्रितों को तत्काल 5-5 लाख मुआवजा, आवास तथा परिवार के एक-एक सदस्य को नौकरी देने की मांग करता हूं ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य डॉ0 रामचन्द्र प्रसाद ।

(सूचना नहीं पढ़ी गयी)

माननीय सदस्य श्री संदीप सौरभ ।

श्री संदीप सौरभ : अध्यक्ष महोदय, पटना जिलांतर्गत पालीगंज प्रखंड में आबकारी विभाग द्वारा शराबबंदी कानून के नाम पर गरीबों-दलितों से दुर्व्यवहार, मार-पीट, अवैध वसूली तथा बेगुनाहों को शराब बेचने के असत्य केस में फंसाने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं ।

लोगों की प्रताड़ना रोकने तथा जांच व उचित कार्रवाई की मांग करता हूं।

श्री सुर्यकांत पासवान : महोदय, बेगूसराय जिलांतर्गत बखरी अनुमंडल की स्थापना के 28 वर्षों बाद भी अनुमंडलीय अस्पताल की स्थापना नहीं हो सकी है जिसके कारण लोगों को बेहतर इलाज के लिए 40 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है ।

अतः बखरी में अनुमंडलीय अस्पताल बनाने की मांग सरकार से करता हूं।

श्री भूदेव चौधरी : महोदय, बांका जिलांतर्गत धोरैया प्रखंड के चन्द्रपुरा एवं सिंगारपुर गांव के बीच राज डॉढ़ में तथा धोपसंडा एवं चन्द्रपुरा के रकौली जोर में बना पुल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है जिससे दर्जनों गांवों का आवागमन बाधित है । क्षतिग्रस्त पुल का जीर्णोद्धार कराने की मांग सरकार से करता हूं ।

श्री रामबली सिंह यादव : महोदय, जहानाबाद जिला के हुलासगंज प्रखंड अंतर्गत गिदरपुर के पास नहर से बौरी आहर होकर बेनीचक तक जाने वाली सड़क निर्माण शुरू होकर दो वर्षों से बाधित है । इसे शीघ्र पूरा कराने की मांग करता हूं ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री प्रणव कुमार ।

(सूचना नहीं पढ़ी गयी)

माननीय सदस्य श्री सतीश कुमार ।

श्री सतीश कुमार : महोदय, 2 अप्रैल, 2018 को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अत्याचार अधिनियम में किये गये बदलाव सी0ए0, एन0आर0सी0, एन0पी0आर0 व अग्निपथ योजना के खिलाफ सरकार द्वारा किये गये तमाम एफ0आई0आर0 को सदन के माध्यम से वापस लेने की मांग करता हूं ।

श्री मनोज मंजिल : महोदय, शिक्षा सेवक जनशिक्षा में महादलित, दलित एवं अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चे-बच्चियों को पढ़ाने के साथ-साथ सरकार के कार्यों में अपना योगदान देते हैं, शिक्षा सेवकों को नियोजित शिक्षक का दर्जा देते हुए नियमित वेतनमान देने की मांग करता हूं ।

श्री महबूब आलम : महोदय, मलेरिया अन्मूलन अभियान अंतर्गत पिछले 40 साल से डी0डी0टी0 छिड़काव कर्मी तप्ती हुई धूप में सुदूर देहातों में अपनी जान जोखिम में डालकर जनता की सेवा करते आ रहे हैं । मैं उन्हें स्वास्थ्य विभाग में सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने की मांग करता हूं ।

श्री रामवृक्ष सदा : महोदय, खगड़िया जिला के अलौली प्रखंड के गोरियाभी पंचायत स्थित महादलित के रविदास टोला सझौती से काजीजाम होते हुए भिरोरिया मुसहरी महादलित टोला तक सड़क निर्माण की मांग करता हूं ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री प्रेम कुमार ।

(सूचना नहीं पढ़ी गयी)

माननीय सदस्य श्री ललन कुमार ।

(सूचना नहीं पढ़ी गयी)

माननीय सदस्य श्री मोहम्मद अंजार नईमी ।

श्री मोहम्मद अंजार नईमी : महोदय, शुगर मरीजों की संख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है । सदर हॉस्पिटल के अतिरिक्त डायलेसिस की व्यवस्था अन्य किसी हॉस्पिटल में नहीं है । निर्धन परिवारों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है ।

मैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में डायलेसिस तथा ऑपरेटर की व्यवस्था कराने की मांग करता हूं ।

श्री विजय कुमार : महोदय, आशा फैसिलेटर को मात्र 6 हजार रुपये मानदेय है जबकि इन लोगों को दूर-दूर क्षेत्र में जाना पड़ता है । न्यूनतम मजदूरी भी इससे अधिक है ।

अतः आशा फैसिलेटर के काम के महत्व को देखते हुए इनका मानदेय कम-से-कम 15 हजार रुपये किये जाने की मांग करता हूं ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री कुंदन कुमार ।

(व्यवधान)

माननीय सदस्यगण, आपलोग मोबाईल खोलकर न रखें । अगर आप मोबाईल देखते हैं तो यह गलत है । बंद रखिये, यह नियम के विरूद्ध है ।

माननीय सदस्य श्री कुंदन कुमार ।

(सूचना नहीं पढ़ी गयी)

माननीय सदस्य श्री राम विशुन सिंह ।

श्री राम विशुन सिंह : महोदय, भोजपुर जिलांतर्गत जगदीशपुर विधान सभा क्षेत्र के जगदीशपुर प्रखंड में अंगरूआ एवं पीरो प्रखंड में जितौरा ग्राम में एक-एक महिला कॉलेज खोलने की सरकार से मांग करता हूं । दोनों ग्रामों में पर्याप्त सरकारी जमीन उपलब्ध है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : ऐसी स्थिति में ही कार्रवाई होती है तो माननीय सदस्यों को लगता है कि कार्रवाई हो रही है । नेता प्रतिपक्ष बैठे हुए हैं, आजतक मैंने नहीं देखा कि सदन में मोबाईल का उपयोग किया जाता हो । यह नियम के बिल्कुल विरूद्ध है, ये लोग बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली का पालन करने के लिए तैयार नहीं है । यह बहुत गलत बात है, सदन के अंदर मोबाईल का उपयोग कभी नहीं हुआ है ।

माननीय सदस्य श्री विनय बिहारी ।

(सूचना नहीं पढ़ी गयी)

माननीय सदस्य श्री जनक सिंह ।

(सूचना नहीं पढ़ी गयी)

टर्न-9/हेमन्त/17.03.2023

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री राजेश कुमार ।

श्री राजेश कुमार : अध्यक्ष महोदय, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री स्वर्गीय दिलकेश्वर राम दलित, शोषित की आवाज थे । उन्होंने औरंगाबाद के विभिन्न क्षेत्रों का विधान सभा में अनेकों बार प्रतिनिधित्व किया । मैं नयी पीढ़ी को उनकी कृतियों से परिचित कराने के लिए औरंगाबाद शहर में उनकी प्रतिमा की स्थापना की मांग सरकार से करता हूं।

श्री संजय कुमार गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, शिवहर जिलान्तर्गत तरियानी प्रखंड में नरवार एवं सरीफ नगर पंचायत में ओलावृष्टि से घर एवं फसल बर्बाद हो गये हैं ।

बर्बाद घर एवं फसल की क्षतिपूर्ति की मांग सरकार से करता हूं ।

श्री सुदामा प्रसाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, सदर अस्पताल आरा के जांच घर में एक माह से बंद सीवीसी जांच मशीन को शीघ्र चालू करवाया जाय ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री पवन कुमार यादव ।

(सूचना नहीं पढ़ी गयी)

माननीय सदस्या श्रीमती रश्मि वर्मा ।

(सूचना नहीं पढ़ी गयी)

अब ध्यानाकर्षण सूचनाएं ली जायेंगी ।

ध्यानाकर्षण सूचनाएं तथा उस पर सरकारी वक्तव्य

सर्वश्री अजय कुमार, सुदामा प्रसाद एवं अन्य सात सभासदों से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना तथा उस पर सरकार (कृषि विभाग) की ओर से वक्तव्य ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री अजय कुमार अपनी सूचना को पढ़ें ।

श्री अजय कुमार : ''माननीय अध्यक्ष महोदय, बिहार आलू उत्पादन में उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल के बाद तीसरे स्थान पर आता है । राज्य में मुजफ्फरपुर, नालंदा, समस्तीपुर, बेगूसराय, वैशाली, पटना, छपरा सहित अन्य जिलों में भी इस वर्ष आलू की उपज ठीक हुई है । राज्य में आलू उत्पादन के अनुरूप कोल्ड स्टोरेज नहीं होने से आलू का रख-रखाव महंगा हो गया है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष: आप स्थान ग्रहण करें । अभी ध्यानाकर्षण सूचना पढ़ी जा रही है । कृपया आप स्थान ग्रहण करें ।

श्री अजय कुमार : किसानों को उर्वरक के साथ नैनो यूरिया खरीदने, डीएपी समेत सभी कीटनाशकों की कीमत बढ़ने से कृषि लागत पूंजी करीब दोगुनी बढ़ गयी है जिससे किसानों की आय बढ़ने की बजाय घट गई है । आलू के दामों में हो रही गिरावट एवं बाजार उपलब्ध नहीं होने से किसानों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है । सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य तय नहीं करने के कारण किसानों को उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है, जबकि केरल में हरी साग-सब्जियों एवं आलू का न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू है ।

अत: किसानों के हित में पीड़ित किसानों को मुआवजा देने एवं आलू का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने हेतु हम सदन मे माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।''

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, कृषि विभाग ।

श्री कुमार सर्वजीत, मंत्री : महोदय, बिहार राज्य में 3.30 लाख हेक्टेयर में आलू की खेती होती है जिसमें 91.25 लाख मे0टन आलू का उत्पादन होता है । महोदय, बिहार राज्य में कुल 314 कोल्ड स्टोरज हैं जिसमें वर्तमान में 197 कोल्ड स्टोरज कार्यरत हैं । जिसकी भंडारण क्षमता 18.68 लाख मे0टन है । कोल्ड स्टोरेज इकाई टाईप-1 एकल तापमान क्षेत्र सहायता अनुदान परियोजना लागत मूल्य का 8 हजार प्रति मे0टन अधिकतम 5 हजार मे0टन क्षमता कोल्ड स्टोरेज निर्माण हेतु कुल लागत का 4 करोड़, एक व्यक्ति को 50 प्रतिशत अर्थात् 2 करोड़ रुपये का कृषक उत्पादन संगठन, एफ0पी0ओ0 कृषक उत्पादक कंपनी एफ0पी0सी0 को इकाई लागत कुल 4 करोड़ का 75 प्रतिशत अधिकतम 3 करोड़ मात्र के क्रेडिट लिंक बैंक इंडियन सहायता अनुदान दिये जाने का प्रावधान है । महोदय, कोल्ड स्टोरेज इकाई टाईप-2 मल्टी सहायता अनुदान परियोजना लागत का 1000 प्रति मे0टन अधिकतम 5 हजार मे0टन क्षमता कोल्ड स्टोरेज निर्माण हेतु कुल लागत 5 करोड़, एक व्यक्ति को 50 प्रतिशत अर्थात् 2 करोड़ 50 लाख एवं कृषक उत्पादक संगठन, कृषक उत्पादक कंपनी को इकाई लागत का कुल 5 करोड़ रुपये का 75 प्रतिशत अधिकतम 3 करोड़ 75 लाख मात्र के क्रेडिट लिंक बैंक इंडियन सहायता अनुदान देने का प्रावधान है । अब तक इस योजना के तहत कुल 34 कोल्ड स्टोरेज क्षमता 1.57 लाख मे0टन के लिए सहायता अनुदान दिया गया है । आलू जल्द ही नष्ट होने वाली फसल है जिसके भंडारण हेतु सरकार के पास कोल्ड स्टोरेज का प्रावधान नहीं है । जिसके कारण बिहार राज्य में न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू नहीं किया जा सकता है । आलू फसल क्षति होने पर आपदा प्रबंधन विभाग की मार्गदर्शिका के अनुरूप इनपुट सब्सिडी दिये जाने का प्रावधान है । आलू के मूल्य में कमी होने पर इसका मुआवजा देने का कोई प्रावधान नहीं है ।

अध्यक्ष : माननीय प्रश्नकर्ता ।

श्री अजय कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इस बार आलू की उपज कितनी होने की संभावना है और जितनी आलू की उपज होने की संभावना है, क्या उसके रख-रखाव की कोई व्यवस्था सरकार करना चाहती है अथवा नहीं ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ने तो जवाब दिया है ।

श्री कुमार सर्वजीत, मंत्री : महोदय, मैंने माननीय सदस्य को बताया, चूंकि आलू जल्द नष्ट हो जाता है । ऐसे धान, गेंहू सहकारिता से मिलकर बिहार सरकार अपने स्टोरेज की व्यवस्था रखती है । लेकिन आलू का स्टोरेज इसलिए नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वह जल्द खराब हो जाता है । बाकी जो किसान हैं, जिनको अपना कोल्ड

स्टोरेज चाहिए होता है, उसके लिए तो हमने सब्सिडी की व्यवस्था रखी ही है कि जो किसान बनाना चाहते हैं, हमारे यहां उसकी व्यवस्था है, लेकिन सरकार की तरफ से इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है, चूंकि आलू तुरंत नष्ट हो जाता है । इसलिए उतने उत्पादन का कोल्ड स्टोरेज बनाना संभव नहीं है ।

श्री अजय कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि कोल्ड स्टोरेज निर्माण में सरकार अनुदान देती है और सरकार ने बिजली की दर में कोई वृद्धि नहीं की है, लेकिन बिजली की दर में वृद्धि हुए बगैर इस बार पूरे बिहार में कोल्ड स्टोरेज मालिक ने तकरीबन 20 रुपये से 50 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की है । क्या सरकार उसके बारे में, कोल्ड स्टोरेज मालिक के साथ और किसान के बीच में बैठकर कोई नीतिगत निर्णय लेकर कोई फैसला करना चाहती है कि नहीं ?

श्री कुमार सर्वजीत, मंत्री : महोदय, जो बिजली विभाग होता है, इंडस्ट्री का क्या रेट होगा, घर में जो यूज होगा, इसका अपना बहुत तरीके का अपना नियम-कानून है और अगली बार जब उसमें लायेंगे, तो उसमें विद्युत विभाग अपना जवाब देगा, यह तो कृषि विभाग से संबंधित नहीं है ।

अध्यक्ष : अभी न्यूनतम समर्थन देने की कोई व्यवस्था नहीं है । माननीय सदस्य, अपना स्थान ग्रहण करें ।

माननीय सदस्य डॉ0 संजीव कुमार अपनी सूचना को पढ़ें ।

डॉ0 संजीव कुमार, श्री राजेश कुमार सिंह एवं अन्य ग्यारह सभासदों से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना तथा उस पर सरकार (स्वास्थ्य विभाग) की ओर से वक्तव्य ।

डॉ0 संजीव कुमार : ''माननीय अध्यक्ष महोदय, NIOS (National Institute of Open Schooling) मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार का एक उपक्रम है । इसके तहत Biology 10+2 के छात्रों के लिए.....

अध्यक्ष : माननीय संजीव बाबू, जरा एक मिनट । माननीय अजय बाबू कुछ कह रहे हैं ।

श्री अजय कुमार : महोदय, मेरा कहना है कि किसान के आलू उत्पादन पर लागत खर्च बढ़ गया है और इस बार जो लागत खर्च बढ़ा है वह प्रति एकड़ 30 हजार से लेकर 35 हजार रुपये प्रति एकड़ लागत खर्च है...

अध्यक्ष : पूरक पूछिये, समय नहीं है ।

श्री अजय कुमार : महोदय, मैं पूरक ही पूछ रहा हूँ । आलू उत्पादन में सिर्फ जो है 20 हजार रुपये प्रति एकड़ आया है, तो हम सरकार से जानना चाहते हैं कि आपने जिस तरह न्यूनतम समर्थन मूल्य गेहूँ और धान पर लागू किया है, क्या केरल में जिस तरह से हरी सब्जी और आलू पर न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार लागू किये हुए है, बिहार में आलू पर भी न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू करना चाहती है या नहीं ?

अध्यक्ष : इन्होंने तो कह ही दिया कि इस तरह की व्यवस्था नहीं है ।

श्री कुमार सर्वजीत, मंत्री : महोदय, मैं इनका सिर्फ एक लाईन में जवाब दे देता हूँ । इन्होंने कहा है कि डी॰ए॰पी॰, यूरिया, नैनो इसकी कीमत बहुत ज्यादा है इसलिए किसान को, महोदय, इसका रेट जो है यह बिहार सरकार तो निर्धारित नहीं करती है, यह तो केन्द्र सरकार निर्धारित करती है । अभी मैंने कहा, अगर माननीय सदस्य का कहना है कि केरल में इस तरह की व्यवस्था है, तो मैं इनको आश्वासन देता हूँ कि हमारे अधिकारी केरल जायेंगे, जाकर देखेंगे, महोदय, नेचर ऑफ लैंड का भी तो मामला है, वहाँ किस तरह का नेचर ऑफ लैंड है, यहाँ कैसा है । महोदय, अधिकारी जायेंगे, देखेंगे, अगर उचित होगा तो हमारी सरकार किसान के लिए तो चिंतित है ही ।

अध्यक्ष : आपने प्रोपर जवाब दे दिया है । स्थान ग्रहण कीजिये ।

माननीय सदस्य डॉ॰ संजीव कुमार जी । एक मिनट सुनिये, चूंकि समय नहीं है...

डॉ0 संजीव कुमार : महोदय, सिर्फ एक मिनट लगेगा, बस एक मिनट...

अध्यक्ष : यह ध्यानाकर्षण आपका जीवित रहेगा, आप इस चीज को, अगली तिथि को आपसे पढ़वाया जायेगा और सरकार जवाब देगी । आप बैठ जाइये ।

डॉ॰ संजीव कुमार : धन्यवाद महोदय ।

<u>सभा मेज पर कागजात का रखा जाना</u>

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, ऊर्जा विभाग ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 395 के तहत साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के वित्तीय वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सदन के पटल पर रखता हूँ।

अध्यक्ष : अब सभा की कार्यवाही 2.00 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है ।

टर्न-10/धिरेन्द्र/17.03.2023

(अंतराल के बाद)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, हमलोग माँग किये थे कि सरकार जवाब दे । माननीय मंत्री जी को सारा डॉक्यूमेंट उपलब्ध कराया गया है, उन्होंने कहा था कि इसको हम संज्ञान में लेते हैं । माननीय मंत्री इसराईल मंसूरी जी पर आरोप लगा है । आज उसको धमकी भी मिली है, वह पत्र दिया है थाना के अंदर, क्या इस पर कार्रवाई हुई, एफ॰आई॰आर॰ हुआ, जिनको मंत्री...

अध्यक्ष : स्थान ग्रहण किया जाय ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : महोदय, सुन लिया जाय और महोदय...

अध्यक्ष : अब वित्तीय कार्य लिये जायेंगे ।

<u>वित्तीय कार्य</u>

माननीय सदस्यगण, ऊर्जा विभाग के अनुदान की मांग पर वाद-विवाद तथा सरकार का उत्तर एवं मतदान होगा । इसके लिए 3 घंटे का समय उपलब्ध है। विभिन्न दलों को उनकी सदस्य संख्या के आधार पर समय का आवंटन निम्न प्रकार किया जाता है, इसी समय में से सरकार को उत्तर के लिए भी समय दिया जायेगा:

राष्ट्रीय जनता दल	-	58 मिनट
भारतीय जनता पार्टी	-	58 मिनट
जनता दल यूनाइटेड	-	33 मिनट
इंडियन नेशनल कांग्रेस	-	14 मिनट
सी॰पी॰आई॰ (एम॰एल॰)	-	09 मिनट
हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा	-	03 मिनट
सी॰पी॰आई॰(एम॰)	-	02 मिनट
सी॰पी॰आई॰	-	02 मिनट
ए॰आई॰एम॰आई॰एम॰	-	01 मिनट

माननीय मंत्री, ऊर्जा विभाग । अपनी माँग प्रस्तुत करें ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''ऊर्जा विभाग के संबंध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए

115,36,83,67,000/- (एक सौ पंद्रह अरब छत्तीस करोड़ तिरासी लाख सड़सठ हजार) रुपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय ।''

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है ।

अध्यक्ष : इस मांग पर माननीय सदस्य श्री संजय सरावगी, श्री कुमार शैलेन्द्र, श्री अरूण शंकर प्रसाद, श्री जनक सिंह, श्री अखतरूल ईमान एवं डॉ॰ सी॰ एन॰ गुप्ता से कटौती प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं । ये सभी व्यापक हैं जिसपर सभी माननीय सदस्य विचार-विमर्श कर सकते हैं । माननीय सदस्य श्री संजय सरावगी जी का प्रस्ताव प्रथम है ।

अतएव माननीय सदस्य श्री संजय सरावगी अपना कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करें ।

श्री संजय सरावगी : माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार की ऊर्जा नीति पर विचार-विमर्श करने हेतु मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''इस शीर्षक की मांग 10/- रुपये से घटायी जाय ।''

अध्यक्ष महोदय, ऊर्जा विभाग का कुल 11,536.34 करोड़ रुपये का बजटीय उपबंध है, वर्ष 2023-24 के लिए माननीय मंत्री जी ने रखा है लेकिन स्कीम मद में मात्र 1586.52 करोड़ रुपये रखा गया है जो कुल बजट का 13 प्रतिशत के आस-पास है । अध्यक्ष महोदय, यह निराशाजनक है क्योंकि स्कीम मद में अगर प्रावधान बिना किए न तो संरचना व्यवस्था में सुधार लाया जा सकता है और न ही वितरण सहीत आधारभूत संरचना में सुधार लाया जा सकता है, इसलिए यह बहुत कम है और अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2005 के पहले लालटेन लेकर घूम रहे थे। अध्यक्ष महोदय, यह मैं मानता हूँ कि बिजली में कुछ सुधार हुआ है लेकिन फिर से जो लालटेन लेकर घूम रहे हैं, अब लालटेन युग आने वाला नहीं, इसलिए लालटेन लेकर फिर जो घूम रहे हैं और बिहार में जो व्यवस्था बिगाड़ रहे हैं, वह युग आने वाला नहीं है । अध्यक्ष महोदय, पूरे बिहार में जो बिजली है, वह केन्द्र की अनुकम्पा पर चल रही है, नरेन्द्र मोदी जी के सरकार की अनुकम्पा पर चल रही है क्योंकि बिहार का बिजली उत्पादन के लिए खुद का न कोई प्लांट है और न यूनिट है, एक सिंगल यूनिट बिजली का भी उत्पादन बिहार राज्य में खुद से नहीं करते हैं, यह सब केन्द्र की अनुकम्पा से हो रही है । वही कहावत है-

माल महाराज का और मिर्जा खेले होली ।

अध्यक्ष महोदय, नरेन्द्र मोदी जी को धन्यवाद इस सरकार को देना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, बिहार में...

(व्यवधान)

फिर देखिये, महोदय, मेरा समय बर्बाद कर रहे हैं । हम कितना शांति से सुनते हैं...

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप अपना पक्ष रखें ।

श्री संजय सरावगी : अध्यक्ष महोदय, बिहार का एवरेज पॉवर डिमांड 6,000 मेगावाट के आस-पास है लेकिन केन्द्र द्वारा बिहार को 6,280 मेगावाट उपलब्ध करायी जा रही है और बिहार में दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना हो या एकीकृत विद्युत विकास योजना हो, सौभाग्य योजना हो के माध्यम से डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए भारत सरकार ने 23,647 करोड़ रुपये की परियोजना को मंजूरी दी है अध्यक्ष महोदय, लेकिन बिहार में लगातार बिजली का रेट आम गरीब जनता पर बोझ बना रहता है और...

(व्यवधान)

डिस्टर्ब कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय, पढ़े-लिखे लोग हैं और तब जो अध्यक्ष महोदय..

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, शांति बनाये रखें ।

श्री संजय सरावगी : अध्यक्ष महोदय, मैं एक आँकड़ा देख रहा था, बिहार में ए॰टी॰ एण्ड सी॰ लॉस जो है तकनीकी नुकसान एवं व्यापारिक नुकसान, अध्यक्ष महोदय, कुल नुकसान पूरे देश में लगभग 15 प्रतिशत है मगर बिहार में लगभग 30 प्रतिशत जो है कुल तकनीकी नुकसान, संरचना नुकसान, व्यापारिक नुकसान जो ए॰टी॰ एण्ड सी॰ लॉस है, वह सबसे ज्यादा है और इसका सीधा-सीधा भार बिहार की गरीब जनता पर पड़ रहा है । अध्यक्ष महोदय, मैं एक आँकड़ा देख रहा था, बिहार में बिजली खरीदी गई 34,200 मिलियन यूनिट और पैसा मिला मात्र 21,256 मिलियन यूनिट का, मतलब 13,000 मिलियन यूनिट से ऊपर जो यह तकनीकी एवं व्यापारिक नुकसान हुआ है जिसके कारण बार-बार, वर्ष 2015-16 में मैं देख रहा था दोनों जो हमारी बिजली आपूर्ति कंपनियों ने विनियामक आयोग को कहा था कि वर्ष 2019-20 तक बिजली नुकसान का राष्ट्रीय मानक जो 15 परसेंट तक है वह लाने का भरोसा दिया था लेकिन अध्यक्ष महोदय, अभी-अभी मैंने आँकड़ा बताया लगभग 30 परसेंट है और इसका सीधा-सीधा भार बिहार की जनता पर पड़ रहा है, इसको माननीय मंत्री जी को बताना चाहिए, जब आपकी पॉवर कंपनियों ने विनियामक आयोग को, तभी विनियामक आयोग ने दर बढ़ाने की स्वीकृति दी थी । अध्यक्ष महोदय, विनियामक आयोग ने एश्योरेंस किया था कि वर्ष 2019-20 तक हम कर देंगे जो राष्ट्रीय मानक है 15-15.5 परसेंट, वे नहीं कर सकें, जिसका पूरा-पूरा भार गरीब जनता पर पड़ रहा है । अध्यक्ष महोदय, ये कंपनियाँ जो हैं नुकसान के नाम पर विनियामक आयोग के दवाब पर, हमारी बिजली दर बढ़ानी चाहिए और मंत्री जी

भी कह देते हैं कि पब्लिक डोमिनेंट में चर्चा होगी । अध्यक्ष महोदय, पब्लिक डोमिनेंट में क्या चर्चा होती है ? जो पदाधिकारी चाहते हैं, अगर वर्ष 2019-20 में आपने कहा और आज वर्ष 2022-23 हो गया, उसके बाद भी आज लगभग मैं देख रहा था 7750.50 करोड़ रुपये की बिजली नुकसान हो रही है, यह भार जो है आम गरीब जनता पर पड़ रहा है । अध्यक्ष महोदय, अभी हाल में माननीय मुख्यमंत्री जी समाधान यात्रा में गये या व्यवधान यात्रा में, यह तो बिहार की जनता जानती है । अध्यक्ष महोदय, वहाँ भी मुख्यमंत्री जी को गरीब उपभोक्ताओं ने लाखों-करोड़ों की बिजली बिल आने की शिकायत की । माननीय मंत्री जी को बताना चाहिए कि मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया कि गाँव में जाकर आप बिजली बिल का सर्वे कीजिये, क्यों बिजली बिल गलत आ रही है । बताना चाहिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब निर्देश दिया, इस तीन-चार महीने में कितनी जगह इन बिजली बिलों की जाँच हुई? अध्यक्ष महोदय, मैं पेपर कटिंग देख रहा था, किसान को भेजा एक माह का बिजली बिल 1 करोड़ रुपये का, और इसके जड़ में माननीय मंत्री जी को, विभाग के अधिकारी को जाना चाहिए था । अध्यक्ष महोदय, बिहार में, मैं एक आँकड़ा देख रहा था, उपभोक्ताओं को बिना मीटर रीडिंग के बिल मिल रहा था, 45 परसेंट उपभोक्ता को बिना मीटर रीडिंग के एवरेज कर बिजली बिल मिल रहा था और यह देश में सबसे ज्यादा है...

...क्रमशः...

टर्न-11/संगीता/17.03.2023

(क्रमशः)

श्री संजय सरावगी : छत्तीसगढ़ में 75 परसेंट मतलब रीडिंग के लिए बिल मिल रहा है, पांडिचेरी में 74, उड़ीसा में, मतलब बिहार में मात्र 45 परसेंट क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे, कितने आप पी0पी0पी0 मोड में लोगों को रखे हुए हैं, क्यों अभी तक 42 परसेंट लोगों को जो है बिना मीटर रीडिंग के बिजली मिल रहा है 43 परसेंट को यह माननीय मंत्री जी को जवाब देना चाहिए जिसके कारण और मैं बराबर देखता हूं विधान सभा में अध्यक्ष महोदय, बराबर माननीय सदस्य प्रश्न उठाते हैं कि अमुक गांव के अमुक बी0पी0एल0 परिवार को 20 हजार, 25 हजार, 30 हजार, 8 लाख, 9 लाख तक का मेरे क्षेत्र में भी अध्यक्ष महोदय, मैंने कई बार शिकायत की है लेकिन आज तक यह एक तरह से भ्रष्टाचार इस माध्यम से हो रहा है अध्यक्ष महोदय, और गरीब लोग जाकर बिजली विभाग के पदाधिकारियों को लाइन लगाकर रखते हैं अध्यक्ष महोदय, हमारा बिजली बिल ठीक कर दीजिए इसके अंदर लाल

फीताशाही है तो यह आंकड़ा जो 45 परसेंट उपभोक्ताओं को बिना मीटर रीडिंग मिल रहा है अध्यक्ष महोदय बिल, क्या माननीय मंत्री जी इस विधान सभा को कुछ आश्वासन देना चाहते हैं कि कब तक जो है इसको 100 परसेंट लोगों को जब मीटर, जब मीटर आपने लगा दिया अध्यक्ष महोदय तो क्यों एवरेज के नाम पर गरीब को प्रताड़ित किया जा रहा है अध्यक्ष महोदय ? और अध्यक्ष महोदय, एक और मैं आंकड़ा देख रहा था बिहार की बिजली कंपनियों का प्रदर्शन पिछले साल से खराब । अध्यक्ष महोदय, यह आंकड़ा भारत सरकार जारी कर रही है, ऊर्जा मंत्रालय ने देश की 52 सरकारी बिजली कंपनियों की रेटिंग जारी की है अध्यक्ष महोदय और 2012 से जारी हो रहा है, 2012 से बिहार सरकार संतुष्ट थी, हो सकता है इस बार कहे कि नहीं हम इस रेटिंग से संतुष्ट नहीं हैं क्योंकि इस बार इतनी खराब रेटिंग अगस्त, 2022 में हुई है मैं एक आंकड़ा पढ़कर इसका भी सुनाना चाहता हूं । अगस्त, 2015 में अध्यक्ष महोदय, नॉर्थ बिहार देश में 11वें स्थान पर था और साउथ बिहार 23वें स्थान पर था, ऐसे ही 2019 में नॉर्थ बिहार 22वें स्थान पर था और साउथ बिहार 25वें स्थान पर था और अगस्त, 2022 में जो अंतिम रेटिंग आई अध्यक्ष महोदय, आपको जानकर आश्चर्य होगा मंत्री जी जो पीठ थपथपा लें, बिहार सरकार जो पीठ थपथपा ले अध्यक्ष महोदय, नॉर्थ बिहार बिजली कॉरपोरेशन का रेटिंग 52 में 34वें स्थान पर है और साउथ बिहार का रेटिंग बिजली विभाग का महोदय 39वें स्थान पर है अध्यक्ष महोदय, यह माननीय मंत्री जी को बताना चाहिए कि इतनी रद्दी स्थिति बिहार की पॉवर रेटिंग के मामले में कंपनियों की हमारी इतनी खराब स्थिति और यह बता दूं अध्यक्ष महोदय, बिहार की स्थिति कंपनियों की 85 से 100 अंक जो आता है उसको ए-प्लस मतलब उत्कृष्ट, 65 से 85 आता है तो ए मतलब अच्छा, 50 से 65 में बी-प्लस मध्यम, 35 से 50 में बी औसत, 15 से 35 में सी खराब और 0 से 15 सी-माइनस में सबसे खराब तो बिहार के बिजली कंपनियों की रेटिंग महोदय सी-माइनस है मतलब सबसे खराब है, क्यों ऐसी स्थिति बिहार के बिजली कंपनियों की हो गई है अध्यक्ष महोदय, ये बताना चाहिए अध्यक्ष महोदय । अध्यक्ष महोदय, मैं एक आंकड़ा देख रहा था, पटना में सरकारी भवनों पर जो राशि बाकी है अध्यक्ष महोदय...

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, सरावगी जी ।

श्री संजय सरावगी : जी ।

अध्यक्ष : आपके ही दल द्वारा आपको मात्र 12 मिनट ही बोलने के लिए दिया गया है...

श्री संजय सरावगी : अध्यक्ष महोदय, आप कुछ बढ़ा दीजिए अपनी तरफ से अध्यक्ष महोदय, अब हम पहले वक्त...

अध्यक्ष : मैं तो नहीं बढ़ा सकता...

श्री संजय सरावगी : प्रस्ताव है अध्यक्ष महोदय, जो आपका आदेश होगा अध्यक्ष महोदय...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : तब क्या 13 मिनट, 13 मिनट इनको...

श्री जनक सिंह : सबमें से एक-एक मिनट काटकर इनको दे दिया जाय अध्यक्ष महोदय ।

श्री नन्द किशोर यादव : अध्यक्ष महोदय, 5 मिनट और दे दीजिए इनको ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

श्री संजय सरावगी : अध्यक्ष महोदय, मैं बता रहा था कि सरकारी विभागों पर बिजली बिल का 17 सौ 18 लाख रुपया केवल पटना में बाकी है अध्यक्ष महोदय । पूरे बिहार का आंकड़ा मेरे पास नहीं है तो माननीय मंत्री जी को बताना चाहिए कि पूरे बिहार में सरकारी आप एक गरीब का अगर दो दिन लेट हो जाता है अध्यक्ष महोदय तो इस मार्च-चार्ज का पॉवर ऑफ हो जाता है । हमलोग गरीब के यहां जाते हैं अध्यक्ष महोदय, कहते हैं- बउआ इ जे स्मार्ट मीटर हई, इ तुरते तुरते बंद हो जाई छै बउआ, पिछला बेर आवै छलै 200 के बिल अब 1 हजार रुपया रिचार्ज करवावै छिऐ तो दसे दिन बारह दिन में बंदे हो जाइ छै । अगर 500, 200-300 रुपया गरीब नहीं दे पा रहा है तो मंत्री जी उसका ऑफ कर देते हैं और ये करोड़ों-करोड़ रुपया बिजली कार्यालय पर जो पैसा जमा है, मंत्री जी को बताना चाहिए कि कितने पर एफ0आई0आर0 हुआ, कितना का बिजली कट हुआ क्या गरीब का ही केवल गर्दन काटने के लिए तो मंत्री जी बुजुर्ग हैं, हमलोगों के गारजियन भी हैं तो मंत्री जी को बताना चाहिए कि कितने सरकारी कार्यालयों में, पहले तो बताए पटना मुख्यालय में राजधानी के अंदर...

(व्यवधान)

हम कैसे कहें बुढ़े हो गए हम तो कहेंगे कि और जवान हो जायें हमलोगों के गारजियन हैं बिजेन्द्र बाबू, ये तो आप बता सकते हैं । तो मैं कह रहा था अध्यक्ष महोदय कि माननीय मंत्री जी को बताना चाहिए कि कितने पदाधिकारियों पर एफ0आई0आर0 हुआ, अरबों-अरब रुपया जो सरकारी कार्यालयों में बाकी है एफ0आई0आर0 करने के लिए और बिजली कट करने के लिए क्या गरीब जनता ही है कि सरकारी कार्यालयों का भी पॉवर कट होगा, यह मैं पूछना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय । अध्यक्ष महोदय, सरकार ने एक और निर्णय किया था अच्छा निर्णय किया था, जितने भी हमारे भवन हैं बिहार में, सरकारी भवन हैं उसमें सौर ऊर्जा के लिए, उसमें हम सौर ऊर्जा की व्यवस्था करेंगे और यह माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया था और माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ कमजोर हो गए हैं कितना

निर्देश पालन हो रहा है ये तो बताना चाहिए लेकिन मैं पूछना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो सौर ऊर्जा उपकरण का निर्देश दिया सभी सरकारी भवन में, तो माननीय मंत्री जी को बताना चाहिए कि बिहार में कितने प्रतिशत सरकारी भवनों पर सौर ऊर्जा लगा, इसका ब्यौरा अध्यक्ष महोदय माननीय मंत्री जी को विधान सभा में रखना चाहिए यह मैं आग्रह करना चाहता हूं और अध्यक्ष महोदय, दरभंगा में जो है बिहार का पहला तैरता हुआ फ्लोटर जो है अध्यक्ष महोदय, सौर ऊर्जा की व्यवस्था लगा है, पूरे मिथिला में हजारों की संख्या में बड़े-बड़े तालाब हैं अध्यक्ष महोदय जहां सौर ऊर्जा सोलर पॉवर से, नीचे मछली और ऊपर बिजली तो जितने भी पूरे मिथिला में बड़े-बड़े तालाब हैं, सैकड़ों एकड़ की संख्या में तो मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा पिछले साल दरभंगा में लगा तो पूरे मिथिला में सरकार की योजना थी बिहार में कि हर तालाब में हम जो हैं फ्लोटिंग...

(व्यवधान)

सब केंद्र के ही अनुकम्पा से हो रहा है, आज केंद्र अगर ऑफ कर दे न तो बिजली साफ हो जायेगा इतना ही समझ लीजिए इसलिए बेसी तरफराइए मत । यहां पर पढ़े-लिखे लोग हैं ऐसी बात क्यों...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आप अपनी बात कहिए ।

श्री संजय सरावगी : अध्यक्ष महोदय, टोका-टोकी कर रहे हैं तो अध्यक्ष महोदय, मेरा समय बढ़ाइए और इनका समय काटिए...

अध्यक्ष : टोका-टोकी न करें ।

श्री संजय सरावगी : मैं यह आग्रह करना चाहता हूं...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य टोका-टोकी न करें ।

श्री संजय सरावगी : तो अध्यक्ष महोदय, तो ये फ्लोटिंग जो है तैरता हुआ बिजली घर, एक लगा है दरभंगा में तो निश्चित रूप से पूरे बिहार में और मिथिला में जहां बड़े-बड़े तालाब हैं ये लगना चाहिए अध्यक्ष महोदय, यह मैं आग्रह करना चाहता हूं । अध्यक्ष महोदय, एक अखबार में छपा था कि बिहार में बिजली का दर, बगल में और राज्य भी देश में हैं अध्यक्ष महोदय, और विभाग जो आंकड़े का खेल करती है 200 यूनिट से कम वाले का ये रेट, 100 यूनिट से कम वाले का ये रेट, माननीय मंत्री जी को बताना चाहिए कि पिछली बार उद्योग विभाग के लिए अलग से जो है बिजली की व्यवस्था हुई थी उसमें कि उद्योग विभाग को कुछ अलग से रियायत

सरकार देने वाली थी इसलिए जैसे उद्योग विभाग को अलग से घरेलू, शहरी उद्योग विभाग का अलग से हुआ था तो क्या सरकार उद्योग को बढ़ावा देने के लिए लंबी-लंबी बात करती है, इतने फैक्ट्री खोलेंगे, इतने फैक्ट्री खुलवायेंगे, निवेशक आ नहीं रहे हैं तो क्या उद्योग विभाग को अलग से जो उनका अलग से किया गया था उसमें क्या कुछ मंत्री जी रियायत देने वाले हैं अध्यक्ष महोदय, यह मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं माननीय मंत्री जी बतावें कि यही रेट रहेगा उद्योग का बिहार में । बिहार में अध्यक्ष महोदय, उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कुछ न कुछ स्पेशल रियायत तो देनी चाहिए । 4 रुपया 26 पैसा में एन0टी0पी0सी0 जो है बिहार को बिजली दे नही है और 1 रुपया बढ़ाकर बिहार सरकार लोगों से चार्ज कर रही है और उसके बाद भी नुकसान पर नुकसान क्योंकि वह जो 30 परसेंट मैंने पहले बोला, वह लॉस हो रहा है उसके कारण अध्यक्ष महोदय,...

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपका समय खत्म हुआ ।

श्री संजय सरावगी : बस, बस मेरे क्षेत्र का एक विषय है महोदय । आप जितना देर कहिएगा अध्यक्ष महोदय, हम उतना देर बैठ जायेंगे । अध्यक्ष महोदय, दरभंगा में नवंबर में माननीय मुख्यमंत्री जी ने शिलान्यास किया था ऑनलाईन पटना से आर0डी0एस0एस0 योजना का और उसमें शहर में भी गांव में भी कैसे विद्युत संरचना का विकास हो, कैसे एग्रीकल्चर फीडर बढ़े, उसमें अध्यक्ष महोदय, शहर में गलियों से तार जा रहा है, 11 हजार का ए0बी0केबुल अध्यक्ष महोदय, बहुत आवश्यक है क्योंकि लोग सट जाते हैं 11 हजार ओपेन तार से जिसके कारण मौत हो रही है । कम से कम मात्र 2 किलोमीटर की व्यवस्था जो है ए0बी0केबुल में की गई है अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कम से कम इसको 25 किलोमीटर 11 हजार वाट वाला जो है इसको करने की व्यवस्था...

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब स्थान ग्रहण करें अपना ।

श्री संजय सरावगी : और अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी जो शिलान्यास किए, बस 10 सेकेंड महोदय ।

(क्रमशः)

टर्न-12/सुरज/17.03.2023

(क्रमशः)

श्री संजय सरावगी : मुख्यमंत्री जी जो 30 नवम्बर को शिलान्यास किये महोदय चार महीने बीत गये अभी तक उस कंपनी ने एग्रीमेंट नहीं किया है । यह मैं माननीय मंत्री जी को जानकारी देना चाहता हूं, चार-चार महीने शिलान्यास किये हुये हो गया और उस

कंपनी को टेंडर मिल गया । कंपनी एग्रीमेंट नहीं कर रही है इसलिये अध्यक्ष महोदय उसको भी जरा देखें...

अध्यक्ष : माननीय सदस्य आपका समय खत्म हुआ...

श्री संजय सरावगी : अध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया इसके लिये आपको, नेता विपक्ष को, सचेतक को बहुत-बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं । धन्यवाद ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह, आपका समय 12 मिनट है।

श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आज वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिये ऊर्जा विभाग एवं गिलोटिन में अन्य विभागों के अनुदान मांगों के समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हूं । महोदय, इस अवसर पर मैं अपने दल राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष और गरीबों के मसीहा माननीय लालू प्रसाद यादव जी को धन्यवाद देता हूं । मैं विशेष तौर से धन्यवाद देना चाहूंगा बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी को । मैं धन्यवाद देना चाहूंगा युवा तुर्क और बिहार के उप मुख्यमंत्री माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को और विशेष तौर से मैं धन्यवाद देना चाहूंगा नवीनगर और वारूण की जनता को कि आज ये अवसर मुझे मिला कि मैं आज यहां पर सदन में हूं । महोदय, अभी मैं सुन रहा था खास करके संजय भाई का वक्तव्य भी मैं सुन रहा था और वक्तव्य देकर वह निकलते बने । क्योंकि आज मुझे यह अवसर इसलिये भी दिया गया है मेरे दल की तरफ से क्योंकि मुझे ये हर्ष है कि मैं उस विधान से आता हूं जिस विधान सभा को नवीनगर कहा जाता है और नवीनगर वह विधान सभा है जहां पर दो-दो एन0टी0पी0सी0 प्लांट हैं । अभी कह रहे थे कि माल महाराज के और मिर्जा खेले होली । तो हम इस चीज पर अपने पूरे विपक्ष के साथियों का ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं कि किसका माल और कैसी होली, क्या चीज का भारत सरकार ? अगर हिम्मत है तो पूरे हिंदुस्तान को आपलोग अगर कहते हैं कि एक है तो एक टैरिफ कर दीजिये । बिजली बिल का जो रोना रो रहे हैं हमलोग वह हिंदुस्तान के अंदर एक टैरिफ करके दिखा दीजिये, तब हम मानेंगे कि आपलोगों में जिगर है और जो ये कह रहे थे कि माल महाराज के तो हम बताते हैं कि माल किसका और महाराज कहां होली खेल रहे हैं । एन0टी0पी0सी0 हमलोगों के यहां पे बना हुआ है और सी0एस0आर0 का पैसा आता है और यह हमारे यहां ही नहीं । ये आपको जान कर ताज्जुब होगा कि छः-छः एन0टी0पी0सी0 प्लांट इस राज्य के अंदर में हैं और वहां के माननीय विधायकों से पूछ लीजिये, उसमें आपके भी दल के हैं ज्ञानू भैया के यहां है बाढ़ में है, कहलागांव में है भाई हमारे बैठे हैं पवन जी, माननीय मंत्री जी के यहां है, इसराईल भाई के यहां है, मेरे यहां है, सबके यहां है । लेकिन आत्मा पर हाथ रखकर बोलना

होगा । जितने माननीय विधायक हैं जो-जो एन0टी0पी0सी0 के क्षेत्र से आते हैं क्या मिलता है ? जब हमलोगों को जमीन देना था तब हरदम हमलोगों को पूछते थे, किसानों के आंसू पोछते थे । लेकिन आज कोई पूछने के लिये तैयार नहीं है...

(व्यवधान)

सुनते जाइये, सुनते जाइये, क्यों अकबका रहे हैं । सुना दे रहे हैं क्यों अकबका रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : शांति बनाये रखें ।

श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह : जहां पर बिजली देने की बात कर रहे हैं तो याद कीजिये उस समय हमलोग बिजली के इस परियोजना पर हमलोग हस्ताक्षर किये थे, वहां हमारे किसान किये थे, जब पूरा देश जल रहा था । जब सिंगूर का मामला चल रहा था उस समय बिहार का किसान इस हिंदुस्तान की तकदीर को बनाने के लिये अपना जमीन दे रहा था और उसी जमीन के लिये । आज जाकर देख लीजिये वहां के किसानों की दुर्गति । आज एन0टी0पी0सी0 प्लांट आने के चलते उस इलाके के किसानों की हालत देख लीजिये, कोई सुध लेने के लिये तैयार नहीं है । हमलोगों के जिम्मे में, हमलोगों के किसानों के जिम्मे में मात्र केवल राख मिलता है। अगर अगल-बगल के इलाके में आप घूमियेगा तो आपको यह समझ में आ जायेगा कि कितना फ्लाई ऐश उड़ता है उस जिले के अंदर में, कितना पॉल्यूशन हो रहा है । किसान के लिये भारत सरकार ने अभी तक क्या सोचा है, वहां के लोगों को रोजगार देने की बात कभी किया हो । वहां के लोगों को हरदम प्लांट से बाहर कर दिया जाता है । वहां के नौजवान अपनी किस्मत पर रोते हैं, वे यह कहते हैं कि हमारे बाप-दादा का, पुरखों का जमीन एन0टी0पी0सी0 प्लांट ने ले लिया और हमारी कोई सुध लेने के लिये तैयार नहीं है और खास करके मैं सी0एस0आर0 की बात कर रहा था तो जितने भी एन0टी0पी0सी0 प्लांट के हैं, आज हमलोगों को बड़ा गर्व हुआ था कि यहां ही के, बिहार के माननीय मंत्री हैं जिनके पास विद्युत विभाग है । वह पूरे हिंदुस्तान के मंत्री थे । ऐसा क्या है कि पूरे बिहार के एन0टी0पी0सी0 प्लांट के सी0एस0आर0 का पैसा उठा के एक क्षेत्र ले जाया जाता है । मैं आज इस सदन से मांग करता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय एक रेजोलुशन यहां से पास होना चाहिये कि जिस जगह का एन0टी0पी0सी0 प्लांट है उसके सी0एस0आर0 का पैसा 75 प्रतिशत उसी इलाके में खर्च हो जहां पर वहां के लोग अपना जमीन दिये हैं न कि हमलोगों को कुछ चंद रुपये देकर हमलोगों को संतुष्ट करने का ये लोग प्रयास करते हैं । हमलोग जब भी बात करते हैं कि यहां के

लोकल इशूज के डेवलपमेंट के लिये इस पैसे का खर्च होना चाहिये । चूंकि पवन भाई भी हमसे अपना दुख रो रहे थे एक दिन कि हमलोगों का कोई सुनता ही नहीं है । एन0टी0पी0सी0 में कोई नहीं सुनता है और पूरा का पूरा पैसा कॉरपोरेट ऑफिस में चला जाता है और कॉरपोरेट उठाकर एक इलाके के विकास के लिये खर्च होता है । तुम कौन, जमीन हमलोगों की, किसान हमलोगों के, क्षेत्र...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें ।

श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह : खास करके माननीय अध्यक्ष महोदय...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आप बिना इजाजत न बोलें, आप सुनें ।

श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री ललन जी आप स्थान ग्रहण करें ।

श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह : अगर आपलोगों को बोलना ही है तो केवल टैरिफ पर ही बात कर लीजियेगा । अगर उसको ठीक करा लीजियेगा तो हम समझेंगे कि आपलोग अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं । मैं माननीय अध्यक्ष महोदय...

अध्यक्ष : डब्लू जी, आप किसी के टोका-टोकी और उनकी तरफ न ताकिये । आप अपनी बात को कहते चले जाइये ।

श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, खास करके नवीनगर जहां दो-दो एन0टी0पी0सी0 प्लांट हैं, मगध प्रमंडल का सबसे बड़ा ब्लॉक है । मैं खास करके ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि वहां पर विद्युत सब-डिवीजन बनाने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है क्योंकि दो-दो एन0टी0पी0सी0 प्लांट और इतना बड़ा क्षेत्र तो हमें लगता है कि अब वहां दरकार है । मैं एक और चीज पर ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा कि विगत हमलोग देख रहे हैं, सभी माननीय विधायक अपने क्षेत्र में घूमते हैं जो गांव की रूप-रेखा है जिस तरीके से इधर बढ़ी है तो हमको लगता है कि हमलोग जब भी जाते हैं तो ये कम्प्लेन आती है कि हमलोगों का ट्रांसफार्मर जल गया है 63के0वी0 का हो कि 100 के0वी0 का हो । यह हरदम कम्प्लेन मिलता है तो हम आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कराना चाहेंगे कि जहां पर भी एडिशनल ट्रांसफार्मर लगाने की आवश्यकता है उसको ध्यान में रखते हुये, उसका चयन करते हुये जिस गांव में, जिस इलाके में उसको बढ़ाना है वहां पर एडिशनल ट्रांसफार्मर की तुरंत व्यवस्था करायी जाय । मैं खास करके माननीय नीतीश जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने बिजली को

कृषि से जोड़ दिया है । खास करके हमलोगों के इलाके में, जो मगध का इलाका है, जहां पर खास करके पानी की बहुत दिक्कत हो जाती है इलाके में खेती करने के लिये । हर खेत में पानी पहुंचाने के लिये बिजली विभाग ने बहुत शानदार काम किया है, हमलोग देख रहे हैं । लेकिन उसमें और तेजी लाने की जरूरत है ।

(क्रमशः)

टर्न–13/राहुल/17.03.2023

श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह (क्रमशः): जो खासकर के अभी हम लोग महसूस कर रहे हैं कि इलाके में 25 के0वी0ए0 का ट्रांसफार्मर लगाकर उसको 25 की जगह 63 करा दिया जाय और ज्यादा से ज्यादा उसको आगे बढ़ाने की जरूरत है। हमारे इलाके में एक बारूण प्रखंड है जहां पर सबडिविजन बनाने की मांग मैं पहले भी किया था तो मैं चाहता हूं कि इस वित्तीय वर्ष में उसको करा दिया जाय । आज बुलेटिन में विधि विभाग भी है तो विधि विभाग पर एक–दो बात जरूर मैं बोलना चाहूंगा । खासकर कि हम लोग देखते हैं कि न्यायपालिका की अभी जो स्थिति है बहुत सारे केस पेंडिंग पड़े हुए हैं और छोटे–छोटे केस में जो छोटे अपराध हैं जिसमें लोवर कोर्ट में बेल नहीं हो पा रही है और हाईकोर्ट जाने के बाद महीने–दो महीने, 6–6 महीने, 8–8 महीने लग रहे हैं हाईकोर्ट में वह केस पकड़ाने में तो हम आग्रह करेंगे कि इसको थोड़ी स्पीड की जरूरत है, उसके लिए जो भी बन पड़े सरकार उसमें पहल करे और नीचे के लेवल पर जो लोवर कोर्ट हैं उन पर प्रेशर कम करने के लिए कोर्ट को अगर बढ़ाना हो तो उसको बढ़ायें और उसमें तेजी लाने की जरूरत है । खासकर कि मेरे यहां एक बहुत बड़ी समस्या आ गई है कि एक बिहार लैंड ट्रिब्यूनल, जो हर प्रखंड में है,...

अध्यक्ष : माननीय सदस्य मात्र एक मिनट ही समय बच गया है आपका ।

श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह : हर प्रमंडल में है जिसमें जमीन संबंधित जितने वाद हैं वहां पर जाते हैं, रिटायर्ड जजेज उसके अध्यक्ष होते हैं । हमारे यहां गया में वह कोर्ट बैठता है चूंकि हम लोग देख रहे हैं कि भूमि अधिग्रहण का काम हम लोगों के यहां बहुत ज्यादा है एन0टी0पी0सी0 का हो, एन0एच0 का हो, इरिगेशन का हो या रेलवे का हो । चूंकि हम लोगों के यहां सारे विभागों में काम चल रहा है तो उतना ही ज्यादा इसपर लोड है । हर जगह डिस्प्यूट होने के चलते लोग कोर्ट में चले जा रहे हैं लेकिन दुर्भाग्यवश हम देखते हैं कि राज्य सरकार इस पर कहीं पर भी अंकुश नहीं लगा पा रही है कि वे कितने केस

डिस्पोजल कर पा रहे हैं तो अभी तक जो हम लोगों ने महसूस किया है, जो हम लोगों ने देखा है उसमें बहुत कमी है । लोग हम लोगों के पास आते हैं कि विधायक जी हम लोगों का केस आज दो-दो, तीन-तीन साल से गया ट्रिब्यूनल में फंसा हुआ है...

अध्यक्ष : माननीय सदस्य आपका समय समाप्त हुआ ।

श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह : तो इन सारे विषयों पर मैं खासकर के अध्यक्ष जी और पूरी सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं । आप लोगों ने समय दिया इसके लिए माननीय अध्यक्ष जी मैं धन्यवाद करता हूं । जय हिंद, जय भारत ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री विनय बिहारी अपना पक्ष रखें । आपका समय 10 मिनट है।

श्री विनय बिहारी : जादे बोलल क्राईम बा, काहे कि दसे मिनट के टाईम बा । अध्यक्ष महोदय, न गीता, न कुरान अपने साथ लाया हूं फिर भी कुछ सच बोलने सदन में आया हूं । अध्यक्ष महोदय, सदन 365 दिन में सिर्फ चालीस रोज ही चलता है और बड़ी मुश्किल से कोई सवाल सदन के भीतर निकलता है लेकिन हालात के आगे जब तन्हाई में होता हू तो कभी सदन पे तो कभी बिहार की किस्मत पर रोता हूं । शून्यकाल को क्या कहूं, अपने आपको आजमाना पड़ता है और आधी नींद से जागकर सुबह चार बजे आना पड़ता है । कार्यवाही बाधित रहती है, अपनी गरिमा खोती है और सदन में हमारी लड़ाई जानवरों की तरह होती है । बिहार देखता है माहौल कितना अपवित्र है क्योंकि वक्ताओं के निशाने पर सिर्फ चरित्र होता है । अध्यक्ष महोदय, जब दोनों ही पक्षों का चरित्र खराब है तो बिहार में बंद क्यों सिर्फ शराब है । नशा कोई भी हो, सरकार क्यों भ्रमित है बीड़ी, सिगरेट, गुटका, गांजा यह सब कौन सा अमृत है ? समाज का उत्थान हो..

(व्यवधान)

आप कुछ बोलेंगे मैं आप पर ध्यान नहीं दूंगा । समाज का उत्थान हो, परिवार में आनन्दी हो । शराब ही क्यों, राज्य में संपूर्ण नशाबंदी हो ।

अध्यक्ष महोदय,

राऊर भाषा, हमार भाषा, दोनों ओर भोजपुरी बा,
त ना कवनो दबाव में, ना कवनो मजबूरी में,
रऊवा इजाजत से कुछ बात कहें हम भोजपुरी में ।

अध्यक्ष महोदय, आज चार विभागों पर कटौती प्रस्ताव है बस चार-चार लाईन में कुछ कहने का भाव है और भाव क्या है कि :

बंद बावे दारू बाजार में बिकाता,
और बान्हल बा महीना अफसर कमाता ।
रोकला से केकरो, ना पियल रोकाता,
बताइये मलिकार बिहार कहां जाता ?

महोदय, बिजली व्यवस्था कमाल है । धन्यवाद है आपको बिजली व्यवस्था सही है, मैं बोल रहा हूं । बिजली व्यवस्था कमाल है लेकिन बिल से दिल बेहाल है । उपभोक्ताओं के साथ इंसाफ होना चाहिए और जो ब्याज लगा है वह माफ होना चाहिए । क्या है कि:

अईसन करेंट लागल, लोग करकराता,
और बिजली के बिल भरत देह भहराता,
और दिनभर रहत रतिये लपाता,
बताईए मलिकार बिहार कहां जाता ?

अब आते हैं तीन करोड़ मिलता । अध्यक्ष महोदय, सीसो छरहर होईं उकर खातिर पांग लेवे के चाहीं और जब सामने मलिकार बईठल होईं त कुछ मांग लेवे के चाहीं तो क्या कहना चाहते हैं कि तीन करोड़ मिलता जीरा बुझाता, ऊंट के मुंह में जीरा ।

तीन करोड़ मिलता, जीरा बुझाता,
अर चालीस पंचायत में के बनी दाता । आसान काम है ।
10-10 लाख रुपये नहीं आये तो
तीन करोड़ मिलता, जीरा बुझाता,
अर चालीस पंचायत में के बनी दाता ।
योजना के ओखरी में मुड़ी कुटाता,
बताईए मलिकार बिहार कहां जाता ।
सुसुके सुशासन विभाग चरचराता,
केहूं के तनिको ना कान खरखराता ।
इंसाफ के तराजू में नमरी तऊलाता,
बताईए सरकार बिहार कहां जाता ।

अध्यक्ष महोदय,

हम विधायिका हैं, सदन में जीतकर आ गये,
अपनी पेंशन बचा लिए, सबकी पेंशन खा गये...
(व्यवधान)
सामाजिक सुरक्षा पेंशन में सुधार होना चाहिए,

चार सौ रूपइयां अब एक हजार होना चाहिए,
सेविका, सहायिका, आशा, ममता, रसोइयां का कल्याण हो,
सदन से अरजी करता हूं इन बहनों का सम्मान हो ।
अईसन मत होखे कि कहे के परे, तोहरे के फेरा में रहे के परे,
कह तार दीदी कि मार तार ताना,
अर पनरे सौ रूपइयां में बनवाव तार खाना । यह कहां का इंसाफ है अध्यक्ष महोदय,
मजदूर पलायन रूक जाये, उद्योगों की भरमार हो,
विश्व गुरू कहलाये फिर से, ऐसा मेरा बिहार हो ।
मुमकिन है, गागर में सागर संवर जायेगा,
यहां हम सुधर गये तो बाहर बिहार सुधर जायेगा ।

...क्रमशः...

टर्न–14/मुकुल/17.03.2023

श्री विनय बिहारी (क्रमशः) : हमको यहां पर सुधरना होगा । अध्यक्ष महोदय, हम विधायकों की झोली अपने आशीर्वाद से भर दीजिए और मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास की राशि 3 करोड़ से बढ़ाकर 5 करोड़ कर दीजिए, क्या प्रस्ताव अच्छा है तो मैं सदन से कहूंगा कि अगर सबकी राय हो तो हमारे माननीय मंत्री जी यहां पर बैठे हुए हैं, यह राशि 5 करोड़ की हो जाय और हमलोगों पर से पाबंदी हट जाय कि ईंट मत करवाइये, नाली नहीं बनवाइये, पुलिया नहीं बनवाइये । जब हमलोग कुछ बनवा ही नहीं सकते हैं तो क्या बनवायेंगे, आखिर हमलोग यहां पर विधायक बनकर क्या करने आये हैं। इसलिए मैं आपको कहना चाहूंगा कि 5 करोड़ की राशि माननीय मंत्री जी यहां पर बैठे हुए हैं अगर ये यहां पर बोलते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी । अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे सदन में बोलने का मौका दिया इसके लिए और अपनी पार्टी के श्री विजय कुमार सिन्हा जी और श्री जनक जी को बहुत–बहुत धन्यवाद करते हुए, 10 मिनट के अंदर अपनी बात को समाप्त करते हुए आपको बहुत–बहुत धन्यवाद, आपको प्रणाम, अपने क्षेत्र की सम्मानित जनता को प्रणाम, सभी को प्रणाम, नमस्कार, धन्यवाद, जय बिहार, वंदे मातरम् ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री सिद्धार्थ पटेल ।

श्री नन्द किशोर यादव : आज तो विनय बिहारी जी ने महफिल लूट ली ।

अध्यक्ष : नंद किशोर जी, असल बात है कि ये आपके ही पीछे बैठे हुए हैं ।

माननीय सदस्य, श्री सिद्धार्थ पटेल जी, आप अपना पक्ष रखें । आपका समय 10 मिनट का है ।

श्री सिद्धार्थ पटेल : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया । साथ ही, मैं वैशाली विधान सभा क्षेत्र के तमाम सम्मानित मतदाताओं के प्रति आभार प्रकट करता हूं जिनके आशीर्वाद से मुझे इस लोकतंत्र के मंदिर में बोलने का मौका प्राप्त हुआ है । अध्यक्ष महोदय, मैं विपक्ष द्वारा लाए गए कटौती प्रस्ताव के विरोध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं । अध्यक्ष महोदय, हम सबों के नेता माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने घोषणा की थी कि मैं ऊर्जा के क्षेत्र में विकास नहीं कर सका तो आपके बीच वोट मांगने नहीं आऊंगा तो हमलोगों को भी यह लगा था कि इतना जल्द यह कैसे संभव हो पायेगा। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी हर मुश्किल काम को चुनौती के रूप में लेते हैं और उसमें सफलता प्राप्त करते हैं । ऊर्जा प्रक्षेत्र में विभिन्न योजनाओं के माध्यम से विद्युत संरचनाओं का सुदृढ़ीकरण, विस्तार एवं आधुनिकीकरण का कार्य किया गया है, जिसके फलस्वरूप, राज्य के शहरी क्षेत्रों में 23-24 घंटे तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 21-22 घंटे विद्युत की सुचारू आपूर्ति की जा रही है । राज्य में उपभोक्ताओं की संख्या बढ़कर वर्तमान में लगभग 01 करोड़ 86 लाख हो गई है । विद्युत आपूर्ति की अवधि एवं गुणवक्ता में बढ़ोतरी के कारण विद्युत की अधिकतम मांग में लगातार वृद्धि हो रही है, जो नई ऊंचाइयों को छूते हुए विगत 05 अगस्त, 2022 को 6,738 मेगावाट तक पहुंच गया, जो वर्ष 2024-25 तक लगभग 8,000 मेगावाट हो जाने की संभावना है । अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार के सात निश्चय-2 में शामिल ''हर खेत तक सिंचाई का पानी'' को सफल बनाने की दिशा में ऊर्जा विभाग के द्वारा कृषि कार्य हेतु विद्युत संरचना के निर्माण के साथ-साथ डेडिकेटेड फीडर का निर्माण किया जा रहा है तथा सिंचाई हेतु कृषि पम्प सेटों को विद्युत संबद्ध किया जा रहा है । राज्य के बरौनी तथा कांटी स्थित ताप विद्युत केन्द्रों से सस्ता एवं दक्षतापूर्ण उत्पादन हेतु इनका पूर्ण स्वामित्व एन0टी0पी0सी0 को सौंप दिया गया । साथ ही, नवीनगर पावर जेनरेशन कंपनी में बिहार के पूर्ण अंशपूंजी को भी एन0टी0पी0सी0 को हस्तांतरित कर दिया गया । इन परियोजनाओं से उत्पादन प्रारम्भ हो गया है एवं बिहार को इसका लाभ मिल रहा है । राज्य सरकार के प्रयासों से भविष्य में बाढ़ एवं बक्सर थर्मल पावर स्टेशन की दो-दो निर्माणाधीन इकाइयों से लगभग 2,640 मेगावाट अतिरिक्त बिजली उत्पादित होगी । ग्लोबल वार्मिंग एवं क्लाइमेट चेंज की समस्याओं के निराकरण की दिशा में अक्षय ऊर्जा का महत्व दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है । जल-जीवन-हरियाली अभियान के तहत राज्य में सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा कजरा (लखीसराय) एवं पीरपैंती (भागलपुर) में ताप विद्युत केन्द्र के स्थान पर बैट्री

स्टोरेज के साथ लगभग 450 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना के निर्माण का निर्णय लिया गया है, जिसपर अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है । इसके अतिरिक्त राज्य में नहरों के किनारे एवं ऊपर भी सौर विद्युत उत्पादन परियोजनाओं की स्थापना हेतु सर्वेक्षण किया जा रहा है । एक नई पहल के तौर पर राज्य के महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल यथा, राजगीर, बोध गया एवं पटना शहर के कुछ हिस्सों को परम्परागत ऊर्जा के स्थान पर चौबीसों घंटे हरित ऊर्जा के माध्यम से बिजली उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है । संचालित पम्प स्टोरेज प्लांट के माध्यम से आवश्यक मात्रा में बिजली उपलब्ध होगी । इस परियोजना को दिसम्बर, 2023 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है । राज्य के संचरण प्रक्षेत्र में सुदृढ़ीकरण हेतु नयी परियोजनाओं का कार्यान्वयन तीव्रगति से कराया गया है, जिसके फलस्वरूप वर्तमान में राज्य कार्यरत ग्रिड उपकेंद्रों की संख्या 161 हो गयी है । साथ ही, संचरण प्रणाली की विद्युत निकासी क्षमता 13,544 मेगावाट हो गयी है । वर्ष 2021 की तुलना में संरचना लाइनों की कुल लम्बाई 17,120 सर्किट किलोमीटर से बढ़कर वर्तमान में 18,740 सर्किट किलोमीटर हो गयी है । वर्ष 2023-24 तक ग्रिड सब-स्टेशनों की कुल संख्या बढ़कर 173 हो जाएगी । वर्तमान में राज्य परियोजनाओं के अंतर्गत 14 नये ग्रिड उपकेंद्रों एवं सम्बन्धित संचरण लाइनों का निर्माण कार्य तथा ग्रिड उपकेंद्र, एकमा (सारण) का विस्तारीकरण का कार्य प्रगति पर है । संचरण कम्पनी द्वारा पहली बार पटना जिले में नई तकनीक के तीन जी0आई0एस0 ग्रिड उपकेंद्र (बख्तियारपुर-400 के0वी0, दीघा-200 के0वी0 एवं विद्युत कॉलोनी-132 के0वी0) का निर्माण किया जा रहा है । बख्तियारपुर का नया जी0आई0एस0 ग्रिड सब-स्टेशन संचरण कम्पनी द्वारा संचालित पहला 400 के0वी0 का ग्रिड सब-स्टेशन होगा । विगत वर्ष बी0एस0पी0टी0सी0एल0 द्वारा अस्थावां (नालंदा), कर्मनासा न्यू (कैमूर) एवं गोरौल (वैशाली) में 220/132/33 के0वी0 तथा पालीगंज (पटना) में 132/33 के0वी0 नये ग्रिड उपकेंद्रों का निर्माण पूर्ण कर ऊर्जान्वित किया जा रहा है । अध्यक्ष महोदय, मैं एक जानकारी दे दूं कि इसमें जो गोरौल ग्रिड है वह मेरे विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत मेरे गृह पंचायत में पड़ता है, वहां के तमाम भूमिदाताओं ने अपनी जमीन इस कार्य के लिए दी है, मैंने पहल करके अपनी जमीन उसमें दी और बाद में मेरे ग्रामीणों ने भी अपनी भूमि ग्रिड उपकेन्द्र को बनाने में दी । मैं माननीय मंत्री जी एवं विभाग के तमाम पदाधिकारियों के प्रति भी आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि समय-सीमा अवधि के समाप्त होने के पहले ही इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ । साथ ही, जक्कनपुर एवं नौबतपुर में 400/220/132/33 के0वी0 तथा भुसौला में 220/33 के0वी0 का ग्रिड उपकेंद्र का

निर्माण पूर्ण कर ऊर्जान्वित किया गया है । राज्य सरकार द्वारा 1329.61 करोड़ की 'मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना' की स्वीकृति अगस्त, 2020 में दी गयी । योजना में विद्युत संरचना के निर्माण के साथ-साथ कृषि कार्य हेतु विद्युत संबद्ध किया जा रहा है । योजना का कार्य अंतिम चरण में है तथा इसे मार्च, 2023 तक पूरा करने का लक्ष्य है । इसके उपरांत कृषि कार्य हेतु डेडिकेटेड फीडर निर्माण का कार्य पुर्नोत्थान वितरण क्षेत्र योजना के अंतर्गत किया जाना है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, संक्षिप्त में अपनी बात को रखें, क्योंकि आपका समय बहुत कम रह गया है ।

श्री सिद्धार्थ पटेल : अध्यक्ष महोदय, वर्तमान में राज्य में उपभोक्ताओं की संख्या 186 लाख से भी अधिक है । इतनी बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं का मासिक मीटर पठन, विपत्रीकरण एवं राजस्व की वसूली वितरण कंपनियों के लिए हमेशा चुनौतीपूर्ण कार्य रहा है । शहरी क्षेत्र में उत्साहवर्धन परिणाम प्राप्त होने के उपरांत राज्य सरकार द्वारा राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में भी बिजली उपभोक्ताओं के लिए भी स्मार्ट प्री-पेड मीटर उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है । अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बातों को शॉर्ट कर रहा हूं । महोदय, उपभोक्ता सेवाओं तथा शिकायतों के निवारण हेतु टॉल फ्री नम्बर 1912 की सुविधा के अतिरिक्त ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने की सुविधा बी0एस0पी0एच0सी0एल0 के वेबसाइट पर प्रदान की गई है । उपभोक्ता बी0एस0पी0एच0सी0एल0 के वेबसाइट पर जाकर अपनी शिकायत ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं, जो तत्काल सम्बन्धित विद्युत कार्यपालक अभियंता को चला जायेगा जिन्हें निर्धारित समय-सीमा के अंदर उन शिकायतों का निष्पादन करना होगा । शिकायतकर्ता अपने निबंधित शिकायत को ऑनलाइन ट्रैक भी कर सकते हैं ।

(क्रमशः)

टर्न-15/यानपति/17.03.2023

(क्रमशः)

श्री सिद्धार्थ पटेलः अध्यक्ष महोदय, राज्य के विभिन्न सरकारी भवनों के छत पर केपेक्स मॉडल के तहत 9.90 एम0डब्लू0पी0 ग्रिड कनेक्टिंग रूफ टॉप सोलर प्लांट के अधिष्ठापन का कार्य प्रारंभ हो चुका है । जल-जीवन-हरियाली अभियान के तहत राज्य के सभी प्रखंड कार्यालय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों तथा आई0टी0आई0 तथा पंचायत सरकार भवनों पर यह कार्य हो रहे हैं । 50 भवनों पर लगभग एक मेगावाट ग्रिड कनेक्टेड रूफ टॉप सोलर पावर प्लांट का अधिष्ठापन का कार्य पूर्ण हो चुका है शेष भवनों के अधिष्ठापन का कार्य प्रगति पर है । नीचे

मछली ऊपर बिजली योजना के अंतर्गत दरभंगा जिला में 1.6 एम0डब्लू0पी क्षमता तथा सुपौल जिला में 0.525 एम0डब्लू0पी0 क्षमता का प्लॉटिंग सोलर पावर प्लांट का निर्माण कार्य पूर्ण कर ऊर्जान्वित किया जा रहा है । बिहार राज्य के वर्तमान में कुल 13 विद्युत जल परियोजनाएं उत्पादनरत हैं जिनकी कुल क्षमता 54 मेगावाट है । गंडक, बूढ़ी गंडक एवं महानंदा नदियों का जल विद्युत क्षमता की संभावनाओं का सर्वे कराया गया है चिन्हित स्थानों.....

अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपका समय समाप्त हुआ । आप स्थान ग्रहण करें ।

श्री सिद्धार्थ पटेल: सर, एक निवेदन के साथ मैं समाप्त कर देना चाहूंगा । अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो हमलोग जाते हैं तो अक्सर लोगों की समस्याएं आती हैं बिजली बिल के सुधार के संदर्भ में तो मेरा अनुरोध होगा सर आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कि प्रखंड मुख्यालयों में महीने में कोई एक दिन तय किया जाय कि जो ग्रामीण उपभोक्ता को दूर जाने की समस्याओं से मुक्ति मिले और प्रखंड मुख्यालय में जाकर अपने बिजली के मीटरों की जो शिकायत है उसका निवारण करवा सकें ।

अध्यक्ष: स्थान ग्रहण किया जाय ।

श्री सिद्धार्थ पटेल: माननीय मंत्री बिजेन्द्र बाबू के प्रति आभार, जय बिहार ।

अध्यक्ष: माननीय सदस्य श्री अवधेश सिंह अपना पक्ष रखें । आपका समय 8 मिनट ।

श्री अवधेश सिंह: अध्यक्ष महोदय, आज मैं अनुदान मांग के विरोध में जो कटौती प्रस्ताव आया है उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं । बिजली के क्षेत्र में काम बिहार में हुआ है इसमें कोई दो राय नहीं है, बिजली के लिए अपने गांव से बीघा में जमीन बेचकर और कट्ठा में लोग शहरी क्षेत्र में जमीन खरीदते थे कि थोड़ी देर बिजली हमको मिल जाय, आज गांव में भी बिजली है इसमें कोई दो राय नहीं है लेकिन जितना काम हुआ है उससे लोगों की अपेक्षा भी बढ़ती है, आज जो बिजली गांव में है अगर कहीं आंधी छोड़ दीजिए, अगर कहीं तेज हवा आती है या हल्की बारिश होती है तो एक से दो दिन के लिए बिजली बाधित होती है तो विभाग को, माननीय मंत्री जी को जरूर देखना चाहिए कि बिजली हम कैसे लगातार आपूर्ति कर सकें, उपभोक्ताओं को हम बिजली लगातार दे सकें । एक दिन में, जैसे हम हाजीपुर से आते हैं, एक दिन अगर कार्यालय में हमलोग दिनभर बैठते हैं, 7-8 घंटे बैठते हैं या 10 घंटे बैठते हैं दर्जनों बार बिजली ट्रिप होती है, क्या तकनीकी कठिनाई है, प्रॉब्लम है विभाग को यह देखना चाहिए । कई छोटी-छोटी समस्याएं हैं, बड़ी-बड़ी कंपनियों को काम मिल गया है, बड़ी कंपनियां हमारे यहां आईं, विधायक लोगों को न कोई सूचना दी जाती है न कुछ बताया जाता है विभाग की

तरफ से उनलोगों ने जो चौड़ी सड़कें थीं वहां केबलिंग का कार्य कर दिया और जो गरीबों की बस्तियां हैं, जो साढ़े तीन फीट, चार फीट की जो गलियां हैं वहां हमलोगों को लगा कि शायद बाद में केबलिंग का कार्य करेगा लेकिन केबलिंग का कार्य बाद में उसने बताया कि 70 कि0मी0 था, हमारा तो पूरा हो गया है तो वह बस्तियां आज भी बिजली उसमें बांस-बल्ला से गया है विभाग को जरूर देखना चाहिए । हम कोरोना काल से पहले सी0एम0डी0 साहब से भी मिले थे, आग्रह किए थे कि जो टुबुलर पोल होता है, बड़ा वाला जो पोल होता है वह गलियों में जाना संभव नहीं होता है, पॉसिबल नहीं होता है तो टुबुलर पोल की खरीदगी भी हुई, हमको बताया गया कि आपके यहां टुबुलर पोल आ गया है जाकर देख लीजिए। जब जाकर देखे तो विभाग के जो भी बड़े पदाधिकारी उसको देख रहे थे, वह जो सीमेंट वाला पोल है उससे भी बड़ा-बड़ा पोल खरीद कर आ गया तो जो गरीब के बस्ती में भी बिजली जो आज भी खंभों के द्वारा या अपना निजी बांस गाड़कर लोग ले गया है तो उसके द्वारा जो बिजली वहां आज भी लगता है कि एक जाल की तरह, वह तार का जाल बना हुआ है तो निश्चित रूप से सरकार को इसपर विचार करना चाहिए । यह आग्रह आपके माध्यम से हम सरकार से, माननीय मंत्री जी से करना चाहते हैं और बिजली बिल में जो गड़बड़ी की शिकायत है वह तो सत्ताधारी दल के लोग भी जो अभी बोल रहे थे सिद्धार्थ जी वह भी बता रहे हैं और बिजली बिल में गड़बड़ी की शिकायत एक तो होता क्या है कि गरीबों को तीन-तीन साल जब कनेक्शन मिले हुए हो जाता है तो उसको बिजली के कनेक्शन का बिल नहीं आता है, तीन साल के बाद में एकमुस्त बिल आता है तो जो गरीब ठीक हैं, जो सक्षम लोग हैं, सबल लोग हैं उनके लिए तो लाख भी कोई बड़ी चीज नहीं है लेकिन उसके यहां अगर हजार का ही बिल आ जाता है 10 हजार, 20 हजार, 25 हजार तो बड़ी कठिनाई उपभोक्ता को झेलनी पड़ती है, यह जरूर ध्यान हमलोगों को रखना चाहिए, माननीय मंत्री जी से आग्रह करेंगे कि समय से उसका बिल जाना शुरू हो जाय कि समय से, आज ऐसा नहीं है आज से 10 साल पहले अगर बिजली कम रहती थी तो बिल कितना जमा होता था वह भी हमलोग देखते थे । अब तो कस्टमर लाइन लगाकर या मोबाइल का जो सिस्टम आया है, जो ऐप आया है उसपर लोग बिजली का बिल भी समय से जमा करना चाह रहे हैं । तो आग्रह जरूर होगा कि गरीब, चूंकि सही बात है कि हमलोग जाते हैं तो वह बताते हैं कि चप्पल घिस गया, ऐसे तो बाकी कई विषयों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष, सत्ता पक्ष कहता है जैसे लगता नहीं है काम ओवरफ्लो हो गया, सत्ता पक्ष के लोग कहते हैं काम ओवरफ्लो हो गया, विपक्ष के लोग कहते हैं कोई काम हुआ ही

नहीं लेकिन फैक्ट है कि बिजली के क्षेत्र में जो काम हुआ है माननीय मंत्री जी को हम बधाई, धन्यवाद भी देते हैं और केंद्र सरकार की योजनाएं जो हुआ है बड़े स्तर पर भारत की सरकार ने पंडित दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना में पैसा दिया तो उससे भी वे लोग इनकार करते हैं, हमको लगता है कि.....

श्री नंद किशोर यादवः महोदय, मेरे बगल में रहते हैं बिजेन्द्र बाबू इसलिए बिजली का काम होता है, ऐसे नहीं होता ।

अध्यक्षः माननीय नंद किशोर बाबू, बहुत सही तरीके से आपके माननीय सदस्य बोल रहे हैं ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्रीः और सच्चाई बोल रहे हैं जो अभी उन्होंने माननीय मंत्री जी के बारे में नंद किशोर बाबू ने जो कहा कि इनके बगल में रहते हैं इसीलिए सब ठीक-ठाक हो रहा है इसका मतलब तो यह भी स्पष्ट है अपने सदस्यों को बता दीजिए कि जो नहीं हो रहा है वह भी आपही के कारण नहीं हो रहा है ।

श्री अवधेश सिंहः कुछ शिकायत अगर करना भी होता तो एक तो बिजेन्द्र बाबू हमलोगों के.....

अध्यक्षः सरकार के विद्युत विभाग में जो काम माननीय मंत्री जी ने किया है, माननीय सदस्य उसका समर्थन कर रहे हैं ।

श्री अवधेश सिंहः माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर कोई शिकायत भी करना होता तो एक तो.....

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्रीः महोदय, ये बेईमानी कर रहे हैं, पड़ोसी को बेईमानी करने की आदत है । यह सो नहीं कह रहे हैं यह कह रहे हैं कि मेरे बगल में हैं इसीलिए हो रहा है ।

श्री अवधेश सिंहः एक तो बिजेन्द्र बाबू अभिभावक भी हैं, गार्जियन भी हैं और बगल में विजय बाबू भी बैठे हुए हैं । एक तो बिजेन्द्र बाबू का जो अपनों के प्रति जो खौफ है मतलब सदन के किसी दल के सदस्य नहीं हैं जो डरते नहीं हैं चूंकि जब वह बिगड़ते हैं तो पूरी ईमानदारी से बिगड़ते हैं और बगल में विजय बाबू बैठे हुए हैं तो फिर बहुत.....

अध्यक्षः अभिभावक की इज्जत होनी चाहिए ।

श्री अवधेश सिंहः बिल्कुल है, और पहले गांव में लाइनमैन होता था, बिजली कर्मी जब रिटायर होते चले गए तो अनुबंध पर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, मानव बल जो काम कर रहा है उसको 8 हजार रुपये की तनख्वाह और घर से 50-50, 60-60 कि0मी0 दूर उनका ट्रांसफर कर दिया जाता है उस स्थिति में बड़ी कठिनाई होती है, या तो उनको कुछ ऐसा कर दिया जाय कि जहां के वे रहनेवाले हों चूंकि रात में भी अगर बिजली का तार गिरता है तो लोग उसी को फोन करते हैं और जो केबलिंग का कार्य जो विभाग करती है और अभी फिर नया काम शुरू होनेवाला है. .....

अध्यक्षः आपका समय समाप्त हुआ ।

श्री अवधेश सिंहः बहुत-बहुत धन्यवाद ।

अध्यक्षः श्री आनंद शंकर सिंह, अपना पक्ष रखें । आपका समय 14 मिनट ।

श्री आनंद शंकर सिंहः मान्यवर, बहुत-बहुत धन्यवाद । आज ऊर्जा विभाग के अनुदान मांग के पक्ष में मुझे बोलने का मौका मिला इसके लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, अपने दल के नेताओं का, महागठबंधन के नेताओं का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा ।

(इस अवसर पर माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

निश्चित रूप से हमारे साथी सरावगी जी बोलकर निकल गए और उन्होंने बहुत अच्छी-अच्छी बातें कहीं जिसमें एक यह भी कहा कि माल महाराज का मिर्जा खेले होली, डब्लू बाबू ने अपनी बातों से उनको बताया कि कौन मिर्जा है होली खेल रहा है । आरा के वे मिर्जा हैं जो होली खेल रहे हैं औरंगाबाद के एन0टी0पी0सी0 के माल का । तो यह बताया उन्होंने आपको, निश्चित रूप से इस चीज का गुमान आपको नहीं होना चाहिए, आपलोगों ने कई बार पंडित दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का जिक्र किया । माननीय महोदय आपको यह भी समक्षना चाहिए कि यू0पी0ए0 सरकार की योजना थी जिसका नाम केवल बदलकर राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना थी जिसका नाम बदलकर आप उसकी वाहवाही लूटने की कोशिश में हैं ।

(क्रमशः)

टर्न-16/अंजली/17.03.2023

श्री आनंद शंकर सिंह (क्रमशः) : और ऐसी ही नहीं, ऐसी 32 योजनाएं हैं जो यू0पी0ए0 सरकार के द्वारा प्रदत्त रहीं और उनका नाम बदलकर आप वाहवाही लूट रहे हैं । योजनाओं की एक लंबी सूची है । ये जो आप ढोल पीट रहे हैं कि ''माल महाराज का मिर्जा खेले होली'', माल तो यू0पी0ए0 सरकार की थी और आप होली खेलने के चक्कर में लगे हैं तो ये भी समझिए,

''कोई भी शाख किसी की मिल्कियत नहीं होती,
जहां परिंदा बैठ जाय वहीं ठिकाना होता है,
आप करते रहिए अपने सूरज का हिसाब,
हमें तो हर घर तक बत्ती जलाना है ।''

उस ओर हमारी सरकार अग्रसर है और हर गांव में, हर घर तक बत्ती पहुंचाने का काम, बिजली पहुंचाने का काम हमारी सरकार कर रही है । डाटा दिया उन्होंने अगस्त 2022 का, सरावगी जी को इतना सोचना चाहिए था कि 2022 में तो आप भी महाराज सरकार में थे और आपका उस समय इतना क्यों कम रेटिंग आ गया,

आप भी सरकार में थे, आपका भी दायित्व बनता है, आप उस दायित्व से भाग कैसे सकते हैं, आपको यह समझना चाहिए और आप तो दायित्व से भागे ही, सदन से भी भाग गए बोलकर, कम से कम सुनने की क्षमता रहनी चाहिए थी । जहां तक बात है मैं तो यह कहना चाहता हूं कि महात्मा गांधी जी ने कहा था कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है । गांव में जब बसती है तो गांव के लोगों को बिजली पहुंचाने का लक्ष्य महागठबंधन की सरकार की हो, चाहे हमारी यू0पी0ए0 की सरकार हो जिस समय ये योजनाएं बनीं तो गांव-गांव तक बिजली पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया और उसमें हम सफल भी हुए लेकिन आप लोगों ने जो अच्छे दिन का वादा जो किया, मूवी में एक सीन था ''गंगा बोलकर गंदी नाली में कूदा दिया'', तो वही कहानी है आपलोगों की, अच्छे दिन का वादा करके आप लोग देश को नर्क में ले जाने का काम कर रहे हैं और उसके बाद आपको वाहवाही चाहिए । कोई एक ऐसा काम बताइए जो आप लोगों का अपना हो, चाहे अमृत काल की बात आप करते हैं वह भी आपका अपना नहीं । ये सारी चीजें तो आप लोगों ने यू0पी0ए0 सरकार से एडाप्ट की और उसकी वाहवाही लेने के चक्कर में आप लगे हुए हैं तो एक बार जब अपना भाषण दीजिए तो जरूर यू0पी0ए0 सरकार को धन्यवाद दीजिए कि आपके बताए हुए रास्ते पर हम चलने का काम कर रहे हैं, कांग्रेस सरकार को धन्यवाद दीजिए कि आपके बताए रास्ते पर चलने का काम कर रहे हैं । आप लोग तो माफी वीर हैं, यूटर्न वीर हैं, जी0एस0टी0 का विरोध किए, जी0एस0टी0 ले आए, नोटबंदी का विरोध किए, नोटबंदी ले आए, काला धन लाने का वादा किए, काला धन कहां गया किसी को पता नहीं ? एक गांधी थे सूट-बूट छोड़कर, अच्छे वकील थे बैरिस्टर थे, सूट-बूट छोड़कर धोती-लंगोट पर चले आए, लाठी लेकर आए और भारत को आजाद करा दिए और एक हमारे चाय बेचने वाले हैं फकीर थे, अब सूट-बूट पहन लिए और पूरे देश को बेचने का काम कर रहे हैं। अडानी और अंबानी इसके एग्जांपल है आपके लिए और गांव को बेचने का काम...

(व्यवधान)

किसका पैसा एस0बी0आई0 में जमा होता है, किसका पैसा एल0आई0सी0 में जमा होता है थोड़ा बताइएगा हमको ? गरीब व्यक्ति अपना पेट काट-काटकर एल0आई0सी0 में पैसा जमा करता है, एस0बी0आई0 में पैसा जमा करता है और उस पैसे को आप लोग अडानी और अंबानी को देने का काम रहे हैं थोड़ा इस पर भी विचार कीजिए कि गांव के लोगों का आपने क्या हाल कर दिया । महोदय, इसलिए बोल रहे हैं कि ऊर्जा विभाग, 80 प्रतिशत आबादी गांव में बसती है और उन गांव के लोगों का आपने कैसे जीना मुहाल कर दिया और हमारी सरकार ने

बिजली, बत्ती पहुंचाकर लोगों के जीवन को आसान किया, आपलोगों को यह अंतर समझाने का मैं काम कर रहा हूं, समझिए इस अंतर को, इस अंतर को समझिए । इस देश में केवल ऊर्जा, केवल ताप विद्युत घर से नहीं है, इस देश के नौजवानों की ऊर्जा को बर्बाद करने का काम आप कर रहे हैं, धर्म की चाशनी में लपेटकर इस देश की ऊर्जा को बर्बाद करने का आप काम कर रहे हैं ।

''बांट दिया इस धरती को,
चांद सितारों का क्या होगा,
नदियों के कुछ नाम रखे,
बहती धारों का क्या होगा,
और शिव की गंगा भी पानी है,
अबे जम जम भी पानी है,
मुल्ला भी पिए, पंडित भी पिए,
पानी का मजहब क्या होगा,
और इन फिरकापरस्तों से पूछो
क्या सूरज अलग बनाओगे,
एक हवा में सांस है सबकी
क्या हवा भी नहीं चलाओगे ।''

धर्म की चाशनी में लपेटकर आपने देश को बांटने का काम किया है । जहां तक ऊर्जा विभाग के संबंध में जो बातें हैं निश्चित रूप से मैं इस बात की तारीफ करूंगा, इस सरकार की तारीफ करूंगा कि...

(व्यवधान)

बातों को कम से कम सुनने का धैर्य होना चाहिए । जब आपने बोला तो मैंने उसमें टीका-टिप्पणी नहीं की थी, कम से कम बातों को सुनिए । विनय बिहारी जी ने बहुत अच्छी-अच्छी बातें कहीं, उनको जब हमलोगों ने सुना और हमारे तो स्पीकार साहब ने, विजय चौधरी जी ने वाहवाही भी दी, तो हमलोगों की भी बातों को भी सुनिए, सच थोड़ा तकलीफदेह हो सकता है, पीड़ादायक हो सकता है लेकिन सच, सच ही होता है, इसलिए सुनिए ।

उपाध्यक्ष : शांति-शांति । माननीय सदस्य को बोलने दीजिए ।

श्री आनंद शंकर सिंह : विद्युत आपूर्ति की जो गुणवत्ता थी...

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बोलिए ।

श्री आनंद शंकर सिंह : महोदय, जो गुणवत्ता थी, उसमें कहीं-न-कहीं बढ़ोतरी हुई है । शहरों में 23 से 24 घंटे विद्युत आपूर्ति की जा रही है, गांवों में 21 से 22 घंटे आपूर्ति की जा रही है । मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मुख्यमंत्री महोदय को, उप मुख्यमंत्री महोदय को और हमारे ऊर्जा मंत्री जी को जिन्होंने यह विजुलाइज किया जो देश...

उपाध्यक्ष : शांति-शांति । माननीय सदस्य आप बोलिए ।

श्री आनंद शंकर सिंह : भारत के शीर्ष पर बैठे आप लोगों के जो आंका हैं, जिन्होंने बाद में विजुलाइज किया, उसको विजुलाइज हमारे मुख्यमंत्री जी ने पहले कर लिया और जल जीवन हरियाली योजना के रूप में, सभी विपक्ष के दलों को बैठाकर एक निर्णय लिया गया जिसमें हर खेत को पानी पहुंचाने का, वृक्षारोपण करने का, सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए ऐसी योजनाएं...

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष : शांति-शांति, गलत बात है । सभी माननीय सदस्य शांत रहें, माननीय सदस्य को बोलने दीजिए ।

श्री आनंद शंकर सिंह : महोदय, बिहार ने आप लोगों को मार्गदर्शन देने का काम किया है उसके मार्गदर्शन पर चलिए ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष : बोलने दीजिए न, वे बोल रहे हैं । जब आपका समय आएगा तो आप बोलिएगा । बोलिए-बोलिए, आप बोलिए ।

श्री आनंद शंकर सिंह : मान्यवर, ये गुजरात वाला मॉडल पूरे देश में लागू करने चले हैं, जिस तरह गुजरात के संसाधनों का उपयोग अडानी और अंबानी के द्वारा इन लोगों ने कराया, वैसा ही उपयोग, वैसा ही रिसर्च ये इस देश पर कर रहे हैं और देश को गर्त में ले जाने का काम ये लोग कर रहे हैं । अडानी और अंबानी की बात कर रहे हैं आप, गुजरात वाले मॉडल का प्रयोग पूरे देश पर मत कीजिए, आपलोग देश को बेचने का काम कर रहे हैं, चाय बेचने वाला आया और पूरा देश बेच के चला गया बताइए, 15-15 लाख का सूट पहना, चाय बेचने वाले को सूट जंचेगा । अरे देह जल जाना चाहिए था जिस समय 15 लाख का सूट धारण किए होंगे, देह गल जाना चाहिए था उस समय, आम जनता की गाढ़ी कमाई को 15 लाख रुपया का सूट पहनकर देह गल जाना चाहिए था, जिस तरह 15 लाख सूट पहने होंगे वे । आम जनता की गाढ़ी कमाई को लूटकर, इस देश के जो शीर्ष पर बैठै नेता हैं वे 15 लाख का सूट पहन रहे हैं और आप यहां बैठकर भाषण दे रहे हैं ।

उपाध्यक्ष : आनंद शंकर जी, कुछ बजट पर भी बोलिए ।

श्री आनंद शंकर सिंह : इसलिए इस बात को समझिए, हर खेत को पानी देने का काम हमारी सरकार कर रही है, ट्रांसफार्मर देने का काम सिंचाई के लिए हमारी सरकार कर रही है उसका लाभ लीजिए और खेती करिए, केवल नगरों में बसकर, नगर के लोगों को केवल देखकर काम मत चलाइए, ये बी0जे0पी0 के लोग केवल नगर पर आधारित मत रहिए, गांव पर ध्यान दीजिए । हर खेत को सिंचाई के लिए पानी देने का काम, पृथक ग्रिड देने का काम हमारी सरकार ने किया उसका धन्यवाद दीजिए आप लोग ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बजट पर भी बोलिए ।

श्री आनंद शंकर सिंह : धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद दीजिए उस चीज का । महोदय, सौर ऊर्जा के विकल्प की ओर बिहार अग्रसर है और उस ओर पहल की जा रही है । मैं समझता हूं कि आगे आने वाला समय सौर ऊर्जा का होगा और अल्टरनेटिव जो ऊर्जा के स्रोत हैं, चाहे वह, आप और हम देख रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो नेतृत्व करने का काम किया है, इलेक्ट्रिक व्हीकल से उनका आना-जाना होता है विधान सभा में, निश्चित रूप से यह हम सभी लोगों के लिए सीख है । आगे आने वाला जो समय, समय रहते जो चेत जाए, तभी जाकर हम इस पृथ्वी को बचा पाएंगे, महात्मा गांधी जी ने तो उस समय ये बातें बोलीं, जिस समय इस देश की आबादी 35 करोड़ थी । उन्होंने क्या कहा ?

(क्रमशः)

टर्न-17/सत्येन्द्र/17-03-23

श्री आनंद शंकर सिंह(क्रमशः) उन्होंने यह कहा कि पृथ्वी सभी मनुष्यों की जरूरत पूरी करने के लिए पर्याप्त संसाधन प्रदान करती है लेकिन लालच पूरी करने के लिए नहीं । यह महात्मा गांधी का कोट है, उनका एक और कोट है-what we are doing to the forests of the world is but a mirror reflection of what we are doing to ourselves and to one another. यह गांधी जी ने कहा था और अगर उस गांधी जी में आप आस्था रखते हैं और गोडसे के आप पूजारी नहीं हैं तो गांधी के बताये रास्ते पर चलिये और इस भारतवर्ष को, जिस भारतवर्ष को विश्वगुरू बनाने की बात आप कर रहे हैं, उन अंग्रेजों की तरह मत कीजिये कि वह सूटबूट यहां पहनकर आया और लूटकर चले गये। चाय बेचने वाला का कपड़ा जो 15 लाख का सूटबूट पहनकर आया और देश को बेच रहा है, उस ओर मत जाईए बल्कि महात्मा गांधी जी के बताये रास्ते पर चलिये और इस देश का विश्वगुरू बनाने की बात करिये । विश्वगुरू देश ऐसे ही नहीं बनेगा, इसके

लिए महात्मा गांधी के रास्ते पर चलना पड़ेगा और महात्मा के हत्यारे की पूजा करने वाले लोग ये समझते हैं कि इस देश को विश्वगुरू बनायेंगे तो मैं नहीं मानता, कभी भी विश्वगुरू नहीं बनेगा यह देश..

उपाध्यक्ष: कंक्ल्यूड कीजिये, आपका समय समाप्त होने वाला है ।

श्री आनंद शंकर सिंह: महात्मा गांधी को मानिये, मेरा यही कहना है। महोदय, कुछ चीजों पर मैं अपना सुझाव देना चाहूंगा । शहरों में या गांव में जो 11 हजार वोल्ट का वायर खेतों से होकर क्रॉस करता है और वह व्यक्ति जिसकी जमीन होती है, वह घर बनाता है तो उसको 11 हजार का वायर हटाने के लिए शुल्क अदा करना पड़ता है। मैं इस ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि जिसकी जमीन है, वह घर बनाये या कोई भी यूटिलिटी में लाये, सरकार को इसकी जवाबदेही लेनी चाहिए। वह 11 हजार वाला तार हटाने का कॉस्ट जो लगता है वह सरकार वहन करे यह मैं कहना चाहता हूँ । दूसरी ओर जिस प्रकार से जो लोकल पदाधिकारी होते हैं, उनके विरूद्ध कोई कार्रवाई के लिए बात होती है तो पता चलता है कि कागज पटना भेजा गया है और उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है जिसका नतीजा यह होता है कि उनका मनोवल बढ़ता जाता है इसलिए कार्रवाई के लिए जिले में ही फोरम होना चाहिए ताकि वहीं कार्रवाई हो और पटना भेजने के नाम पर 6-6 महीना 12-12 महीना मामला अटका रहता है। हमारे यहां एक जे0ई0 का मामला है आपका गौतम कुमार सहायक अभियंता हैं, उनका एक विडिओ वायरल हुआ है जिसमें मुखिया और आमजनों को गाली गलौज कर रहे हैं, उन पर कार्रवाई का मामला अबतक लटका हुआ है इतने दिनों तक मामले लटकेंगे तो कहीं न उनका मनोवल बढ़ेगा इसलिए मैं आग्रह करूंगा ऐसे पदाधिकारियों पर कार्रवाई के लिए कि जल्द से जल्द इसका रिड्रेशर हो..

उपाध्यक्ष: टाईम हो गया आपका, समय हो गया आपका ।

श्री आनंद शंकर सिंह: मैं यह आग्रह करूंगा जहां तक हमारे सदस्यों को मिर्ची लगी है तो उस मिर्ची का इलाज हमलोग क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं । धन्यवाद महोदय ।

उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, श्री वीरेन्द्र कुमार । 8 मिनट आपका समय है ।

श्री बीरेन्द्र कुमार: आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, हम आभार व्यक्त करते हैं अपने सचेतक मान्यवर जनक जी को जिनके माध्यम से आपने मुझे समय दिया हैं। महोदय, आज ऊर्जा विभाग पर चर्चा है । महोदय, जो आज यहां बिजली दिखायी पड़ रही है, वह वाजपेयी के समय डॉ0ए0पी0जी0 अब्दुल कलाम के पीरियड में जो रचना बनी, उन्होंने कहा था कि बिजली हम इतनी उपलब्ध करा देंगे कि लोग शौक से मोमबती

जलाया करेंगे और आज लोग शौक से मोमबती जला रहे हैं। हम आभार व्यक्त करते हैं अपने क्षेत्र की जनता को जिनके माध्यम से मुझे यहां आने का मौका मिला। आज 115 अरब 36 करोड़ 83 लाख 67 हजार का जो बजट सरकार लायी है और यह बिहार प्रदेश जहां पर दुनिया का 18 प्रतिशत पानी है वहां पर आज भी यह प्रदेश ताप के बिजली पर आधारित है इसलिए इस प्रस्ताव के माध्यम से बजट में कटौती करनी चाहिए । महोदय, लाखों क्यूसेक पानी प्रत्येक वर्ष नदी के माध्यम से समुद्र में चला जाता है लेकिन हम आज भी ताप बिजली पर ही आधारित हैं । महोदय 24 करोड़ का डागमारा प्रोजेक्ट बनाया गया था और इसके लिए पांच साल का समय रखा गया था फिर भी वह पूरा नहीं हुआ । अध्यक्ष महोदय, अगर डागमारा प्रोजेक्ट पूरा हो जाता तो पानी के माध्यम से बिजली भी पैदा होती और इससे लाखों किसानों को, सैकड़ों नौजवानों को नौकरी भी मिलता लेकिन बिहार सरकार की अकर्मण्यता के कारण वह प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ । आज कई साथी हल्ला करते हैं, बात मुद्दत की थी, जो गयी सो बीत गयी, जरा खुले में सांस तो ले लें और व्यक्ति की परिभाषा संबंध के आधार पर तय की जाती है, व्यक्ति की परिभाषा कोई मानक परिभाषा नहीं है। हम उस ओर रहते हैं तो सरकार का समर्थन करते हैं और इस ओर आते हैं तो सरकार का विरोध करते हैं लेकिन जनहित के मुद्दे पर विपक्ष की बात को सुननी चाहिए। महोदय, आज कोशी प्रोजेक्ट को ही लें जिस समय कोशी प्रोजेक्ट योजना चल रही थी और हमारे माननीय अभिभावक विजेन्द्र बाबू उसी क्षेत्र से आते हैं, क्षेत्र बहुत खुशहाल हो रहा था, मजदूरों का पलायन रूक रहा था, किसानों को समय समय पर पानी मिलती थी लेकिन आज उस प्रोजेक्ट का चलाने के लिए बाहर से बिजली लेनी पड़ती है जिससे वहां ताप विद्युत के माध्यम से हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट को चलाने का काम किया जा रहा है। अगर पानी का हम शत प्रतिशत उपयोग करेंगे तो हर खेत को पानी मिलेगा, हर हाथ को काम मिलेगा । आज मुख्यमंत्री जी चर्चा करते हैं कि हम सात निश्चय-2 के माध्यम से हर किसान को पानी उपलब्ध करायेंगे लेकिन सात निश्चय 2 के माध्यम से जो हमारे पास नदियों की पर्याप्त संख्या है, पानी का जो प्रचुर मात्रा है उसका उपयोग करके अगर हम हर खेत को पानी देने का काम करते तो हर नौजवानों को रोजगार भी मिलता और किसानों को लहलहाती फसल भी मिलती । महोदय, किसानों के बारे में कहा गया है कि किसानों के हाथ अगर ढीले हुए तो ऋषि मुनि की तपस्या भी व्यर्थ है । आज असंगठित क्षेत्र में देश ही नहीं, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा रोजगार का अवसर किसान के माध्यम से दिया जाता है लेकिन किसान आज के दिन में फटेहाल हैं । महोदय, आज पूरे बिहार में धान की

जो खेती की गयी, वह मात्र 32 प्रतिशत खेती किया गया लेकिन 94 प्रतिशत लोग अनुदान प्राप्त कर रहे हैं । कृषि पदाधिकारी ब्योरा देत हैं कि हम मोटा अनाज की खेती 280 हेक्टेयर में समस्तीपुर जिले में कराते हैं और जब कृषि पदाधिकारी से पूछा जाता है चिनाकौनी का नाम बताईए, जो किसान उत्पादन किया है उन चार किसान का नाम बताईए लेकिन साल भर में कृषि पदाधिकारी के पास नाम तक नहीं पहुंचता है । इस प्रकार इस नाम से जो पैसों का बंदरबांट किया जाता है और सरकार के माध्यम से सरकारी पदाधिकारी जो पैसों का बंदरबांट करते हैं, उसकी थाह लगाना बहुत मुश्किल है । जैसे पानी के अंदर रहने वाले मछली का अंदाज लगाना मुश्किल है कि वह पानी पी रही है या नहीं पी रही है, इसी प्रकार सरकार के संरक्षण में जिस तरह से खुलेआम क्प्सन हो रहा है, उसका जीता जागता उदाहरण इस सदन के अंदर भी दिखता है। आज जिनके मेहनत के कारण हम स्वच्छ वातावरण में सदन के अंदर रहते हैं उनका भी शोषण होता है । मात्र 6 हजार रू0 में उसे 12 घंटा का ड्यूटी इस सदन के अंदर लिया जाता है और सदन के बाहर की बात क्या होगी, उसका अंदाजा लगाना मुश्किल है । जैसे पानी के अंदर मछली पानी पीती है कि नहीं पीती है उसका अंदाज लगाना मुश्किल है...

उपाध्यक्षः अब कंक्ल्यूड कीजिये, 2 ही मिनट बचा है ।

श्री बीरेन्द्र कुमारः माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज बिजली की जो है, आज खुदी राम बोस के नाम पर भी जो करोड़ों रू0 बिजली का बिल भेजा जाता है और गरीब किसानों को जो है प्रीपेड मीटर लगाने के नाम पर डराया जाता है । आज किसान 3-3 साल से औफिस में दौड़ रहे हैं लेकिन उनको बिजली का मीटर नहीं दिया जा रहा है और सरकार की जो योजना है, वह वहां पर असफल साबित हो रही है। आज सड़क चौड़ी हो रही है । बिजली का खम्भा सड़क पर रहता है जिसके कारण सैंकड़ों नौजवानों का परिवार समाप्त हो गया, समय पर सरकार का ऊर्जा विभाग उस बिजली के खम्भे को समय पर हटाने का काम नहीं करती है । महोदय, हम आपके माध्यम से हम आग्रह करते हैं माननीय विजेन्द्र बाबू से कि जिस हिसाब से सड़क चौड़ी हो रही है, उसी हिसाब से त्वरित आधार पर सड़क पर जो बिजली का खम्भा खड़ा है, उस खम्भा को भी हटाने का काम करेंगे।(क्रमशः)

टर्न-18/मधुप/17.03.2023

...क्रमशः...

श्री बीरेन्द्र कुमार : आज जबतक सरकार ताप विद्युत को विकल्प के रूप में, हाइडेल इलेक्ट्रिक प्लांट का विस्तार नहीं करती है, इस कटौती प्रस्ताव के माध्यम से हम बजट में

कटौती की अनुशंसा करते हैं । इन्हीं बातों के साथ हम अपनी बात को समाप्त करते हैं ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री अमरजीत कुशवाहा । 9 मिनट है आपका ।

श्री अमरजीत कुशवाहा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ । साथ-ही-साथ, पार्टी विधायक दल के नेता महबूब आलम साहब का, सचेतक अरूण जी का और देशरत्न भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद की महान धरती जीरादेई से महान जनता ने चुनकर हमें भेजा है, मैं उन सबका आभारी हूँ ।

महोदय, मैं विपक्ष द्वारा रखे गये कटौती प्रस्ताव के विरोध में बोलने के लिए खड़ा हूँ । महोदय, आज का जो विषय है ऊर्जा, मद्य निषेध, योजना एवं विकास तथा विधि विभाग लेकिन मेरा ज्यादा से ज्यादा जोर जो होगा, मैं ऊर्जा पर ही रखना चाहता हूँ और यह बात साफ है, बहुत देर से मैं चर्चा सुन भी रहा था कि बिहार माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिजली के क्षेत्र में एक मुकाम हासिल किया है और आज हमलोग देख रहे हैं कि चाहे विपक्ष के लोग जितना भी हल्ला करें, कल तक ये लोग इधर थे तो प्रशंसा करते नहीं थकते थे और आज आलोचनाओं का अंबार खड़ा कर रहे हैं । आज भी 22 घंटा बिजली बिहार को मिल रही है, यह सराहनीय कदम है और साथ-ही-साथ, ऊर्जा के जो अन्य स्त्रोत हैं, सिर्फ इतने की जरूरत नहीं है, ऊर्जा के जो अन्य स्त्रोत हैं, उसकी भी तलाश बिहार में की जा रही है । अभी कई माननीय सदस्यों ने रखा कि सोलर प्लेट के द्वारा विद्युत उत्पादन की जो योजना बिहार सरकार ने ली है, यह मैं समझता हूँ कि बहुत ही सराहनीय कदम सरकार का है । लेकिन इसके बावजूद और भी जो बिहार के प्राकृतिक संसाधन हैं जैसे इन्द्रपुरी जलाशय योजना के तहत 350 मेगावाट बिजली उत्पादन की योजना है । अगर शीघ्र उसे करा दिया जाय तो बिहार बिजली के उत्पादन में और आगे बढ़ेगा । उसी तरह से उत्तर बिहार के अंदर नदियों से बिजली उत्पादन के कार्य को बढ़ाया जाय तो इससे ज्यादा विद्युत का उत्पादन होगा और बिहार आत्मनिर्भर होगा । मैं समझता हूँ कि बिहार अपने संसाधनों से पिछड़ा हुआ राज्य होने के बावजूद आगे बढ़ रहा है लेकिन इसके साथ-ही-साथ, हमलोग गाँव में जब जाते हैं और सुनते हैं, कुछ समस्याएँ भी जो हैं सामने उभर कर आती हैं । महोदय, उसमें हमलोग देखते हैं कि यह बिहार की जो हमारी सरकार है खास करके विपक्षी सदस्यों के हटने के बाद 6 महीना से जो सरकार चल रही है, इस सरकार से बिहार की जनता की अपेक्षाएँ, जब ये लोग थे तो ज्यादा उम्मीद लोगों की नहीं थी लेकिन आज उम्मीद ज्यादा लगी है और इसलिए हम माननीय मंत्री जी से कहेंगे कि उन उम्मीदों को हर घर में, हर गरीबों के घर में बिजली कैसे पहुँच

जाय इसपर विशेष जोर देकर सोचने की जरूरत है । लेकिन जो व्यवहार में हमलोग देखते हैं कि बी0पी0एल0 के तहत जिनको विद्युत कनेक्शन मिला है, विभागीय लापरवाही की वजह से होता यह है कि लम्बे समय के बाद बिल आ रहा है और उसमें चक्रवृद्धि ब्याज जोड़कर बिल आ रहा है । महोदय, मैं कहना चाहता हूँ कि यह सुधारने की चीज है, इसमें प्रक्रिया भी चल रही है । कैम्प लगाकर, एक सप्ताह में कैम्प लगे और बी0पी0एल0 परिवार का जो बिल आया है, सरकार को उसे माफ कर देना चाहिए और नये सिरे से उनका बिल जोड़ा जाना चाहिए । साथ-ही-साथ, बिल में जो गड़बड़ी हो रही है उसको भी त्वरित सुधार करके लेना चाहिए । बहुत सारे दलित बस्तियों में सामूहिक रूप से बिजली काट दिया जाता है, हमलोगों के पास लोग शिकायत करते हैं, इसपर महोदय से आग्रह होगा कि जरूर विभाग गंभीर हो ।

दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि बिहार का जो प्रति व्यक्ति आय का जो सूचकांक हमने देखा है, मात्र 55 हजार रू0 बिहार का प्रति व्यक्ति आय है और पंजाब का हमलोग जब देखते हैं तो 1.5 लाख प्रति व्यक्ति आय है । पंजाब जैसे राज्य अपने लोगों को बिजली फ्री दे सकता है तो एक लोकप्रिय सरकार से हमारा आग्रह होगा कि बिहार के गरीब और किसानों को, दलितों को कम से कम 200 यूनिट बिजली फ्री देना चाहिए ।

महोदय, मैं दूसरी बात जो कहना चाहता हूँ, हमारे विपक्ष के लोग कह रहे थे, बहुत सारी बात कह रहे थे, मैं तो कहूँगा कि देहाती कहावत है कि सूप हँसे तो हँसे, चलनी का हसीं जेकरा में सहत्तर गो छेद है । इसलिए मैं कह रहा हूँ महोदय, ऊर्जा का सिर्फ और सिर्फ साधन बिजली पर हमलोग चर्चा कर रहे हैं लेकिन ऊर्जा का एक जो सबसे महत्वपूर्ण साधन है, वह है पेट्रोलियम, गैस । मैं विपक्ष के लोगों से मैं पूछ रहा हूँ कि उसका हाल तो जरा बता दीजिए । कहाँ आपने पहुँचाया है ? जब 2014 में ये लोग सत्ता में आये थे तो 110 डॉलर प्रति बैरेल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोलियम की कीमत थी, कच्चे तेल की कीमत थी । आज भी अगर आंकड़ा उठाकर देखें तो उससे नीचे आया है और उस समय जो हमारे देश में डीजल की कीमत थी, वह 55.49 रू0 था, इन लोगों ने शतक मरवा दिया । क्या इन लोगों को कुछ कहने का हक है ? शतक मरवाया है डीजल में, पेट्रोल में और मैं तो कहना चाहता हूँ कि इनकी एंटी-मुस्लिम पॉलिटिक्स जो है, हमारे अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध हैं उसमें दरार लाया है और गैस पाईपलाईन जो पाकिस्तान के रास्ते आकर हमारे देश में सस्ते गैस मिल सकते थे, इसी की वजह से नहीं आ रहा है और आज मैं पूछना चाहता हूँ । ये हल्ला कर रहे थे कि गैस

का दाम बढ़ गया, स्मृति ईरानी जी से पूछिये सिलेन्डर मूड़ी पर लेकर हंगामा कर रहीं थीं, उस समय 400 रू0 सिलेन्डर का कीमत था और आज 1200 रू0 हो गया है । मैं पूछना चाहता हूँ कि ये लोग बतायेंगे, कह रहे थे मोदी जी कि अच्छे दिन आयेंगे । क्या अच्छे दिन यही हैं ? ये अच्छे दिन हैं तो मैं तो कह रहा हूँ कि अच्छे दिन अपने घर में रखिये और हमारे पुराने दिन ही लौटा दीजिये ताकि गरीबों को कम से कम 400 रू0 में सिलेन्डर मिल जाता । आज तो मैं देख रहा हूँ, चिल्ला-चिल्लाकर कहते थे प्रधानमंत्री जी कि हमने तो गरीब महिलाओं को चूल्हा फूंकने से रोक दिया है । आज जाकर हाल पूछिये, आप लोग गाँव में तो रहते नहीं हैं, आज वह सिलेन्डर कोने में फेंक दिया गया है, वह जलाया नहीं जा रहा है । इनको जनता से कुछ लेना-देना है ? कुछ लेना-देना नहीं है । एकमात्र काम है अडानी का सेवा करना । महोदय, मैं कहना चाहता हूँ, ये लोग सुनेंगे नहीं, कोयला एक ऊर्जा का सबसे बड़ा स्त्रोत है । इनके प्रधानमंत्री जी पैरवी करने आस्ट्रेलिया गये थे अडानी साहब के लिए, श्रीलंका गये थे और उसमें शर्त रख दिया कि 25 परसेंट कोयला अडानी जी के कम्पनी से ही लिया जायेगा । अडानी जी कौन हैं ? वे बतायेंगे कि अडानी जी कौन हैं । वह अडानी जी वही हैं जिन्होंने जालसाजी करके हिन्दुस्तान में दुनिया के तीसरे नम्बर के पूँजीपति के रूप में आये थे और जब हिंडनबर्ग ने जाँच किया है तो 35 नम्बर पर चले गये और शेयर का बाजार इतना गिरा है । हम कहना चाहते हैं कि आप लोगों के पास एक ही उपाय है, कितना सच्चाई छिपाइयेगा ।

उपाध्यक्ष : अब आप कंक्लुड कीजिए ।

श्री अमरजीत कुशवाहा : एक शायर ने कहा है कि सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती है कभी कागज के फूलों से । महोदय, हमलोगों देखा है कि इनका काम सिर्फ और सिर्फ....

टर्न-19/आजाद/17.03.2023

उपाध्यक्ष : अब आप कनक्लूड कर दीजिए माननीय सदस्य ।

श्री अमरजीत कुशवाहा : महोदय, थोड़ा सा समय देंगे, अभी हमारा समय है । महोदय, मैं कहना चाहता हूँ .....

उपाध्यक्ष : अब आपका आधा मिनट समय मात्र है ।

श्री अमरजीत कुशवाहा : महोदय, मैं कहना चाहता हूँ कि ये सिर्फ अफवाह फैलाने का काम करते हैं । इसके अलावे कुछ नहीं करते । अभी तमिलनाडु में अफवाह फैलाया और देश के अन्दर नफरत का बीज बोया और लगातार ये लोग बीज बोते रहते है।

ये बीज बोने का फैक्ट्री हैं महोदय । ये लोग दंगा फसाद करते हैं, इनके लिए एक शेर है मेरे पास बशीर बद्र का है –

लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में,
और तुम्हें तरस नहीं आती है बस्तियां जलाने में ।

ये लोग पूरे देश में आग लगाते रहते हैं । मैं आप लोगों को सलाह दे रहा हूँ कि जब इन लोगों ने 1992 में इस देश के अन्दर झगड़ा करवा दिया था....

उपाध्यक्ष : अब समाप्त कीजिए ।

श्री अमरजीत कुशवाहा : उस समय हमलोगों ने एक नारा दिया था –

फिर से ना मस्जिद टूटे,
न फिर से अब देश बंटे,
धर्म के ठिकेदारों से कह दो,
काशी जाकर माला जपे ।

आप लोग काशी जाकर माला जपिए । महोदय, आप कह रहे हैं कि मेरा समय समाप्त है, मेरे अपने क्षेत्र का कुछ मांग है .....

उपाध्यक्ष : अब समाप्त कीजिए ।

श्री अमरजीत कुशवाहा : महोदय, मैं अपने क्षेत्र के कुछ मांग पत्र है, मैं चाहूंगा कि प्रोसिडिंग्स का पार्ट बना लिया जाय और उसको जोड़ लिया जाय ।

महोदय, मैं पढ़ दे रहा हूँ, थोड़ा सा मौका दीजिए ।

उपाध्यक्ष : अब समाप्त कीजिए ।

श्री अमरजीत कुशवाहा : आधा मिनट महोदय । बिहार से जुड़ा हुआ और इन लोगों से भी जुड़ा हुआ है । बिहार के गरीबों एवं किसानों को पंजाब की तर्ज पर 200 यूनिट फ्री बिजली दिया जाय.....

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री भीम कुमार सिंह ।

माननीय सदस्य, अब आप समाप्त कीजिए ।

श्री अमरजीत कुशवाहा : महोदय, बिजली बिलों पर चक्रवृद्धि ब्याज पर रोक लगा दिया जाय और 2020 बिजली बिल कानून उन लोगों ने जो बनाया है, उसे वापस लिया जाय..

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री भीम कुमार सिंह, आपका 10 मिनट समय है । अब समाप्त कीजिए, अब आप बैठ जाईए ।

श्री भीम कुमार सिंह : महोदय, ऊर्जा विभाग पर सरकार द्वारा प्रस्तुत मांग का समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं । महोदय, मैं अपनी ओर से अपने नेता परम आदरणीय श्री लालू प्रसाद जी एवं बिहार के लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी

और बिहार के उपमुख्यमंत्री माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का आभार प्रकट करता हूँ और गोह विधान सभा के महान जनता को मैं आभार प्रकट करता हूँ कि उन लोगों के प्रयास से इस सदन में मैं आपके समक्ष बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ।

महोदय, राज्य सरकार ने ऊर्जा के क्षेत्र में ऐतिहासिक काम किया है जिसकी मैं सराहना करता हूं और तमाम साथियों की बातों को मैंने सुना और आज बिहार में बिजली के क्षेत्र में नये-नये टेक्नोलॉजी के द्वारा हर गांव में, हर घर में बिजली पहुँच रही है । मैं अपने क्षेत्र के छोटी-मोटी क्षेत्रीय समस्याओं की ओर भी आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा ।

महोदय, मैं औरंगाबाद जिला अंतर्गत गोह विधान सभा क्षेत्र से आता हूँ, वहां बिजली पर आधारित कृषि कार्य होते हैं, जिससे खेती का कार्य होता है । लमसम वहां ज्यादा बिजली का खपत है और किसान को बिजली की अति आवश्यकता है । विभिन्न गांवों में कृषि कार्य हेतु तार, पोल और ट्रांसफार्मर की अति आवश्यकता है । गोह प्रखंड के बक्सर-पंचायत के ग्राम-मंजाठी, महरी, बक्सर, पंचाग बिगहा, मायापुर, बंदेया बिगहा, बनतारा-पंचायत के ग्राम-बनतारा, गोबिंद बिगहा, बेला, बिलारू मठिया, डहरू बिगहा, उपहारा-पंचायत के ग्राम-अरण्डा में पोल एवं बिजली की काफी जीर्ण-शीर्ण अवस्था है महोदय और वहां घटना भी हो गई है । कुछ लोग बिजली से आहत हुए हैं, जिनकी मृत्यु भी हो गई है । इसके अलावा भुरकुंडा-पंचायत के ग्राम-पिपरा, पिपराही एवं भौठाही झिकटिया-पंचायत के ग्राम घोंटा, खड़गपुर, खोरी खाप, नारायणपुर, बेदुला, थानापुर बाजारवर्मा पंचायत के ग्राम-बाजारवर्मा, दुल्हा बिगहा, दधपी-पंचायत के ग्राम दधपी सरसोल डिहुरी पंचायत के ग्राम-डिहुरी त्याप-पंचायत के ग्राम-त्याप, परासी, हमीदनगर हथियारा-पंचायत के ग्राम भिमलीचक, दुलारबिगहा, मिरपुर-पंचायत के ग्राम-मीरपुर, कलुट बिगहा, भलूवार, डढ़वा, फाग-पंचायत के ग्राम डिंगराही, सागरपुर, हसामपुर पंचायत के ग्राम-मियांपुर, बुधई, हरिगांव, अमारी-पंचायत के ग्राम-अमरपुर, अनंत बिगहा, मलहद पंचायत के चपरा, नम्हूबिगहा, झगरूपिपर, सुग्गी बेला, हसपुरा प्रखंड के डिंडिर पंचायत के ग्राम-बघोई, निलकोठी, दिलावरपुर, मेरीगंज, तार बिगहा, डिंडिर, अहियापुर, पंचायत के ग्राम सलेमपुर, कमालपुर में बिजली के पोल एवं तार की स्थिति काफी जर्जर स्थिति है, वहां पर बदलने की आवश्यकता है महोदय । सोनहथू-पंचायत के ग्राम गगन बिगहा, कैथी, पिरू पंचायत के ग्राम-चिरैयाटाड़, डिहुरी, रसूलपुर, महदीपुर, गवसपुर, धुसरी-पंचायत के ग्राम-महमदपुर, भौली, भानबिगहा,, डुमरा पंचायत के ग्राम रतनपुर, मलहारा-पंचायत के ग्राम नगौली अमझरसरीफ पंचायत के ग्राम मुस्लीमाबाद, पहरपुरा, जैतपुर पंचायत

के ग्राम–नान्हू बिगहा, जैतपुर, बंशी बिगहा, रफीगंज प्रखंड के पौथू पंचायत के ग्राम–भारतीपुर, पाठकबिगहा पौथू, सिमा लट्टा–पंचायत के तेमुडा, यदुबिगहा, अचुकी सिहुली पंचायत के ग्राम–चंदौल, पटोई खुर्द, पटोई इटार पंचायत के ग्राम–परसिया, भरकौल, शाहपुर, सबदल, परसडीह गांवों में बिजली की आवश्यकता है, क्योंकि वहां पर स्थिति काफी जर्जर है । ट्रांसफर्मर की क्षमता वहां पर बढ़ाने की जरूरत है और वहां पहले से जो ट्रांसफर्मर, तार, पोल लगे हुए हैं, वह कम पावर के हैं, उसको बढ़ाने की आवश्यकता है

महोदय, गोह विधान सभा क्षेत्र में मात्र दो छोटा–छोटा पावरग्रीड है और गर्मी के दिनों में बिजली कटौती बड़ी समस्या है । बिजली खपत का मात्र 25 प्रतिशत ही बिजली बाधित रहती है । गोह विधान सभा को दिया जाता है जिससे कभी–कभी रात भर बिजली गोह विधान सभा क्षेत्र के क्षमता के बराबर विद्युत आपूर्ति किया जाय । गर्मियों में भार बढ़ जाने से बार–बार बिजली ट्रीप कर जाता है। आपके माध्यम से सरकार से मांग करूंगा कि देवरहा में प्रस्तावित है विद्युत उपकेंद्र को जल्द से जल्द बनवाने की आवश्यकता है क्योंकि यहां पर काफी दिनों से काम लगा हुआ है, जमीन का कुछ मामला था, उसमें अभी तक विभाग के थोड़ा सा उसमें काम में लापरवाही के चलते काम नहीं लग पा रहा है, उसमें काफी दिनों से काम बंद है । महोदय, हसपुरा प्रखंड के ग्राम जखौरा में एवं रफीगंज प्रखंड के ग्राम– चंदौल में नये विद्युत उपकेंद्र लगवाने के लिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मांग करता हूँ । गोह में बिजली की इतनी दिक्कत है, जब बिजली के बार–बार ट्रीप हो जाता है । साथ ही रात्रि में किसी भी गांवों में बिजली खराब होता है तो लोगों को सुबह तक बिजली आने का इंतजार करना पड़ता है, इसलिए वहां मैन पावर को बढ़ाने की आवश्यकता है, वहां पर मानव बल बढ़ाया जाय । इसलिए मैं आपके माध्यम से मांग करूंगा कि उस ग्रीड पर थोड़ा ध्यान दिया जाय और वहां पर मैन पावर को बढ़ाया जाय और तार, पोल जो वहां पर काफी जर्जर है, उसको बदलवाया जाय ।

साथ ही बी0पी0एल0 कार्डधारी, भूमिहीन गरीबी रेखा में अपना जीवन बसर करने वालों को बिल चार्ज तय चक्रवृद्धि ब्याज माफ होना चाहिए जिससे उन गरीब परिवारों को बिजली बिल भुगतान करने में राहत हो सके ।

आपका ध्यान गोह प्रखंड के बंदेया स्थित विद्युत उपकेंद्र की तरफ आकृष्ट कराना चाहता हूं कि इस विद्युत उपकेंद्र से मात्र एक गांव को ही विद्युत आपूर्ति किया जाता है । इस गांव के कुछ दबंगों द्वारा किसी अन्य गांव में विद्युत

आपूर्ति नहीं करने दिया जाता है जबकि लगभग 8 पंचायत के लोग इस उपकेंद्र से लाभान्वित होने से वंचित हैं ।

महोदय, हम आपके माध्यम से सरकार से मांग करेंगे कि देवकुर के इलाके में और अरवल जिला के तेलपा में बड़ी संख्या में जमीन जो सरकारी उपलब्ध है, उसमें सोलर एनर्जी प्लांट बैठाया जाय । जैसे गया जिला के शेरघाटी के इलाके में सरकार द्वारा सोलर प्लांट बैठाया गया है, उससे बहुत किसानों को फायदा है हुजूर, इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करूंगा कि वहां पर सोलर प्लांट बैठाया जाय और लोगों को फायदा पहुँचाया जाय । इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ । धन्यवाद ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री सुनील मणि तिवारी । आपका 8 मिनट समय है ।

श्री सुनिल मणि तिवारी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आभार व्यक्त करता हूँ अपने नेता विजय सिन्हा जी का और मैं आभार व्यक्त करता हूँ अपने नेता जनक सिंह का, जिन्होंने मुझे बोलने का मौका दिया । मैं आभार व्यक्त करता हूँ अपने महान जनता गोविन्दगंज का जिन्होंने मुझे आशीर्वाद देकर के यहां पर भेजने का काम किया ।

हमारे कुछ कांग्रेस के नेता बोल रहे थे कि ये किया, वो किया । लेकिन पहले लाईन था, जब गांवों में लाईन आता था तो बच्चा सब कहता था कि बिजली आ गई, बिजली आ गई और जैसे ही बच्चा घर में जाता था, बिजली कट जाती थी। फिर वही बात आ गया, अगर यही बात अभी है तो सरकार से पूछिए । महोदय, पहले लोग गर्मी में लाईट के अभाव में रात भर रोड पर घुमते रहते थे कि बिजली आयेगी, तब घर के अन्दर सोने के लिए जायेंगे, आपलोग भी अनुभव करते होंगे और वे कांग्रेसी लोग भी अनुभव करते होंगे । लेकिन आज मान्यवर मोदी जी का देन है कि 22 से 24 घंटा अगर बिजली मिल रही है तो उसमें आप बिजली ले रहे हैं और आराम कर रहे हैं । एक बात जान लीजिए कि उस समय ढ़िबरी युग था और उसके बाद लालटेन युग आया, आज जो बिजली युग है जिससे आप भी बिजली ले रहे हैं, एकदम ले रहे हैं ।

..... क्रमशः .....

टर्न–20/शंभु/17.03.23

श्री सुनील मणि तिवारी : क्रमशः.....मनमोहन जी का नाम लेते न तो हमलोग रातभर जगे रहते थे, गर्मी में कपड़ा खोलकर रोड पर रहते थे और रातभर छत पर ही सोना होता था या बाहर, लेकिन आज कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं सोता है, छत पर नहीं सोता है बिजली में सोता है यह बिजली का युग है । अब हम अपने अभिभावक मंत्री जी से अपने क्षेत्र की कुछ बात रखेंगे जो वाजिब बात है । हमारे पहाड़पुर प्रखंड में

बलुवा पंचायत है वहां बी0पी0एल0 परिवार को, सौ परिवार को दो-दो बिजली कनेक्शन का बिल जाता है, दो कनेक्शन का बिल जाता है और उस बिल में एक पर 9 हजार होता है और दूसरा बिल पर 52 हजार होता है- उपभोक्ता किसको दे और जाकर पदाधिकारी से कहता है तो पदाधिकारी असभ्य बोलता है । वहां के एस0डी0ओ0 और जे0इ0 का हम आपको प्रूफ देंगे, हमारे पास सारा प्रूफ है हम प्रूफ लेकर आये हैं और आपको प्रूफ देंगे ।

(व्यवधान)

गला फंस गया है चूंकि आपलोग का हड़ताल हुआ था उसमें गला फंस गया । ये सर, हम आपको प्रूफ देंगे ।

(व्यवधान)

अरे सुनिये तो पहले आवाज तो किसी तरह से निकल जायेगा ।

उपाध्यक्ष : बोलने दीजिए माननीय सदस्य को ।

श्री सुनील मणि तिवारी : हम सर आपको प्रूफ देंगे ।

(व्यवधान)

वह भी बिजली से खत्म हो गया, आपको बता दें कि अरेराज के मलाही प्रखंड में एक अरविन्द प्रसाद हैं उनका एक महीना का बिल 5800 जाता है और अंतिम 12वॉ महीना में 1 लाख 20 हजार का बिल जाता है और उनका लाइन काटने के लिए जाते हैं और वह व्यक्ति कुछ कहता है तो उसपर 353 दफा लगाकर के मुकदमा किया जाता है और उसको डराया जाता है । इसका भी हम आपको कागज देंगे । आपके कृषि फीडर का हमारे यहां डेढ़ सौ लोगों को मीटर दे दिया गया और न पोल है, न तार है और नंगा तार से बिजली चालू हो गया जिससे एक 8 वर्षीय बच्चा शुभम कुमार को करेंट लग गया जिससे वह मर गया और आपके विभाग के एस0डी0ओ0, जे0इ0 जाकर उसके लाश को दफना देते हैं और मामले को रफादफा कर देते हैं चूंकि नंगा तार था । यह सरकार की बात है ।

(व्यवधान)

बिल सर नहीं जाता है, पांच साल बिल नहीं गया गरीब के घर पर और पांच साल के बाद एक ही बार 15 हजार गया, 25 हजार गया उसमें काफी ब्याज बढ़ गया । कहा जाता है कि आप कैंप लगाकर इसकी जॉच कीजिए, इसमें सुधार कीजिए। उसका ऑडियो भी है सर, पब्लिक को गाली देते हैं वहां के पदाधिकारी- हम आपको ऑडियो भी दे देंगे, विडियो भी देंगे और सारे कागजात का प्रूफ देंगे । सर, इसको देखा जाय । वहां जो एस0डी0ओ0 हैं उनका ऑडियो भी है, विडियो भी है और ये सारे कागजात हैं सर, देखा जायेगा । सर, एक विशेष आग्रह आपसे

है चूंकि गला फंसा हुआ है ज्यादा नहीं बोलेंगे । हमारे अरेराज सबडिविजन का पहले मुख्यालय मोतिहारी में था जिसे अब चकिया में कर दिया गया है । जो अरेराज से 80 कि0मी0 दूर है । पहले मोतिहारी 30 कि0मी0 दूर था यदि कोई गड़बड़ी होती थी तो हमलोग मोतिहारी जाकर के एक्सक्यूटिव से कहकर के करा लेते थे, लेकिन चकिया 80 कि0मी0 जाने में दिक्कत है । हम आपसे आग्रह करेंगे आप अभिभावक हैं, आप सबके अभिभावक हैं जो सबडिविजन का मुख्यालय पहले मोतिहारी में था उसे मोतिहारी में ही करा दें ताकि वहां के लोगों को सुविधा मिले । हम आपसे एक बात और कहेंगे कि आप ही का नलजल योजना है और हमारे सिसुआ पंचायत में चलियेगा तो आज भी बांस के खंभा पर नलजल योजना का तार गया है और वहां से पानी सप्लाय होता है, जाता है । मैंने वहां के विधायक होने के नाते एक बार नहीं दस बार एस0डी0ओ0 से कहा और हरदम कहते हैं कि अब बदला जायेगा, पोल लग जायेगा, लेकिन आज तक नहीं लगा और एक बार आंधी आई तो वहां पर आग लग गयी इसका दोषी कौन होगा ? वहां आग लगने के बाद भी फिर बांस पर ही तार लग गया । इसका भी ऑडियो आप कहेंगे तो हम सुना देंगे । ये मेरी मांग है, चूंकि गला फंस रहा है । हम आपसे आग्रह करेंगे चूंकि आप अभिभावक हैं इस बात की आप जॉच करा लीजिए । सभी का कागजात है प्रूफ के साथ हम आपको दे रहे हैं इसको आप लीजिए और लाइन का जो 11000 का तार है वह अल्युमिनियम का तार है, थोड़ा सा भी पानी अगर बरस जाता है तो तार शार्ट करने लगता है और रातभर लाइन चला जाता है । यह कहावत भी है कि बरसा बरसे पातभर और बिजली जाये रातभर तो बिजली रातभर न जाये, उसके भी तार को आप बदलने का काम करें । गला फंस रहा है आपको बहुत-बहुत धन्यवाद, सरकार को बहुत-बहुत धन्यवाद । अब तो कम से कम बिजली युग में जी रहे हैं और ये अगर बिजली का उपलब्धि है तो मेरा भी उसमें सहयोग है, हमारी केन्द्र सरकार का सहयोग है और आपसे आग्रह करेंगे कि सारा कागजात मेरे पास है इसकी जॉच कराकर जो दोषी पदाधिकारी होगा उसपर कानूनी कार्रवाई करने की कृपा की जायेगी, चूंकि आप अभिभावक हैं आपसे नहीं कहेंगे तो हम कहेंगे कहां ? हम जनता के प्रतिनिधि हैं हम कहां जायेंगे ? हम उपाध्यक्ष जी के माध्यम से आपसे आग्रह करते हैं और मैं सीधे भी आपसे आग्रह करता हूँ कि इन तमाम बात का हमारे पास प्रूफ है इसको लेकर आप जॉच कराने की कृपा करेंगे, इसको रख लिया जाय । बहुत-बहुत धन्यवाद और हमारे साथी जो सुने हैं उन लोगों को भी बहुत-बहुत धन्यवाद । हम समस्या बोले हैं तो वह आपका भी है और मेरा भी है । हम कोई दूसरी समस्या नहीं बोले हैं, वाहवाही लूटने के लिए आप पक्ष में हैं

हम विपक्ष में हैं तो यह पक्ष विपक्ष का होते रहता है, लेकिन हमने अगर कोई समस्या कही है तो पूरे बिहार का बोला है और अपने अभिभावक के बीच में रखा है । बहुत–बहुत धन्यवाद उपाध्यक्ष जी, बहुत–बहुत धन्यवाद । जय भाजपा ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री अनिल कुमार, आपका तीन मिनट समय है ।

श्री अनिल कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, ऊर्जा विभाग के अनुदान मांग के समर्थन में बोलने का मौका मिला है । महोदय, ऊर्जा विभाग में बिहार ने एक अद्‌भुत काम किया है, एक तरह से कहें तो क्रांति लाने का काम किया है । क्रांति का असर तो गांवों में जब जाते हैं, क्षेत्र का भ्रमण करते हैं तो उस दरम्यान पता चलता है कि गांव में पहले लोग सोचते नहीं थे कि गांव में हमको रहना है– बम्बई, पटना, दिल्ली, लखनऊ में रहनेवाले लोग दिनभर काम करके वापस चले जाते थे अपने शहर में लेकिन आज वे अपने घर गांव में जाकर के गांव में रहने का काम करते हैं, घर बनवा रहे हैं और वहीं ए0सी0, फ्रीज सब चालू कराकर गांव के बीच उनको रहने का मौका मिल रहा है । यह एक क्रांति आयी है और इस क्रांति में अब गांव में लोग कोई यह नहीं कहता है कि बिजली चाहिए, अब लोग भले कहीं ट्रांसफार्मर जल जाता है तो बोलता है कि ट्रांसफार्मर दे दीजिए, विधायक से बस इतना ही कहता है । हमलोग ट्रांसफार्मर के लिए फोन करते हैं तो 6 घंटा, 12 घंटा में बिजली मिल जाता है । कहीं ऐसा नहीं होता है कि 5–5 दिन तक ट्रांसफार्मर जला हुआ है और नहीं आता है तो एक क्रांति आयी है । महोदय, ऊर्जा विभाग ने बिहार में अद्‌भुत काम किया है एक तरह से कहें तो क्रांति लाने का काम किया है पूरे सूबे के अंदर शहरों में 23 घंटे के लगभग वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में 20–22 घंटे तक बिजली की आपूर्ति किया जाना किसी सपने के सच होने जैसा है । जिसके कारण आप देखेंगे कि उपभोक्ताओं की संख्या में भी भारी वृद्धि हुई है, सरकारी आंकड़ों के मुताबिक लगभग 2 करोड़ के आंकड़े को छूनेवाले उपभोक्ताओं की संख्या इन चीजों पर असर देखेंगे तो इलेक्ट्रोनिक बाजारों की हालत हमारे बिहार में बहुत ही सुदृढ़ हुई है । इलेक्ट्रोनिक सामानों की डिमांड बढ़ी है, इलक्ट्रोनिक दूकानदारों की हालत बेहतर हुई है । विद्युत् आपूर्ति अवधि एवं गुणवत्ता में बढ़ोत्तरी के कारण बिजली की अधिकतम मांग में लगातार वृद्धि हो रही है जो नयी उंचाइयों को छूते हुए विगत 5 अगस्त, 2022 को 6737 मेगावाट तक पहुंच गया जो वर्ष 2024–25 तक लगभग 8 हजार मेगावाट होने की संभावना है ।

(क्रमशः)

टर्न–21/पुलकित/17.03.2023

श्री अनिल कुमार (क्रमशः) : महोदय, इतना ही नहीं राज्य सरकार के सात निश्चय पार्ट–2 के अंतर्गत हर खेत तक सिंचाई का पानी योजना को सफल बनाने के लिए ऊर्जा विभाग से कृषि कार्य अलग से कृषि फीडर के माध्यम से आठ घंटे से लेकर सोलह घंटे तक बिजली की आपूर्ति करने का प्रयास किसानों के लिए वरदान साबित हो रहा है । माननीय मुख्यमंत्री जी की दूरगामी योजनाओं का परिणाम देखेंगे तो ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेंट चेंजिंग की समस्याओं के निराकरण हेतु अच्छी ऊर्जा का महत्व समझते हुए उसे जल–जीवन–हरियाली अभियान के तहत तथा राज्य में सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने का काम किया, जिसका परिणाम कजरा–पीरपैंती में ताप विद्युत केन्द्र के स्थान पर बैट्री स्टोरेज के साथ लगभग 450 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना के निर्माण का निर्णय आने वाले दिनों में राज्य और देश के साथ–साथ पूरी दुनिया के लिए भी अत्यंत लाभकारी होगा । महोदय, मुख्यमंत्री जी की दूरगामी सोच का परिणाम है कि हमारा राज्य देश का पहला राज्य बना, जिसने पूरे राज्य में स्मार्ट मीटर लगाने की योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है ।

उपाध्यक्ष : अब समाप्त कीजिये ।

श्री अनिल कुमार : अब तक लगभग 12 लाख प्रीपेड मीटर लगाये जा चुके हैं । खासकर के शहरी क्षेत्रों में बहुत उत्साहवर्धक परिणाम प्राप्त हुए है तदनुपरांत ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्मार्ट मीटर लगाने का काम शुरू करने का निर्णय लिया गया है ।

उपाध्यक्ष : अब समाप्त किया जाए ।

श्री अनिल कुमार : महोदय, स्मार्ट मीटर सुविधा, मोबाइल सुविधा केन्द्र आदि के माध्यम से लोगों को बहुत ही सहजता से बिजली उपलब्ध कराने का काम हुआ है इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ माननीय ऊर्जा मंत्री जी और उनके विभाग के सभी लोग धन्यवाद के पात्र है ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य अब अपना भाषण समाप्त कीजिये ।
माननीय सदस्य श्री अजय कुमार, आपका समय मात्र दो मिनट है ।

श्री अनिल कुमार : महोदय, एक आग्रह होगा लोग गलत बिजली बिल से परेशान हो रहे हैं ।

उपाध्यक्ष : माननीय अनिल बाबू बैठ जाइये ।

श्री अजय कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, मैं ऊर्जा विभाग की मांग के पक्ष में और कटौती प्रस्ताव के विरोध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं । बिहार में बिजली, ऊर्जा के क्षेत्र में एक बड़ा काम हुआ है, इससे कोई इंकार नहीं कर सकता लेकिन अभी कुछ दूर और चलना बाकी है । यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि क्योंकि सात निश्चय

योजना पार्ट–2 में हर खेत को पानी के लिए जो बिजली देने की बात है, बिजली विभाग के पदाधिकारी भी यहां बैठें हुए हैं । जो 2017 में आवेदन पड़े थे उसको अभी कार्यान्वित करने का काम किया गया है लेकिन 2017 के बाद पांच साल बीत गये जब बिजली अच्छी हुई है और किसान को भी और उम्मीद जगी है । आज आवेदन के लिए वे प्रयास कर रहे हैं लेकिन आवेदन नहीं हो पा रहा है । मैं सुझाव देना चाहता हूं कि इसको ब्लॉक के स्तर पर कैम्प लगाकर किसानों का आवेदन लिया जाए ।

दूसरा, मैं एक अपील करना चाहता हूं कि जब बिजली विभाग, आप अच्छी बिजली दे रहे हैं तो पिछले दिनों बी0पी0एल0 परिवार को आपने मुफ्त में बिजली दी थी लेकिन आज उसके पास भी बिजली बिल जा रहे हैं । मैं अपील करना चाहता हूं कि आप गरीबों की सरकार है, हमलोग उनके लिए काम करना चाहते हैं । पंजाब की सरकार अगर बिजली मुफ्त दे सकती है तो कम से कम बिहार के अंदर गरीबों को हम मुफ्त बिजली दें । तीसरी बात, हम यहां कहना चाहते हैं मद्य निषेध के भी मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं, शराबबंदी बहुत जरूरी है और शराब जो बेचते हैं उन्हें जेल के अंदर बंद करना चाहिए और कर भी रहे हैं लेकिन इस नाम पर जो ताड़ी उतारने वाले, रिक्शा चलाने वाले और ठेला चलाने वालों को पकड़कर के जेल के अंदर बंद किया जाता है, हमें इस पर गौर करना चाहिए, उन गरीबों का क्या कसूर है । उनके बारे में हमें ख्याल करना पड़ेगा और जो जेल में बंद हैं उनके ऊपर जो मुकदमें हैं उसे वापस लेने के लिए भी विचार करना चाहिए। दूसरी बात, लॉ मिनिस्टर साहब भी यहां बैठे हुए हैं, मैं आपसे भी यह अनुरोध करना चाहता हूं कि रेल के अंदर आपका एक कोर्ट होता है और मैं एक उदाहरण दे रहा हूं समस्तीपुर डिवीजन से हमारे उपाध्यक्ष महोदय जी भी आते हैं । किसी न किसी केस में जरूर रेल के केस में होंगे, एक कोर्ट सिर्फ समस्तीपुर में है और उसका दायरा नरकटियागंज से समस्तीपुर और समस्तीपुर से पूर्णिया, कटिहार तक है। वहां के लोग सिर्फ बेल कराने के लिए समस्तीपुर आते हैं, सिर्फ तारीख करने के लिए । महोदय, कितने पैसे उनके खर्च हो जाते हैं, हमें इस पर गौर करना चाहिए और हम अपील करना चाहते हैं कि आप कोर्ट को ई–सेन्ट्रलाइज कीजिये और जहां पर भी जिले के अंदर जंक्शन है, वहां एक कोर्ट आप स्थापित कीजिये, इससे गरीबों के पैसों का जो दुरूपयोग हो रहा है, उससे बचत होगी ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य अब समाप्त कीजिये ।

श्री अजय कुमार : महोदय, बस 30 सेकेंड का समय चाहता हूं । सरावगी जी, आ चुके हैं क्योंकि इन्होंने कहा कि – ''माल महाराज का, मिर्जा खेले होली ।'' माल किनका

है? दिल्ली में पैसा हो या पटना में पैसा हो, ये गरीबों के टैक्स का पैसा है और गरीबों के टैक्स के पैसों पर कौन होली खेल रहा है । होली खेल रहा है, अडाणी। होली खेल रहा है, अंबानी और उसको खेलने की इजाजत कौन दे रहा है सरावगी जी, साढ़े ग्यारह लाख करोड़ कर्जा आपने उन अडाणी, अंबानी का माफ किया लेकिन बिहार के गरीबों का एक पैसा माफ नहीं किया । महोदय, हम इनके लिए दस सेकेंड और लेना चाहते हैं ।

''मंदिर, मजिस्द, गुरूद्वारों ने बांट दिया भगवान को,
धरती बांटी, सागर बांटा, मत बांटो इंसान को ।''

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य बैठ जाइये ।

श्री अजय कुमार : महोदय, आपको बहुत-बहुत शुक्रिया ।

श्री संजय सरावगी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं व्यवस्था पर खड़ा हूं । माननीय सदस्य मेरा नाम लेकर बोल रहे हैं, जवाब देने दीजिये ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री सुर्यकान्त पासवान ।

श्री सुर्यकान्त पासवान : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कटौती प्रस्ताव के विरोध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं । महोदय, हमारा बिहार ऊर्जा के क्षेत्र में काफी आगे बढ़ा है, अब हर गांव और टोले तक बिजली पहुंच चुकी है । महागठबंधन की सरकार में अब बिजली गुल नहीं होती है । महागठबंधन की सरकार ने अपनी सात निश्चय योजना के तहत हर घर तक बिजली पहुंचाने का काम किया है और जो पूरा हो चुका है । खासकर के किसानों को बिजली दर में राज्य सरकार ने काफी छूट दी है । महोदय, मैं भी एक किसान हूं और आज भी खेती करता हूं, जब केन्द्र की सरकार ने डीजल, पेट्रोल की दरों में बेतहाशा वृद्धि की तो किसानों के सामने विकराल समस्या खड़ी हो गयी । महोदय, राज्य सरकार को केन्द्र की सरकार ने धन्यवाद भी दिया, उन्होंने मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंधी योजना और मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना से कृषि उपभोक्ताओं को अतिरिक्त अनुदान देते हुए मात्र 65 पैसे प्रति यूनिट की दर से सस्ती बिजली किसानों को उपलब्ध कराई । महोदय, माननीय मंत्री महोदय बैठे हुए हैं, मैं इनसे निवेदन करना चाहता हूं कि आज आपने बिजली के क्षेत्र में बिहार के अंदर क्रांति लाई है लेकिन आज जो 11000 का तार घरों के ऊपर से गया है । महोदय, वास भूमि के ऊपर से गया है, सरकार उसको अपने खर्च से हटाने की व्यवस्था करें । विद्युत आपूर्ति कम्पनियों ने फिक्स्ड चार्ज को 200 को ढाई गुणा बढ़ाने और बिजली दर को 40 प्रतिशत बढ़ाने का प्रस्ताव विद्युत विनियामक आयोग को भेजा है ।

उपाध्यक्ष : अब समाप्त कीजिये ।

श्री सुर्यकान्त पासवान : बिहार एक उद्योग विहीन पिछड़ा राज्य है । जहां की 52 प्रतिशत जनता गरीबी रेखा से नीचे रहती है । ऐसी स्थिति में बिहार की वर्तमान बिजली दर कई विकसित राज्यों से ज्यादा है फिर भी बिजली दर में बढ़ोत्तरी आश्चर्यजनक है।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य अब समाप्त कीजिये ।

श्री सुर्यकान्त पासवान : महोदय, दस सेकेंड और लेना चाहते हैं । उपाध्यक्ष महोदय, बखरी अनुमंडल की स्थापना 1994 में ही की गयी थी, मगर स्थापना के 28 वर्षों के बाद भी आज तक बखरी अनुमंडल का अनुमंडलीय स्तरीय व्यवहार न्यायालय का भवन निर्मित नहीं हो सका ।

उपाध्यक्ष : ठीक है, अब समाप्त कीजिये ।

श्री सुर्यकान्त पासवान : महोदय, हमारे विधि मंत्री बैठे हुए हैं, मैं इनसे निवेदन करता हूं कि बखरी अनुमंडल में व्यवहार न्यायालय भवन निर्माण कराया जाए । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य श्रीमती कविता देवी, आपका समय सात मिनट है ।

श्रीमती कविता देवी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं ऊर्जा विभाग पर लाये गये कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिए खड़ी हुई हूँ । मैं धन्यवाद देना चाहूंगी अपने कोढ़ा विधान सभा की जनता को, जिन्होंने मुझे इस सदन में भेजने का काम किया है । मैं धन्यवाद देना चाहूंगी अपने विपक्ष के नेता को और मैं धन्यवाद देना चाहूंगी अपने सचेतक महोदय को, जिन्होंने मुझे बोलने का बहुमूल्य समय दिया है । महोदय, राज्य के हर प्रखंड में ऊर्जा प्रक्षेत्र की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से आधुनिकीकरण का कार्य किया गया है । महोदय, स्मार्ट मीटर के खेल में उपभोक्ता परेशान हो रहे हैं । किसी उपभोक्ता का बिजली बिल अधिक आता है तो किसी का बिना मीटर लगाये ही बिजली बिल आ रहा है । नये कनेक्शन वाले उपभोक्ता के बीच विचार से लेकर बिजली बहाल होने तक गंभीर समस्या बनी रहती है । महोदय, मैं यह कहना चाहती हूं कि बिजली खपत से पहले स्मार्ट प्रीपेड के माध्यम से उपभोक्ताओं से गलत पैसा लिया जा रहा है । बिजली कम्पनी के लिए स्मार्ट मीटर कमाई का जरिया बन गया है । मीटर में पैसा होने के बावजूद बिजली काट दी जाती है । बिजली खपत में कोई संतुलन नहीं है ।

(क्रमशः)

टर्न-22/अभिनीत/17.03.2023

श्रीमती कविता देवी (क्रमशः) : महोदय, एक दिन में पांच यूनिट बिजली खपत करने वाला मीटर अगले दिन 20 यूनिट खपत करता है । एक दिन में 20 रुपये की खपत की

जानकारी देने वाला मीटर अगले दिन 30 रुपये की खपत की सूचना देता है । महोदय, ऊर्जा मंत्रालय के अधीन आर0ई0सी0 लिमिटेड की एक रिपोर्ट से यह खुलासा हुआ है कि बिहार में 58 प्रतिशत लोगों को बिना मीटर रीडिंग के बिल दिये जा रहे हैं । मीटर रीडिंग के आधार पर बिजली बिल देने का राष्ट्रीय औसत 79.21 फीसदी है । महोदय, आपराधिक इकाई, बिहार ने बिजली कंपनी के सेंटर से साईबर ब्रांच तक उपभोक्ताओं का डाटा पहुंचाया है । पुलिस यह मान रही है कि बिजली बिल के नाम पर साईबर ठगी के सबसे अधिक मामले पटना में दर्ज किये गये हैं । पुलिस जांच टीम की माने तो पांच लाख से अधिक बिजली उपभोक्ताओं का डाटा साईबर अपराधियों के हाथ लगा है । यही कारण है कि पटना में बिजली बिल के नाम पर ठगी का मामला अधिक है । महोदय, राज्य सरकार द्वारा किसानों के लिए पृथक कृषि फीडर के जरिए दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत किसानों के खेतों तक बिजली दिया जा रहा है पर सत्य बात यह है कि किसान फीडर में कहीं पोल है तो तार नहीं और कहीं तार है तो पोल नहीं । किसी भी किसान के खेत को ससमय बिजली नहीं मिल पा रही है । महोदय, सरकार के आदेश के अनुरूप सभी जर्जर तार, पुराने तार बदलने का प्रावधान है । साथ ही, आबादी वाले क्षेत्रों में कवर तार लगाने का प्रावधान है परंतु आज भी पूरा प्रदेश इससे वंचित है, मात्र 50 प्रतिशत ही कार्य हो पाये हैं । हमारे सीमांचल के चार जिलों कटिहार, पूर्णिया, अररिया और किशनगंज में सरकारी कंपनी द्वारा कृषि विद्युतीकरण का कार्य किया जा रहा है । लगभग चार माह से कंपनी एवं अधिकारी की उदासीनता के चलते कार्य पूर्ण रूप से बंद है । संपूर्ण सीमांचल क्षेत्र में मात्र 20 प्रतिशत ही कार्य हो पाया है । वर्तमान समय में भी संपूर्ण बिहार में हजारों गांव, टोलों में बांस के सहारे ही बिजली चल रही है । उदाहरण स्वरूप मेरे विधान सभा क्षेत्र में ही कोढ़ा प्रखंड के उत्तरी सिमरिया पंचायत के वार्ड सं0-9 में कई वर्षों से बांस के सहारे बिजली चल रही है । नगर पंचायत कोढ़ा के वार्ड सं0-8 तक आदिवासी बिंद टोला से आदिवासी पोखर टोला तक बांस के सहारे ही, कई बार मेरे द्वारा भी बड़े अधिकारी को संज्ञान में दिया गया है । ऐसे कई उदाहरण प्रदेश में हैं । उपभोक्ता मीटर के लिए परेशान रहते हैं और विभाग द्वारा उपलब्ध नहीं कराया जाता है । व्यापक बिजली की भी गड़बड़ी आती रहती है और कोई भी अधिकारी इसे सुधारने के लिए तत्पर नहीं है । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री मोहम्मद अंजार नईमी ।

श्री मोहम्मद अंजार नईमी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे मौका दिया । मैं अपने क्षेत्र की जनता का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे

यहां भेजकर अपनी बात रखने का मौका दिया । मैं अपने नेता तेजस्वी जी का आभार व्यक्त करता हूं और अपने लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का आभार व्यक्त करता हूं कि इन्होंने पूरे बिहार को आगे बढ़ाने का काम किया है, खासकर ऊर्जा के क्षेत्र में विभिन्न योजनाओं के माध्यम से विद्युत का विस्तार एवं आधुनिकीकरण का कार्य किया है । जिसके फलस्वरूप राज्य के सारे क्षेत्रों में 23 से 24 घंटे तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 20 से 21 घंटे विद्युत आपूर्ति की जा रही है । महोदय, राज्य में उपभोक्ताओं की संख्या वर्तमान में लगभग 186 लाख हो गयी है। विद्युत आपूर्ति की अवधि एवं गुणवत्ता में सुधार के कारण विद्युत की मांग बढ़ी है जो नई उंचाई को छूते हुए विगत 5 अगस्त, 2022 को 6 हजार 738 मेगावाट तक पहुंच गयी है, जिसकी वर्ष 2024-25 तक लगभग 8 हजार मेगावाट हो जाने की संभावना है । राज्य सरकार के सात निश्चय-2 में शामिल हर खेत तक सिंचाई के लिए पानी को सफल बनाने की दिशा में ऊर्जा विभाग द्वारा कृषि कार्य हेतु विद्युत संरचना के साथ-साथ डेडिकेटेड फीडर का निर्माण किया जा रहा है तथा सिंचाई हेतु कृषि पंप सेटों को विद्युत संबंध दिया जा रहा है । महोदय, विगत वर्ष 2022 में राज्य में सुखाड़ की स्थिति को देखते हुए कृषि कार्य हेतु लगाये गये दोषपूर्ण ट्रांसफॉर्मर को तत्परतापूर्वक बदला गया तथा कृषि फीडरों में विद्युत आपूर्ति 8 घंटे से बढ़ाकर 16 घंटे की गयी । महोदय, राज्य में बरौनी तथा कांटी ताप विद्युत केंद्रों में सस्ता एवं दक्षतापूर्ण उत्पादन हेतु इनका पूर्ण स्वामित्व एन0टी0पी0सी0 को सौंप दिया गया है जो सफलतापूर्वक काम कर रही है । महोदय, राज्य सरकार के प्रयासों से सम्प्रति उचित समय में बिहार में विद्युत की उपयोगिता लगभग 9 हजार 200 मेगावाट हो गयी है जिसमें लगभग 2 हजार 484 मेगावाट बिजली नवीन एवं नवीकरणीय स्रोतों से प्राप्त होती हैं । ग्लोबल वार्मिंग एवं क्लायन्मेंट चेंज की समस्याओं के निराकरण की दिशा में अक्षय ऊर्जा का महत्व दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है । महोदय, जल-जीवन-हरियाली अभियान के तहत राज्य में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा कजरा एवं पिरपैंती भागलपुर में ताप विद्युत केंद्र के स्थान पर बैट्री स्टोरेज के साथ लगभग 450 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजनाओं के निर्माण का निर्णय लिया गया है जिस पर अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है । डेडिकेटेड फीडर का निर्माण किया जा रहा है तथा सिंचाई हेतु कृषि पंप सेटों को विद्युत संबंध दिया जा रहा है । पृथक कृषि फीडर, राज्य में कृषि उपभोक्ताओं को समुचित एवं गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति निश्चित करने के लिए 7 हजार 488 करोड़ की लागत से दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अंतर्गत 33/11 के0वी0 के 291 विद्युत उपकेंद्र तथा कृषि कार्य हेतु टी-1354 पृथक फीडरों

का निर्माण किया गया है जो आने वाले समय में किसानों के लिए वरदान साबित होगा । महोदय, राज्य सरकार द्वारा विद्युत उपभोक्ता सहायता योजनांतर्गत विभिन्न श्रेणी के विद्युत उपभोक्ताओं को विद्युत खपत में प्रति यूनिट अनुदान दिया जा रहा है वहीं कृषि उपभोक्ताओं को विशेष छूट देते हुए मात्र 70 पैसे प्रति यूनिट की दर से सस्ती बिजली उपलब्ध करायी जा रही है । महोदय, इस योजना से हमारे अन्नदाता लाभान्वित हो रहे हैं तथा केंद्र सरकार की महंगी डीजल से मुक्ति मिली है । महोदय, वर्तमान में राज्य में उपभोक्ताओं की संख्या 186 लाख से भी अधिक है । इतनी बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं का मासिक मीटर पठन एवं राजस्व की वसूली वितरण कंपनियों के लिए हमेशा चुनौतीपूर्ण रहा है । इस समस्या के समाधान हेतु सरकार प्रीपेड मीटर लगवाने पर काम करना शुरू कर दी है, इससे उपभोक्ताओं को बिल समस्या से मुक्ति मिल सकेगी । महोदय, उपभोक्ता सेवाओं के अधिक पारदर्शी एवं ससमय निष्पादन हेतु 01 जनवरी, 2020 से सुविधा मोबाईल एप लागू किया गया है । अब इस एप के माध्यम से उपभोक्ता बिजली संबंधी समस्या का निदान एवं लाभ उठा रहे हैं । महोदय, ऑनलाईन उपभोक्ता सेवाओं तथा शिकायत हेतु टाल फ्री नं0-1912 की सुविधा के अतिरिक्त ऑनलाईन शिकायत दर्ज कराने की सुविधा बी0एस0पी0एच0सी0एल0 के वेबसाईड पर प्रदान की गयी है । महोदय, इसके साथ ही जल-जीवन-हरियाली अभियान, नीचे मछली ऊपर बिजली, बिहार राज्य जल विद्युत निगम जैसी योजनाएं काम कर रही हैं । महोदय, बिहार राज्य में वर्तमान में कुल 13 जल विद्युत परियोजनाएं उत्पादनरत हैं जिनकी क्षमता 54 मेगावाट है ।

महोदय, हमारे क्षेत्र बहादूरगंज विधान सभा में टेरागाछ है जहां पलासी पावर ग्रिड से वहां हमको जोड़ना था लेकिन अबतक नहीं हो पाया है । उपाध्यक्ष महोदय, हम आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि अररिया से जो लाईन हमारे टेरागाछ को मिल रही है उसकी दूरी काफी लंबी होने के कारण अक्सर ट्रीप हो जाता है जिससे कई दिनों तक बिजली बाधित रहती है । महोदय, हम चाहेंगे कि टेरागाछ को जल्द-से-जल्द पलासी पावर ग्रिड को पूर्ण करते हुए उसको पलासी से जोड़ा जाय । महोदय, हम एग्रीकल्चर के संबंध में कहना चाहेंगे कि हमारे क्षेत्र को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है । महोदय, एग्रीकल्चर के लिए जितने भी पोल, ट्रांसफॉर्मर लगाने थे अभी तक नहीं लग पाये हैं । महोदय, हम चाहेंगे कि इस परियोजना को जल्द पूर्ण करते हुए हमारे किसान भाइयों को इसका लाभ दिया जाय। महोदय, हमारे क्षेत्र में कुछ ऐसे गरीब लोग हैं जिनके घर के ऊपर से बिजली की तारें, हाईटेंशन वायर गुजरती है और उनलोगों के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं हैं

कि वे किसी दूसरी जगह पर अपना घर बनायें, इसलिए हम निवेदन करना चाहेंगे कि ऐसे हाईटेंशन वायर को सरकार अपने खर्च पर दूसरी तरफ से लेकर जाये ताकि वो गरीब आदमी अपना घर बना सके ।

..क्रमशः..

टर्न-23/हेमन्त/17.03.2023

मोहम्मद अनजार नईमी(क्रमशः) : और कुछ बिजली बिल की समस्याएं भी आ रही हैं हमारे क्षेत्र में । हम चाहेंगे कि उसको देखा जाय । जो गरीब आदमी है, उसका अचानक 40-50 हजार रुपये बिल आ जाता है और उसकी बिजली काट दी जाती है । इसको थोड़ा तत्परता से देखा जाय । महोदय, हमारे क्षेत्र में चार और पावर ग्रिड की आवश्यकता है । बहादुरगंज प्रखण्ड में दो और टेहराघाट में दो । मैं समझता हूं कि ये चारों पावर ग्रिड हो जाने के बाद मेरे क्षेत्र में बिजली पूरे तरीके से परिपूर्ण हो जायेगी । इसी के साथ हम अपनी बात समाप्त करते हैं ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री अचमित ऋषिदेव ।

श्री अचमित ऋषिदेव : महोदय, क्या कहूं, किसको कहूं,

''जान लीजिए सदन मेरा इशारा,
आ गयी है गर्मी, बिजली ही करेगी सहारा ।''

महोदय, आज समय तो हमको मिला है, उस दिन तो हमको पढ़ने नहीं दिया गया ।

उपाध्यक्ष : अपने क्षेत्र के बारे में बोलिये ।

श्री अचमित ऋषिदेव : आज हमको समय तो मिला है । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं । लोकतंत्र के इस सम्मानित सदन में बोलने का मौका देने के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और अपने दल के नेताओं को धन्यवाद देना चाहता हूं और आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने मुझे ऊर्जा विभाग के 11,536.84 करोड़ की अनुदान मांग पर सरकार के पक्ष में बोलने का अवसर दिया है । मैं रानीगंज की महान जनता के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने मुझे इस सदन में भेजने का काम किया है ।

महोदय, राज्य में विद्युत उपभोक्ताओं की संख्या बढ़कर वर्तमान में लगभग 1 करोड़ 86 लाख हो गयी है । सरकार हर घर बिजली के बाद हर खेत में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कृषि फीडर लगा रही है । इसके लिए अतिरिक्त पावर सब स्टेशन का निर्माण कर खेत में बिजली पहुंचा रही है । राज्य सरकार बिजली उत्पादन बढ़ाने के लिए नये-नये तरीकों का भी उपयोग कर रही है । महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सबसे पहले ऊर्जा विभाग की जिम्मेदारी सबसे अनुभवी नेता श्री बिजेन्द्र बाबू के सबल कंधों पर डाली और फिर जिम्मेदार,

ईमानदार पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति ऊर्जा विभाग में की । हमें खुशी है कि आज सब मिलकर हर घर बिजली पहुंचाने का काम कर रहे हैं । महोदय, राज्य सरकार के प्रयास से बिहार में विद्युत की उपलब्धता लगभग 9200 मेगावाट हो गयी है जिसमें लगभग 2484 मेगावाट बिजली नवीन एवं नवीकरण स्तरों से प्राप्त होती है । जब बाढ़ एवं बक्सर थर्मल पावर की दो-दो इकाई चालू हो जायेंगी, तो लगभग 2640 मेगावाट अतिरिक्त बिजली उत्पादित होगी । महोदय, राज्य में विद्युत आपूर्ति की अवधि एवं गुणवत्ता की बढ़ोतरी के कारण विद्युत की अधिकतम मांग में लगातार वृद्धि हो रही है, जो नयी ऊंचाई को छूते हुए विगत 5 अगस्त, 2022 को 6738 मेगावाट तक पहुंच गयी है । महोदय, वर्तमान में राज्य में कार्यरत ग्रिड उपकेंद्र की संख्या 161 है, 12 अतिरिक्त ग्रिड उपकेंद्र का निर्माण कार्य पूरा होने वाला है । संचरण कंपनी द्वारा पहली बार पटना जिले में नयी तकनीक के जीआईएस ग्रिड उपकेंद्र का निर्माण किया जा रहा है । महोदय, राज्य में संचरण प्रणाली की विद्युत निकासी क्षमता 73,544 मेगावाट हो गयी है । वर्ष 2020-21 की तुलना में संचरण की कुल लम्बाई 17,120 किलोमीटर से बढ़कर वर्तमान में 18,740 किलोमीटर हो गयी है । महोदय, राज्य में कृषि उपभोक्ताओं को समुचित एवं गुणवत्तापूर्ण विद्युत की आपूर्ति सुनिश्चित करते हुए 7788.78 करोड़ की लागत से दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अन्तर्गत 33/11 केवीए के 291 विद्युत उपकेंद्र तथा कृषि कार्य हेतु 1354 फीडरों का निर्माण किया गया है । महोदय, राज्य सरकार द्वारा हरित ऊर्जा, मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना, मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना, उपभोक्ताओं के लिए स्मार्ट प्रीपेड मीटर सुविधा, जल जीवन हरियाली अभियान, रूफ टॉप सोलर पावर प्लांट के अधिष्ठापन के कार्य एवं नीचे मछली ऊपर बिजली जैसी जनोपयोगी योजना विभाग द्वारा चलायी जा रही हैं । महोदय, जब हम अपने गांव जाते हैं, एक रोज हम घर जा रहे थे, हमको यहां से जाने में पांच घंटे लगे । नेपाल से सटी हुई सीमा में मेरा गांव है, अररिया जिला, रानीगंज । चांदनी रात में जो तारा होता है, बिजली के चलते लो हो जाता है, घर-घर बिजली है । अगर कोई एक कोस दूर घर बना लिया है, तो वहां भी बिजली हमने पायी है और जब रास्ते से गुजरते हैं, तो देखते हैं कि पशु-पक्षी भी अब बिजली के नीचे बैठते हैं । यह सरकार की बहुत-बड़ी उपलब्धि है । महोदय, राज्य सरकार के दृष्टिकोण न्याय के साथ विकास हो रहा है । राज्य सरकार ने सात निश्चय कार्यक्रम के तहत कई क्षेत्रों में अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल की है । हर घर बिजली, हर घर नल का जल, पक्की नली-गली, शौचालय का निर्माण, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नये संस्थानों की स्थापना, युवा सशक्तिकरण हेतु उच्च शिक्षा एवं

उद्यमशीलता के साथ वित्तीय सहायता प्रदान करना एवं महिला सशक्तिकरण हेतु सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35 प्रतिशत आरक्षण करना आदि राज्य सरकार की कुछ प्रमुख उपलब्धियों में से है ।

महोदय, अब मैं सरकार का ध्यान अपने विधान सभा क्षेत्र रानीगंज की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं । रानीगंज में एक ग्रिड उपकेंद्र की जरूरत है । इस संबंध में मैं विधान सभा में कई बार सरकार का ध्यान आकृष्ट करता रहा हूं । रानीगंज की आबादी काफी घनी है, बाजार में बिजली का पुराना तार लगा हुआ है जिसमें हमेशा शॉर्ट सर्किट लगता रहता है । इनको बदलकर नया तार लगाने की मांग मैं सरकार से करता हूं ।

उपाध्यक्ष : अब समाप्त कीजिए ।

श्री अचमित ऋषिदेव : महोदय, एक मिनट । महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक परिहारी पंचायत है, जो पूर्णिया जिला की सीमा पर है । वहां एक पावर सब स्टेशन की, हम माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करेंगे और मांग करते हैं । बहुत-बहुत धन्यवाद।

उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री, मद्य निषेध विभाग, अपना पक्ष रखें ।

श्री सुनील कुमार, मंत्री : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपका हम शुक्रिया अदा करते हैं, जो आपने हमें विभाग की बातों को यहां रखने का मौका दिया । हम माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करते हैं, जिन्होंने इन विभागों की जिम्मेदारी हमें सौंपी है । हम माननीय उप मुख्यमंत्री एवं माननीय सचेतक महोदय का भी आभार प्रकट करते हैं ।

महोदय, निबंधन विभाग एक बहुत ही पुराना विभाग है । 1796 में कार्यालयों की स्थापना हुई, पटना में, मुजफ्फरपुर में और पूर्णिया में और हमारे विभाग में 1798 के भी दस्तावेज धरोहर के रूप में हैं ।

(क्रमशः)

टर्न-24/धिरेन्द्र/17.03.2023

...क्रमशः...

श्री सुनील कुमार, मंत्री : महोदय, और हमें सदन को यह बताते हुए खुशी हो रही है कि वर्ष 1938 के राष्ट्रकवि श्री दिनकर जी की हस्ताक्षरित जो दस्तावेज है वे उपलब्ध हैं चूंकि उन्होंने अपनी सेवाएँ इस विभाग को दी थी और धरोहर में जो भी दस्तावेज हमारे पास है, हमारी कोशिश है कि उसको डिजीटाईज करा कर, जिसको कि हमलोग उचित स्थान पर उसका प्रदर्शन करेंगे ।

महोदय, इस विभाग का मुख्य कार्य है राजस्व संग्रह करना और हमें यह बताते हुए संतोष हो रहा है कि पिछले वित्तीय वर्ष में हमलोगों ने अपने लक्ष्य का 104 प्रतिशत प्राप्त किया राजस्व का और इस साल वर्ष 2022-23 में हमारा लक्ष्य था 5,500 करोड़ रुपये, जिसके विरुद्ध में अभी तक यानी 16 मार्च तक हमलोगों ने 6,059.53 करोड़ रुपये यानी 110 प्रतिशत से भी ऊपर हमलोगों ने लक्ष्य प्राप्त किया है और उम्मीद है कि इस वित्तीय वर्ष के खत्म होते-होते हमलोग 6,200 करोड़ रुपये से ऊपर राजस्व की प्राप्ति कर लेंगे । माननीय सदस्यों के अनुरोध पर हमलोगों ने 11 जगहों पर कार्यालय खोला है और वह अब काम भी करने लगा है। उसके अतिरिक्त हमलोगों ने 44 पदों का सृजन किया और बियाडा की जमीन पर जो निजी निवेशक आते हैं, उनको हमने 100 प्रतिशत रजिस्ट्रेशन फी और स्टैम्प ड्यूटी में एग्जम्पशन दिया है और आम जनता की सुविधा के लिए हमलोगों ने ऑनलाईन अप्वाईंटमेंट, रजिस्ट्रेशन, पेमेंट की व्यवस्था की है और उसमें कुछ छूट भी दी है और साथ-ही-साथ ऑनलाईन हमलोगों ने मॉडल डीड भी रखा है ताकि लोगों को सहूलियत हो । हम सदन को आश्वस्त करना चाहते हैं कि आने वाले समय में विभाग निश्चित रूप से अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करेगा ।

महोदय, जहाँ तक शराबबंदी का प्रश्न है, वर्ष 2016 में 5 अप्रील को पूर्ण शराबबंदी दोनों सदनों ने पास किया और समय-समय पर आवश्यकतानुसार हमलोगों ने संशोधन भी किये हैं । यह माननीय मुख्यमंत्री जी का पॉलिटिकल विल, एक राजनीतिक दृढ़निश्चितता का परिणाम है कि आज भी बदस्तूर हमलोग पूर्ण शराबबंदी को जारी रखे हुए हैं और पूरी मुस्तैदी से पुलिस विभाग और एक्साइज विभाग काम कर रहा है । हम सभी जानते हैं कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने शराब को एक अभिशाप कहा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन की जो भी रिपोर्ट है उससे भी परिलक्षित होता है कि 200 से अधिक बीमारियाँ होती हैं, आत्महत्याएँ लोग करते हैं, रोड एक्सीडेंट्स होते हैं । इसलिए हमलोगों ने अभियान चलाकर सारी कार्रवाई पूरी की है और माननीय मुख्यमंत्री जी समय-समय पर, उन्होंने विभाग की समीक्षा भी की है और जो समाधान यात्रा था उसमें मैं संयोग से साथ था और समाज सुधार अभियान के दौरान भी जो बातें विशेषकर महिलाओं ने कही, उससे स्पष्ट है कि उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार आया है । जो तीसरा सर्वेक्षण हमलोगों ने कराया, हाल में जो फरवरी, 2023 में जो हमें प्राप्त हुआ, उससे पता चलता है कि 1 करोड़ 84 लाख लोगों ने शराब पीना छोड़ दिया, 99 प्रतिशत महिलाओं ने पूर्ण शराबबंदी का समर्थन किया है, 92 प्रतिशत पुरुषों ने

समर्थन किया है और निश्चित रूप से जहाँ तक महिलाओं का प्रश्न है...

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

उनकी आय में इजाफा हुआ है, अब ज्यादा पैसा वे शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, खाने-पीने की वस्तुओं पर कर रही हैं और साथ-ही-साथ जो घरेलू हिंसा है उसमें भी कमी आयी है, कुछ कमी सड़क दुर्घटनाएँ शराब पीकर चलाने में होती थी उसमें भी कमी आयी है और विधि व्यवस्था पर तो निश्चित रूप से इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ा है । आप होली के त्यौहार को ही देख लें जहाँ हाल में, हर जगह पहले शराब पीकर हंगामा होता था, शादियों में हंगामा होता था, इन सब चीजों में तो निश्चित रूप से कमी आयी है और आपको यह बताते हुए हमें...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : सरकार का उत्तर है, नहीं टोका जाय । अभी स्थान ग्रहण किया जाय ।

श्री सुनील कुमार, मंत्री : विभिन्न राज्यों से यहाँ अध्ययन दल भी आये । पूर्व में कर्नाटक से, राजस्थान से, छत्तीसगढ़ से अध्ययन दल आये हुए थे और हाल में छत्तीसगढ़ से पुनः एक अध्ययन दल यहाँ आया, उन्होंने वैशाली जिले में जाकर देखा कि किस तरह से, प्रभावकारी ढंग से शराबबंदी लागू है । उन्होंने हमारे विभाग में सभी पदाधिकारियों से विचार-विमर्श किया, हमसे किया, उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी विचार-विमर्श किया और आपने मीडिया में भी देखा होगा कि किस तरह से उन्होंने शराबबंदी की बड़ाई की है और अपने राज्य में भी उन्होंने कहा है कि वे कोशिश करेंगे कि अपने राज्य में भी शराबबंदी लागू करें क्योंकि वहाँ काफी समस्याएँ हैं । देखिये, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी हमेशा से निर्देश रहा है और विभाग की भी सोच है कि हमारा जो मुख्य उद्देश्य है कि जो आपूर्तिकर्ता हैं या फिर जो निर्माणकर्ता हैं, उन्हें पकड़ा जाय और इसी वजह से, आप देखेंगे कि पिछले 2016 से अब तक के लिए जो दूसरे राज्यों के बड़े-बड़े कारोबारी थे या सप्लायर थे, उसमें से 10 हजार हमलोगों ने गिरफ्तारियाँ की हैं, 10 हजार से ऊपर और उसमें से करीब 100 कारोबारियों को सजा भी हुई है । एक तरफ पुलिस तो अपना काम कर ही रही है लेकिन साथ-ही-साथ हमलोगों ने इस बात पर भी ध्यान दिया है कि प्रचार-प्रसार कैसे किया जाय, जागरूकता कैसे बढ़ायी जाय, इस वजह से हमलोगों ने टी॰वी॰ का सहारा लिया, सोशल मीडिया का, नुक्कड़-नाटक का, जीविका दीदियों का और साथ-ही-साथ हमलोगों ने, आपने देखा होगा कि हाफ मैराथन दौड़ भी हमलोगों ने कराई थी शराबबंदी दिवस के दिन और आने वाले नवम्बर के महीने में हमलोग पुनः जागरूकता अभियान को लेकर फुल मैराथन जरूर करायेंगे । हमलोगों ने...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : नेता प्रतिपक्ष, माननीय सभी सदस्यों को अपना पक्ष रखने का अवसर मिला, अब सरकार का उत्तर हो रहा है, इसको तो आप सुनें ।

(व्यवधान)

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : महोदय, आसन को तो विपक्ष का संरक्षक होना चाहिए । अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री...

अध्यक्ष : आप हमेशा आसन से ही संरक्षण माँगते हैं और हमेशा, अब हम नहीं कहेंगे कि आते हैं, जाते हैं, यही आपका काम है ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी अभी आपने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी पीने वाले को छूट दे दिये कि पीने वाले को नहीं पकड़ना है । चार लाख लोगों पर जो पीने वालों पर केस हुआ है, क्या उसे वापस ले रहे हैं ? दूसरा, जो आपकी जहरीली शराब से मरा, उसके अनाथ और विधवा का क्या दोष है ? उसको असामाजिक तत्व के हाथ में जाने से आप बचायेंगे ?

अध्यक्ष : अब आप स्थान ग्रहण करें । अब माननीय मंत्री जी ।

श्री सुनील कुमार, मंत्री : बिल्कुल इस पर भी हम आयेंगे, मौका दीजिये । महोदय, हमलोगों ने पुलिस तंत्र और एक्साइज तंत्र को भी मजबूत किया है, एंटी-लिकर टास्क फोर्स को मजबूत किया है और 1,033 नये पद भी सृजित किये हैं । हमलोगों ने ग्रुप सेंटर की व्यवस्था की है, कॉल सेंटर की व्यवस्था की है और कॉल सेंटर में अमूमन 300 से ज्यादा कॉल रोज आते हैं और किसी को भी, इस विधान सभा में किसी को भी अगर कोई सूचना देनी हो तो उनका नाम हम निश्चित रूप से गुप्त रखेंगे, उसे दिया जा सकता है और इसके अलावा 85 चेक पोस्ट हैं और पुलिस विभाग अपना काम कर रही है और नये टेक्नोलॉजी का हमने इस्तेमाल किया है, जिसमें सी॰सी॰टी॰वी॰ कैमरा है, इसके अतिरिक्त ड्रोन का भी हमलोगों ने इस्तेमाल किया है, वॉटर बोट का इस्तेमाल किया है और हेल्पलाईन भी हमलोगों के पास है । हम जो दर्ज मामले हैं उसमें त्वरित गति से कार्रवाइयाँ हो रही हैं, 74 कोर्ट हमलोगों ने इजात किये हैं और आपको बताना चाहेंगे कि ऐसी बात नहीं है कि सजाएँ नहीं मिल रही हैं, अगर आप जुरमाने को, जो हमलोगों ने प्रावधान किया था पिछले साल...

...क्रमशः...

टर्न–25/संगीता/17.03.2023

(क्रमशः)

श्री सुनील कुमार, मंत्री : और अन्य सजाओं को ले लें तो 1 लाख 98 हजार से ज्यादा सजाएं मिली हैं लोगों को और रोजगार के क्षेत्र में भी जो लोग पारंपरिक रूप से ताड़ी के व्यवसाय से जुड़े हुए थे, अन्य निर्धन परिवार हों, चाहे वे ग्रामीण क्षेत्र हों या शहरी क्षेत्र हों उन्हें हमलोगों ने सतत् जीविकोपार्जन योजना से जोड़ा है, 1 लाख 40 हजार परिवार हैं । इसके अतिरिक्त नीरा के संबंध में, उससे तो फायदा ही होता है 18 से ज्यादा अनुज्ञप्तियां दी गई हैं और उसके पदार्थ भी आपलोगों ने शायद खाये होंगे और जो बोतल नष्ट किए जा रहे थे पर्यावरण के हिसाब से अच्छा नहीं था, उन बोतलों से अब पटना जिले में आप देख रहे हैं 6 लाख चूड़ियां भी बनाई गई हैं और उसमें जीविका की दीदीयां भी जुड़ी हुई हैं । कहा जाता है कि पर्यटकों की संख्या घटी है लेकिन वर्ष 2016 में करीब 3 लाख पर्यटक बिहार आए थे । वर्ष 2019 में ये बढ़कर साढ़े 3 लाख से ऊपर हो गए, कोविड के समय में तो कुछ कम जरूर हुए, एक चिन्ता का विषय माननीय सदस्य भी उठाते रहे हैं नशीली पदार्थों के संबंध में, उसमें भी हमलोगों ने 5 हजार से ज्यादा केसेज दर्ज किए हैं और 6 हजार से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई हैं गांजा, चरस इत्यादि बरामद हुए हैं जो जहरीली...

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, समय की कमी है ।

श्री सुनील कुमार, मंत्री : दो मिनट महोदय । जहरीली शराब के संबंध में पूछ रहे थे तो जहरीली शराब का शराबबंदी से लेना–देना नहीं है कुछ और अन्य राज्यों में मैं आंकड़े बताता हूं कि वर्ष 2016 से 2021 तक कर्नाटक में 1 हजार 13 मौतें हुई जहरीली शराब से, मध्य प्रदेश में 13 सौ 22 हुई तो वहां पर...

(व्यवधान)

मैं बता रहा हूं कि...

अध्यक्ष : नहीं, नहीं । सरकार का उत्तर...

(व्यवधान)

सरकार का उत्तर हो रहा है...

(व्यवधान)

श्री सुनील कुमार, मंत्री : ये ढोल की राजनीति नहीं होनी चाहिए, ढंग की राजनीति होनी चाहिए...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आपलोगों ने भी अपना पक्ष रखा, अब सरकार का उत्तर होने दीजिए ।

(व्यवधान)

श्री सुनील कुमार, मंत्री : बिल्कुल । हमलोग वहां गए थे और जो उचित कार्रवाई है सभी केसेज में अनुसंधान पूरा करके...

अध्यक्ष : मंत्री जी, आप बोलते रहिए । अपना पक्ष बोलते रहिए ।

(व्यवधान)

श्री सुनील कुमार, मंत्री : माननीय सदस्य ने चर्चा की थी भ्रष्टाचार के विषय में...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : अब आपलोग अपना स्थान ग्रहण करें । नहीं, नहीं...

श्री सुनील कुमार, मंत्री : अच्छे पदाधिकारियों को पुरस्कृत किया गया है और दोनों विभाग को अगर आप मिला लें तो पूरे हिन्दुस्तान में नहीं होगा कि 291 लोगों की बर्खास्तगियां हुई हों...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपलोग स्थान ग्रहण करें । माननीय मंत्री जी अपना पक्ष जारी रखें।

श्री सुनील कुमार, मंत्री : हम इस सदन को आश्वस्त करना चाहते हैं कि पूरी मजबूती के साथ और मनोयोग के साथ एक्साइज विभाग और पुलिस विभाग शराबबंदी के कानून को प्रभावकारी ढंग से जारी करता रहेगा और यह जरूरी है बिहार के सर्वांगीण विकास के लिए न सिर्फ आर्थिक विकास जरूरी है लेकिन सामाजिक विकास भी जरूरी है इसलिए आपलोगों ने हमारी बातों को ध्यान से सुना, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, जय हिन्द ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री विधि विभाग, कृपया अपना पक्ष रखें । संक्षेप में ।

श्री शमीम अहमद, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं । मैं धन्यवाद देता हूं राज्य के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी को और अपने उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी को, जिनके नेतृत्व में यह सरकार चल रही है । आज बिहार सरकार पूरी तरह लोगों को न्याय कैसे मिले, उसमें जितनी भी महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं सब चलायी जा रही हैं । सरकार श्रमिकों, औरतों, बच्चों, औद्योगिक मजदूरों, गरीबों, अल्पसंख्यक, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए सुलभ एवं सस्ता न्याय प्रदान करते हुए उन्हें न्यायिक दृष्टि से सशक्त एवं जागरूक करने की दिशा में प्रयास...

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, संक्षिप्त में ।

श्री शमीम अहमद, मंत्री : जी, संक्षिप्त में । आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार बिहार में कैसे केसों की संख्या कम हो, इसकी तरफ लगातार प्रयास किए जा रहे

हैं । इसमें माननीय उच्च न्यायालय, पटना एवं राज्य के व्यवहार न्यायालय में बिहार सरकार की ओर से वचनबद्ध विधि पदाधिकारी एवं अन्य अधिवक्ता तथा संबद्ध कनीय सहायक अधिवक्ता एवं निजी लिपिक...

अध्यक्ष : अब समाप्त करें ।

श्री शमीम अहमद, मंत्री : माह फरवरी, से बढ़ोतरी किया गया । अध्यक्ष महोदय, थोड़ा सा समय और चाहिए ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी...

श्री शमीम अहमद, मंत्री : वर्ष 2022-23 में...

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी आपका समय खत्म हो गया । आप स्थान ग्रहण करें । अब माननीय मंत्री ऊर्जा विभाग ।

(व्यवधान)

मतलब क्या जाना चाहते हैं ?

(व्यवधान)

सरकार के उत्तर को सुनिए ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष आग्रह कर रहा है...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : नेता प्रतिपक्ष, जब सरकार खड़ी हो गई है तब आप...

(व्यवधान)

आपको यह मालूम है कि जब सरकार को बुला दिया जाय तो उस समय आपको स्वयं ही नहीं आग्रह करना चाहिए नहीं कहना चाहिए कि हम बोलना चाहते हैं । आप अपना स्थान ग्रहण करें ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : इस हद तक जायेगी...

(व्यवधान)

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय...

(व्यवधान)

महोदय, मैं कुछ बातों को...

अध्यक्ष : अब सरकार का उत्तर ।

(व्यवधान)

आप क्या मतलब, देखिए...

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी भी सदन में आए हैं, जिस दिन हमलोग मंत्री इसराईल मंसूरी जी का मामला उठाए थे...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : नहीं, नहीं, सरकार का उत्तर ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : इसका जवाब...

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, आप अपना पक्ष रखें ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, मुझे स्मरण होता है...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आपलोग अपना स्थान ग्रहण करें ।

(व्यवधान)

सरकार का उत्तर । अपना पक्ष रखिए, एकतरफा नहीं है, आपने बोल लिया है । अब हर वक्त मंसूरी, मंसूरी, मंसूरी लगता है कि फोबिया की बीमारी जैसे हो जाती है उस तरह की स्थिति है ।

सरकार का उत्तर

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं कि आज बजट पर बोलने का...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : अब शांति बनाए रखें, सुनें आप ।

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण सदन से बहिर्गमन कर गए)

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : बजट पर बोलने का आपने मौका दिया । कुछ संदर्भों को मैं याद करता हूं महोदय, जब हमलोग संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य थे तो एक वक्त था कि नारा लगाते थे कि शहर में उजाला गांव में अंधियारा दो तरह का भारत नहीं चलेगा । मुझे स्मरण है स्वर्गीय वाजपेयी जी की जब सरकार बनी और हमारे मुख्यमंत्री जी उस समय रेलमंत्री थे तो बिहार का जब बंटवारा हुआ तो हमलोग गए थे मिलने के लिए हम भी थे इसमें कि बिहार को विशेष पैकेज मिलना चाहिए । एक मिश्रा कमिटी का गठन हुआ जो भागलपुर के थे और 3 सेक्टर को उन्होंने आइडेंटीफाई किया कि बिजली तो मिलती भी है लेकिन यहां ट्रांसमिशन लाईन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की बड़ी किल्लत है एक हजार करोड़ रुपया उसके लिए, स्टेट हाईवे ठीक स्थिति में नहीं है एक हजार करोड़ रुपया उसके लिए, नहरों के मामले में यह हुआ कि 50-60 के दशक में ही नहर का निर्माण हुआ गंडक योजना, कोसी योजना और अंग्रेजों के जमाने में सोन नहर प्रणाली वह अब डिलेटेड पोजीशन में चला गया उसके अपग्रेडेशन के लिए भी एक हजार करोड़ रुपया, और उसी समय में 2003 में ही यह घोषणा हुई थी स्वर्गीय वाजपेयी जी की सरकार ने कि गांव के गरीब को बी0पी0एल0 वाले को 10 परसेंट को हर घर में बिजली की योजना चालू होगी । मैं ऐसे नहीं स्मरण से उतार सकता हूं

लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी उस समय मंत्रिमंडल में थे । फिर मुझे याद आता है एक दूसरा संदर्भ, चूंकि यहां चावला साहब बैठे हुए हैं इसलिए मैं इसका जिक्र कर रहा हूं, वर्ष 2006 की बात है आदरणीय मनमोहन सिंह जी ने इनर्जी मिनिस्टर का एक कान्फ्रेंस बुलाया, शिंदे साहब उस समय एनर्जी मिनिस्टर थे, मैं शिंदे साहब के भाषण को उद्धृत करना चाहूंगा क्योंकि इतिहास को भुलाना नहीं चाहिए । कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब हमारे सभी कलीग्स यहां हैं आज खाली लोग बिहार और भारत का फर्क करते हैं उन्होंने यह वर्ड कहा कलीग्स । फेडरल स्ट्रक्चर है भारत का ही हिस्सा है सभी राज्य, यहां संविधान अमेरिकन पैटर्न पर नहीं है प्रेसिडेंसियल नहीं है, फेडरल स्ट्रक्चर है । उन्होंने कहा कि हमारे सारे कलीग्स बैठे हुए हैं । एक वक्त था आज से एक साल पहले जिस किसी को यह विभाग मिलता था तो क्षेत्र के लोग भी कहते थे क्यों यह सड़ा हुआ विभाग लिया और विभाग क्यों नहीं लिये लेकिन आज पुतले दहन होते हैं, रोड जाम किये जाते हैं और अर्थशास्त्री लोग यहां कहते हैं...

(क्रमशः)

टर्न-26/सुरज/17.03.2023

(क्रमशः)

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : कि पैसे का अभाव है कहां से बिजली हर घर हो । लेकिन मुझे यह स्मरण है मैं उस क्रम में बोलने के वक्त में मैंने कहा आदरणीय प्रधानमंत्री जी आपने स्वामीनाथन कमेटी बनाया, एग्रीकल्चरल फुड एंड सिक्योरिटी एक्ट लाने जा रहे हैं । उनके रिपोर्ट का मैं जिक्र करना चाहूंगा, उन्होंने कहा कि फर्स्ट ग्रीन रेवोल्युशन, वेस्टर्न यू0पी0 और हरियाणा, पंजाब में हुआ और ईस्टर्न इंडिया उससे मरहूम रहा । सेकेंड ग्रीन रिवॉल्यूशन ईस्टर्न इंडिया से हो और बिहार को उसमें खासकर उत्तर बिहार को जहां जल की कमी नहीं है, उसको न्यूक्लियस बनाया जाय । मैंने कहा आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी जब आये हैं तो एग्रीकल्चर रोड मैप बनाने का काम उन्होंने प्रारंभ किया है । आपसे मेरा निवेदन होगा कि अभी हमारे किसानों को सिंचाई में ढ़ाई हजार, तीन हजार रुपया सिंचाई की व्यवस्था में खर्च करना पड़ता है डीजल से पटवन करने में । आप अगर हमें 10-15 हजार करोड़ रुपया मदद कर दें तो मैं वादा करता हूं कि 40 परसेंट आपके नेशनल और जो जरूरत है उसको बिहार अकेले मीट करेगा क्योंकि थ्री क्रॉप्स ऑफ लैंड कहीं नहीं है लेकिन अगर नहीं तो एक बात मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा प्रधानमंत्री जी जब अगले पांच-दस साल में दस हजार मेगावाट भुगतान और ईस्टर्न इंडिया से आप नार्थ ईस्टर्न इंडिया से बिजली इवैक्योट

करने जा रहे हैं देश के विभिन्न हिस्सों में । साढ़े सात सौ किलोमीटर बिहार को ट्रांसमिशन लाईन जायेगा अगर हमारा खेत सूखा रहा और हमारे लोग अंधेरे में रहें तो मैं लोगों को बताऊंगा ये अपना टावर है, ये भारत सरकार का टावर- अहलूवालिया साहब प्लानिंग कमीशन के वाइस चेयरमैन थे कहा कि इज इट ए नेशनल थ्रेट । मैंने कहा कि अगर आप समझते हैं कि ये नेशनल थ्रेट है बिहार इज ए पार्ट ऑफ दी कंट्री और नॉट । मैंने देखा, मैं आदर के साथ कहना चाहूंगा, मनमोहन सिंह ने उनको इशारा किया, चुप हो गये । खाने के वक्त वो आ गये वॉट इज योर प्रोब्लम मैंने कहा इट विल टेक वन ऑवर । हमने कहा इट विल वेटर मिस्टर चावला इज योर प्राइवेट सेक्रेटरी यू मे टॉक टू हिम । सात-आठ दिन के बाद चावला साहब यहां बैठे हुये हैं इसलिये सामने मैं कह रहा हूं । उन्होंने फोन किया कि सर पूरा एकदम क्लास लिये प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 10-12 हजार करोड़ का भेज दीजिये, आपको इतना पैकेज मिल जायेगा । 12 हजार करोड़ का पैकेज उन्होंने दिया, तीन हजार और । पांच हजार में 1 हजार खर्च हुआ स्टेट हाइवे में जो पांच हजार बचा हुआ था, मुख्यमंत्री जी को स्मरण होगा । कुछ दिन पहले जब वह लैप्स करने की स्थिति में था तो मैंने कहा बिजली विभाग को दे दीजिये, हम खर्चा कर देंगे । पहले इन्होंने बहुत सीरियसली नहीं लिया लेकिन बाद में जब पता किया तो हुआ कि सम्पूर्ण सिस्टम वगैरह कम्पलीट है, बन चुका है सारा इस्टीमेट वगैरह फिर उन्होंने दिया । तो कहने का मतलब मनमोहन सिंह को भुलाया नहीं जा सकता । दूसरी एक घटना और शिंदे साहब आये, विजय बाबू यहां बैठे हुये हैं एयरपोर्ट पर हमलोग रिसिव करने गये । मुख्यमंत्री जी के यहां खाने का इंतजाम भी था और मीटिंग भी हुई । आते ही उन्होंने मुख्यमंत्री जी को कहा हम मीटिंग नहीं, ये हमसे झगड़ा करते हैं, आइये बैठके हमलोग चाय वगैरह- 2 हजार मेगावाट नवीनगर में, 1320 मेगावाट का बाढ़ में, 250-250 मेगावाट के 2 यूनिट बरौनी में, 200-200 के दो यूनिट मुजफ्फरपुर में और 110-110 दो यूनिट मुजफ्फरपुर, बरौनी का रेनोवेशन । बिहार के बंटवारे के बाद केवल 420 मेगावाट ही बिहार को हिस्सा मिला था । लेकिन 2018-19 में जब ये बातें मेरे दिमाग में आयी कि कोयला भारत सरकार का, रेल भारत सरकार का, हम बिजली केवल लेते हैं तो क्यों नहीं भारत सरकार को सुपुर्द कर दें । जो लोग आज प्रश्न उठाते हैं कि बिहार को अपनी बिजली नहीं है तो देश अपना है कि दूसरे का देश है । हम बंगाल से बिजली लेते हैं, अमेरिका से बिजली लेते हैं । एन0टी0पी0सी0 पूरा नेशनल कंपनी है कि केवल एक भारत सरकार की कंपनी है और पैसा राज्य का हो कि देश का हो, सारे देश का पैसा एक जगह इकट्ठा होता है, राज्यों को भी जाता है, केन्द्र को

भी जाता है, क्या-क्या बकवास हो रहा है इसलिये मैंने इसका जिक्र कर दिया महोदय और मैं कुछ बातों को रखना चाहता हूं । महोदय, बहुत सारी चर्चायें होती हैं बिजली के क्षेत्र में हुये विकास को मापने का एक पैमाना है, नाइट टाइम लाईट में वृद्धि है । भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान प्रतिष्ठान इसरो ने नेशनल रिमोट सेंससिंग सेंटर द्वारा सेटेलाईट के माध्यम से पूरे देश में नाइट टाइम लाईट में हुये परिवर्तन का अध्ययन किया गया । नवम्बर, 2022 में उनके द्वारा एक एटलस जारी किया गया है जिसमें वर्ष 2012 से वर्ष 2021 के बीच 10 वर्षों के अंतराल में नाइट टाइम लाईट में हुये परिवर्तन को दर्शाया गया है । इसके अनुसार बिहार में नाइट टाइम लाईट में 474 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी है जो देश में सर्वाधिक है, जबकि राष्ट्रीय औसत केवल 43 प्रतिशत है । इसके लिये मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को आभार प्रकट करता हूं कि पैसे की किल्लत इस विभाग को कभी इनकी कृपा से नहीं हुई, इनकी कृपा से ही यह हासिल हुआ ।

महोदय, दूसरी बात बिजली के विषय में चर्चा होती है कि महंगी बिजली, अब मैं जिक्र कर रहा हूं । बिहार राज्य द्वारा क्रय की गयी बिजली की दर पड़ोसी राज्यों झारखण्ड, पश्चिम बंगाल एवं उत्तर प्रदेश की तुलना में महंगी है । प्राप्त आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2021-22 में बिजली क्रय की दर पश्चिम बंगाल के लिये रु0 3.41 (तीन रुपया इकतालिस पैसा) प्रति यूनिट, झारखंड के लिये रु0 3. 87 (तीन रुपया सतासी पैसा) प्रति यूनिट तथा उत्तर प्रदेश के लिये रु0 4.97 (चार रुपया सन्तानबे पैसा) प्रति यूनिट है जबकि बिहार का बिजली क्रय दर रु0 5.24 (पांच रुपया चौबीस पैसा) प्रति यूनिट है । पूरे देश में इसलिये मुख्यमंत्री जी भी इसको कई बार कहें, हम तो हर मीटिंग में उठाते हैं वन नेशन वन टैरिफ । जब वन नेशन वन टैक्स हो सकता है तो वन नेशन वन टैरिफ क्यों नहीं हो सकता है । लेकिन आज तक इस पर ध्यान नहीं दिया गया ।

महोदय, राज्य में उपभोक्ताओं की संख्या बढ़कर 1 करोड़ 90 लाख हो गयी है जिसमें घरेलू उपभोक्ताओं की संख्या 90 प्रतिशत है । घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं में 42 प्रतिशत ग्रामीण घरेलू, 32 प्रतिशत कुटीर ज्योति तथा शेष शहरी घरेलू हैं । महंगे दर पर विद्युत क्रय के बाद भी राज्य सरकार अपने उपभोक्ताओं को, विशेषतः ग्रामीण घरेलू एवं कुटीर ज्योति श्रेणी के उपभोक्ताओं को किफायती दर पर बिजली उपलब्ध करा रही है । इसके लिये राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के अंतर्गत वितरण कंपनियों को अनुदान दिया जा रहा है । वर्तमान में उपभोक्ताओं को पड़ोसी राज्यों, पश्चिम बंगाल एवं उत्तर प्रदेश की तुलना में सस्ती बिजली की आपूर्ति की जा रही है । वर्तमान वर्ष 2022-23 के

लिये लागू टैरिफ के अनुसार कुटीर ज्योति उपभोक्ताओं का टैरिफ उत्तर प्रदेश में रु0 3.00 (तीन रुपये) प्रति यूनिट एवं पश्चिम बंगाल में रु0 3.79 (तीन रुपया उन्यासी पैसा) प्रति यूनिट है, जबकि बिहार में उन्हें मात्र रु0 2.12 (दो रुपया बारह पैसा) प्रति यूनिट की दर से बिजली की आपूर्ति की जा रही है । महोदय, इसी प्रकार ग्रामीण घरेलू उपभोक्ताओं के लिये पश्चिम बंगाल में बिजली आपूर्ति की दर रु0 3. 35 (तीन रुपया पैंतीस पैसा) से लेकर रु0 5.50 (पांच रुपया पचास पैसा) से लेकर रु0 8.99 (आठ रुपया निन्यानबे पैसा) प्रति यूनिट है, जबकि बिहार में यह दर मात्र रु0 2.60 (दो रुपया साठ पैसा) से लेकर रु0 3.15 (तीन रुपया पन्द्रह पैसा) प्रति यूनिट है । विगत चार वर्षों में आयोग द्वारा टैरिफ कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है । महोदय, इसके अतिरिक्त राज्य सरकार अनुदान देकर दी जा रही है सस्ती बिजली । वर्ष 2021-22 में उपभोक्ता अनुदान की राशि 6578 करोड़ (छः हजार पांच सौ अठत्तर करोड़) रुपया थी जो वर्तमान वर्ष 2022-23 में बढ़ाकर 7801 करोड़ (सात हजार आठ सौ एक करोड़) रुपया कर दी गयी । इतना सात-आठ हजार करोड़ के करीब अनुदान मुख्यमंत्री के द्वारा दिया जा रहा है उपभोक्तओं को फिर भी लोग कह रहे हैं कि बिजली का दर घटाइये तो कहां से पैसा आयेगा । भारत सरकार अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देता तो निश्चित उसे वन नेशन वैन टैरिफ किया जाय तो आप माननीय सदस्य जो कह रहे हैं और भी सस्ती बिजली हमलोग देंगे मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में । किसानों के लिये महोदय राज्य सरकार द्वारा दी गयी उपभोक्ता अनुदान में कृषि उपभोक्ताओं को अतिरिक्त अनुदान देते हुये सस्ती बिजली उपलब्ध करायी जा रही है । वर्तमान वर्ष 2022-23 में कृषि उपभोक्ताओं के लिये बिजली की दर मात्र 70 पैसे प्रति यूनिट है किसानों के लिये। कृषि कार्य में सिंचाई हेतु डीजल चालित पम्प की जगह सस्ती बिजली चालित पम्म सेट के उपयोग से फसल के लागत मूल्य में कमी आयी है । जिसका सीधा लाभ किसानों को हो रहा है । राज्य सरकार द्वारा किसानों को विगत वर्ष 2021-22 में 934.74 (नौ सौ चौंतीस करोड़ चौहत्तर लाख) रुपये अनुदान दी गयी जिसे वर्तमान वर्ष 2022-23 में बढ़ाकर 1,003 करोड़ (एक हजार तीन करोड़) रुपये का अनुदान दिया गया है ।

विकसित बिहार के सात निश्चय-2 में शामिल ''हर खेत तक सिंचाई का पानी'' को पूरा करने हेतु सरकार द्वारा सभी इच्छुक किसानों को निःशुल्क कृषि विद्युत संबंध दिया जायेगा । आकलन के अनुसार आगामी चार वर्षों में लगभग 4.80 (चार लाख अस्सी हजार) कृषि विद्युत संबंध देने का अनुमान है । चतुर्थ कृषि रोड मैप में भी इसका प्रावधान किया गया है ।

महोदय, राज्य में कृषि कार्य हेतु विद्युत संरचना का निर्माण व्यापक रूप से किया गया है । दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना तथा मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना अन्तर्गत अब ये नाम केवल बदले गये हैं, मनमोहन सिंह के समय से ही यह शुरू हो गया था ।

वर्तमान में वितरण कंपनियों के परिचालन क्षमता एवं वित्तीय स्थिरता में सुधार हेतु केन्द्र सरकार द्वारा पुर्नोत्थान वितरण क्षेत्र योजना लागू की गयी है । इसके तहत 13 हजार करोड़ की योजना तैयार की गयी है और इसको लागू किया जाय । कुछ माननीय सदस्य ने कहा मेरे यहां सब स्टेशन नहीं है, तार जर्जर है, कुछ कठिनाइयां होती है उसमें सभी चीज को अपग्रेड किया जायेगा । इस योजना में अन्य कार्यों के अतिरिक्त कृषि कार्य हेतु डेडिकेटेड फीडर भी किया जायेगा । सरकारी भवन पर जल-जीवन-हरियाली अभियान के तहत राज्य में सौर ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु राज्य सरकार द्वारा सभी सरकारी भवनों के छतों पर ग्रिड कनेक्टेड रूफ टॉप सोलर पावर प्लांट लगाया जा रहा है ।

(क्रमशः)

टर्न-27/राहुल/17.03.2023

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री (क्रमशः) : अब तक विभिन्न सरकारी भवनों पर 20 मेगावाट क्षमता का ग्रिड कनेक्टेड रूफ टॉप सोलर पावर प्लांट का अधिष्ठापन किया जा चुका है । महोदय, आगामी दो वर्षों में लगभग 9000 सरकारी भवनों पर कुल 65 मेगावाट क्षमता का ग्रिड कनेक्टेड रूफ टॉप सोलर पावर प्लांट लगाया जाना है जिसमें 3000 सरकारी भवनों पर 23 मेगावाट क्षमता के लिए कार्यादेश निर्गत किया जा चुका है । महोदय, कजरा एवं पीरपैंती में सोलर पावर प्लांट लगाया जायेगा उसकी कार्रवाई चल रही है जल्दी ही उसका काम प्रारम्भ हो जायेगा । महोदय, इसके अतिरिक्त शहरी विद्युत उपभोक्ताओं को स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का कार्य M/s EESL के माध्यम से किया जा रहा है । महोदय, बिहार देश का श्री नीतीश जी के नेतृत्व में, पहला राज्य है जहां स्मार्ट मीटर का अधिष्ठापन प्रीपेड मोड से आरंभ किया गया है । आज देश उसकी नकल कर रहा है, भारत सरकार इसको सभी राज्यों में, प्रधानमंत्री जी ने इसकी जय जयकार करते हुए कहा कि बिहार मॉडल को पूरे देश में लागू किया जाय जो कि तीन-चार लाख करोड़ रुपया ड्यू है विभिन्न कंपनियों पर । शहरी क्षेत्र में उत्साहवर्द्धक परिणाम प्राप्त होने के उपरांत राज्य सरकार द्वारा राज्य के शेष बिजली उपभोक्ताओं के लिए भी स्मार्ट प्रीपेड मीटर उपलब्ध कराने का निर्णय

लिया गया है । तद्नुसार अक्टूबर, 2022 में 1.48 करोड़ उपभोक्ताओं को स्मार्ट प्रीपेड मीटर उपलब्ध कराने हेतु 15074 करोड़ रुपये की योजना की स्वीकृति दी गयी । प्रारम्भ में 36 लाख स्मार्ट प्रीपेड मीटर के अधिष्ठापन का कार्य प्रगति पर है । शेष 112 लाख स्मार्ट प्रीपेड मीटर के अधिष्ठापन हेतु निविदा प्रक्रियाधीन है । अब तक बिहार में 13 लाख से अधिक स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाये जा चुके हैं जो देश में सर्वाधिक है । स्मार्ट प्रीपेड मीटर के उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए मोबाईल ऐप बनाया गया है जिसके माध्यम से उपभोक्ता बैलेंस राशि की जानकारी, विद्युत उपभोग की नियमित जानकारी, मासिक विद्युत विपत्र, इत्यादि प्राप्त कर सकते हैं । इस ऐप के माध्यम से उपभोक्ता राशि के भुगतान के साथ-साथ स्मार्ट मीटर संबंधी शिकायत भी दर्ज कर सकते हैं । महोदय, कुछ माननीय सदस्यों ने कुछ चर्चायें की, निश्चित तौर से कोई नई योजना होती है तो प्रारम्भिक चरण में कुछ लोगों को समझने में भी कठिनाई आती है, उसको ठीक से इंप्लीमेंट करने में भी, ठीक से उसका उपयोग करने में भी दिक्कतें होती हैं यह स्वभाविक क्रिया है लेकिन सारी व्यवस्था की गई है उसके सुधार के लिए और ऐप के माध्यम से जो शिकायतें मिलती हैं उसको दूर भी किया जाता है। महोदय, जो वस्तुस्थिति है वर्ष 2012 में ग्रिड उपकेन्दों की संख्या थी 83 और आज वर्ष 2022-23 में हो गयी है 161, संचरण लाईन की कुल लंबाई थी 6872 किलोमीटर अब हो गयी है 18812 किलोमीटर, विद्युत निकासी की क्षमता 132 के0वी0 मेगावाट 2000 थी और अब हो गयी है 13000, अधिकतम मांग की आपूर्ति (Peak Demand Met) 1802 और आज 6738 मेगावाट पिछले साल हुई अब इस बार संभावना है कि साढ़े सात-आठ हजार मेगावाट चली जायेगी । शक्ति उपकेन्द्रों की संख्या 545 थी अब हो गयी है 1231, उपभोक्ताओं की संख्या (लाख में) 38 थी अब हो गयी है 190, विद्युतीकृत राजस्व गांवों की संख्या 33850 थी अब 39073 है, प्रीपेड स्मार्ट मीटर का अधिष्ठापन अब है 13 लाख । महोदय, ऊर्जा विभाग का कुल बजट जो मैंने पढ़ा । महोदय, एक बात और भी मैं कहना चाहता हूं कि यह लगातार प्रक्रिया है कुछ शिकायत स्वभाविक हैं माननीय सदस्यों से मैं अपील करूंगा कि कुछ छोटी-मोटी शिकायतें अगर हों आप भी निश्चित तौर से लेकिन एक चीज मैं कहना चाहूंगा इसको बाद में कहूंगा, एक बूढ़ी महिला मेरे पास आई और कहा कि हम दो ही बल्ब जलाते हैं मेरा 2 हजार रुपये बिल आ गया । रात के 7 बजे मैं गाड़ी लेकर चला गया और वह बूढ़ी जब देखी तो भाग गयी । उसके यहां पांच पंखे, 2 फ्रीज और 8-10 बल्ब जल रहे थे इसकी भी जांच कीजिये।

खाली कहने से नहीं जाकर देख लीजिये और माननीय सदस्य लिखिये निश्चित रूप से उसको दूर किया जायेगा । महोदय, दूसरी बात एक माननीय सदस्य ने कहा Complaint के लिए तो आज मैं घोषणा करता हूं कि प्रत्येक माह के द्वितीय शनिवार को प्रखंड स्तर पर एक कैंप का आयोजन किया जायेगा जिसमें शिकायतों पर सुनवाई की जायेगी लेकिन शिकायत सही हो । साथ ही, बिहार पहला राज्य है जहां माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा शिकायत निवारण कानून बनाया गया है तो आप वहां जाकर भी शिकायत कर सकते हैं वहां अफसर को भी बुलावेंगे, आपको भी बुलावेंगे और वहां मामला निपटा जायेगा । इसीलिए यह लगातार की पक्रिया है । कुछ जगह लोग कह रहे हैं कि घर में बिजली नहीं है, तो नये घर भी बन रहे हैं लेकिन नये घर में जब तक पिटिशन नहीं देगा, घर पर से तार गुजरने की एक शिकायत हुई थी, जब तार लग गया, बिजली चली गयी तब नीचे में लोग घर बनाये यह कैसे संभव हो पायेगा । इसीलिए इन सब बातों का ख्याल रखना चाहिए । माननीय सदस्य कह रहे थे फ्री बिजली, फ्री बिजली चलने वाली नहीं है । जो भी राज्य फ्री कर रहा है उसका ड्यूज देखिये कितना ड्यूज है । जैसा मैंने कहा 3 लाख उससे ज्यादा है कुछ दिनों में बिजली कट जायेगी कहां से बिजली खरीदी जायेगी ? बिजली खरीदी जाती है, फिर सप्लाई की जाती है । सरकार जो 7-8 हजार करोड़ सब्सिडी देती है इससे ज्यादा सस्ती बिजली क्या होगी । इसीलिए आप सभी लोगों से मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि सच्चाई को स्वीकार्य और सच के साथ हम आगे बढ़ें और आगे जो समस्या आयेगी उसका मिनट टू मिनट निश्चित रूप से निराकरण किया जायेगा । अगर कोई ज्यादा कठिनाई होगी तो आप मुझसे भी बात कीजिये, लिखकर भी दीजिये उसकी जांच करायी जायेगी । महोदय, इसी के साथ मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कटौती प्रस्ताव चले गये वे लोग, वे अपना कटौती प्रस्ताव वापस लें और इस मांग को पारित करनें की कृपा करें । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

अध्यक्ष : क्या माननीय सदस्य, श्री संजय सरावगी अपना कटौती प्रस्ताव वापस लेना चाहते हैं ?

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''इस शीर्षक की मांग 10/- रुपये से घटाई जाय ।''

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

अब मैं मूल प्रस्ताव को लेता हूं ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''ऊर्जा विभाग के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए 115,36,83,67,000/- (एक सौ पन्द्रह अरब छत्तीस करोड़ तिरासी लाख सड़सठ हजार) रुपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

मांग स्वीकृत हुई ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आज दिनांक-17 मार्च, 2023 के लिये स्वीकृत निवेदनों की कुल संख्या-52 है, अगर सदन की सहमति हो तो इन्हें संबंधित विभाग को भेज दिया जाय ।

(सदन की सहमति हुई)

अब सभा की बैठक सोमवार, दिनांक-20 मार्च, 2023 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक के लिये स्थगित की जाती है ।